एक्स से

हमें और अधिक मजबूत व प्रभावशाली संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है, जो लोगों की ज्यादा सेवा कर सके और 21वीं सदी की अपेक्षाओं के अनुरूप हो - एंटोनियो गुटेरस/ संयुक्त राष्ट्र महासचिव

हर पर्व पर रक्त आकांक्षा

एक खतरनाक प्रवृत्ति तेजी से पनपी है। धार्मिक शोभा-यात्राएं अब शक्ति-प्रदर्शन का जरिया बन चली हैं। समूची दुनिया में जब सांप्रदायिक उन्माद पनप चला हो, तब भारत पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए मिसाल बन सकता था, लेकिन इसका उलटा हो रहा है। होली, दिवाली, ईद या बकरीद से बात काफी आगे बढ़ गई है।

स्कैन करें
आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

शशि शेखर

आजकल

होली के दिन रंग और उल्लास के बीच मेरा मन डोल रहा था। पिछला पखवाड़ा अपशकुनी संदेशों से बजबजाता बीता था। दो राज्यों में तो देश के दो सबसे बड़े समुदाय भिड़ भी चुके थे। होली परंपरागत तौर पर प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। यह त्योहार हम हिन्दुस्तानियों की बीती ताहि बिसारकर आगे की राह पकड़ लेने की रीति-नीति का जीवंत उदाहरण भी है।

क्या अब यह एहसास स्वर्णिम अतीत का हिस्सा बनने जा रहा है?

इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको पत्रकारिता के अपने शुरुआती दिनों में गोते लगाने के लिए आमंत्रित करता हूं। 1980 की दहाई के शुरुआती बरसों की मुझे वाराणसी और इलाहाबाद (माफ कीजिएगा, प्रयागराज) की वे बैठकें याद हैं, जो हर खास त्योहार से पहले कोतवाली में आयोजित की जाती थीं। इनको अमन कमेटी की बैठक कहा जाता था। जिले के आला अफसरों के साथ तमाम पुजारी, संत, मठाधीश, मौलवी, मुफ्ती, मौलाना और अन्य 'संभ्रांत' लोग इनमें हिस्सा लेते। घंटों की बातचीत के बाद हर साल यही निष्कर्ष निकलता कि सभी समुदाय मिल-जुलकर त्योहार मनाएंगे। इस दौरान आला अधिकारी चाशनी पगे शब्दों में धमकी देना न भूलते कि कानून हाथ में लेने की जरा सी कोशिश भी महंगी पड़ेगी।

होली पुलिस वालों के लिए अन्य त्योहारों के मुकाबले अधिक कठिनाई लेकर आती। इस वर्ष की भांति पहले भी जब होली जुमे के दिन होती, तो उनकी जान सांसत में पड़ जाती। उस वक्त दोनों समुदायों की संवेदनाओं को आसानी से भड़काया जा सकता था। उत्तर भारत के कुछ शहर ऐसे थे, जहां त्योहारों के आस-पास प्रायः हर साल दंगे भड़क उठते। दंगों के दौरान दोनों धर्मों के कुछ कट्टरपंथी अपने संगी-साथियों पर दबाव बनाते कि भविष्य में 'उन लोगों' से कोई कार्य-व्यापार नहीं रखना है। यह कटुता कुछ दिनों में हवा में कपूर की भांति विलीन हो जाती। लड़खड़ाने और हर लड़खड़ाहट के बाद सम्हलकर आगे चल पड़ने में हम भारतीयों को महारत हासिल है।

क्या इस इस्पाती एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है?

'सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी ऐंड सेक्यूलरिज्म' (सीएसएसएस) के मुताबिक, साल 2024 में सांप्रदायिक दंगे की 59 घटनाएं घटीं, जबकि 2023 में ऐसी दुखद घटनाओं की संख्या 32 थी। महज एक साल में 84 फीसदी का इजाफा! चौंकाने वाला यह मनहूस आंकड़ा डराता भी है। इन घटनाओं में 13 लागों को जान गंवानी पड़ी और सैकड़ों घायल हो गए। इनमें से ज्यादातर दंगे धार्मिक उत्सवों के समय हुए।

संगठन की रिपोर्ट आगे बताती है, इनमें से चार सांप्रदायिक झड़पें रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के समय, सात सरस्वती पूजा में मूर्ति विसर्जन के वक्त, चार गणेश उत्सव के दौरान और दो बकरीद के समय हुईं। इसी संगठन ने पिछले साल भीड़ हिंसा की 13 घटनाओं में 11 लोगों की मौत के आंकड़े प्रकाशित किए थे, जिनमें मुस्लिम, हिंदू और ईसाई, हर धर्म के लोग शिकार बने थे। क्या आपको अब भी नहीं लगता कि यह समय साझा सकारात्मक सोच विकसित करने का है?

ऐसा कहने की एक और वजह भी है। इस दौरान एक खतरनाक प्रवृत्ति तेजी से पनपी है। धार्मिक शोभा-यात्राएं अब शक्ति-प्रदर्शन का जरिया बन चली हैं। समूची दुनिया में जब सांप्रदायिक उन्माद पनप चला हो, तब भारत पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए मिसाल बन सकता था, लेकिन इसका उलटा हो रहा है। होली, दिवाली, ईद या बकरीद से बात काफी आगे बढ़ गई है। पिछले दिनों इजरायल पर आतंकी हमले के बाद उसकी जवाबी कार्रवाई पर हमारे देश में भी कटु कुतर्कों से भरपूर बहस चल पड़ी थी। महीनों तक 'इनके' या 'उनके' खिलाफ अनर्गल प्रलाप माहौल में जहर घोलता रहा। लंबे समय से षड्यंत्रपूर्वक रोपी जा रही इस नफरती फसल का

असर बहुत से भारतीयों की मानसिकता पर पड़ा है।

पिछले दिनों एक पुलिस अफसर का बयान वायरल हुआ। वह कह रहे थे कि होली साल में सिर्फ एक बार आती है, जबकि जुमे 52 दिन। जिसे रंगों से तकलीफ है, वह उस दिन अपने घर से न निकले। हो सकता है, उनके बयान को तोड़ा-मरोड़ा गया हो। यह भी संभव है कि अर्थ का अनर्थ करने की कोशिश की गई हो, पर इसमें कोई दोराय नहीं कि पुलिस का काम है, वह रंगों की बारिश के बीच भी रोजे, जुमे की नमाज और अन्य धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों को सुचारू रखे। इस उधेड़-बुन से उबरा नहीं था कि एक और सोशल मीडिया पोस्ट ने मुझे चौंकने को मजबूर कर दिया। वह सड़क किनारे खड़े एक कियोस्क का फोटो था, जिसमें अपील दर्ज थी- ईद पर उन्हीं लोगों से सामान खरीदें, जिनके घर उस पैसे से ईद मनाई जा सके। इशारा साफ है। क्या इसे दर्ज कराने वाला नहीं जानता कि यह हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है? कियोस्क लगाने के लिए सरकारी विभागों से बाकायदा अनुमति ली जाती है। क्या इसके लिए इजाजत ली गई थी? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति किस अधिकारी ने दी? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई?

ध्यान रहे, सामाजिक समरसता हमारी रगों में बहती है। अब से 75 वर्ष पूर्व 12 मार्च, 1950 को दैनिक *हिन्दुस्तान* में छपे इस अग्रलेख पर एक नजर डालने का कष्ट करें- 'हमारे हर्ष और उल्लास का सबसे बड़ा त्योहार होलिकोत्सव इस वर्ष ऐसे दिनों में आया, जब पूर्वी बंगाल के अभागे अल्पसंख्यकों के साथ किए गए जघन्य अत्याचारों की रक्तरंजित गाथाएं भारत के कोने-कोने में अपनी पूर्ण कर्कशता के साथ गूंज रही थीं। ऐसे विषाक्त वातावरण में होली का निर्विघ्न व्यतीत हो जाना एक ऐसी घटना है, जिसके लिए भारत की जनता और उसके कर्णधार सराहना के अधिकारी हैं। संतोष का विषय है कि पाकिस्तान की ओर से निरंतर उत्तेजित किए जाने पर हमारे देशवासी आज अद्वितीय सहनशीलता से काम ले रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण होली जैसे हुड़दंग वाले त्योहार पर कहीं भी कोई बड़ी दुर्घटना का न होना है।'

स्पष्ट है, विभाजन की भीषण दाहकता में दहकने के बावजूद हम भटके नहीं थे। फिलवक्त ऐसी विचारधारा को फिर से बल देने की जरूरत है।

यहां एक और तथ्य काबिले-गौर है। विश्व के प्रमुख इस्लामी देशों के साथ दिनोंदिन हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वहां हिंदू मंदिरों की इजाजत मिल रही है, पिछले वर्ष फरवरी में अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के पहले मंदिर का उद्घाटन किया था। शायद आपको याद हो, एक बार नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में वह भाषण दे रहे थे। इसी बीच किसी मस्जिद से अजान की आवाज आने लगी। उसके सम्मान में मोदी ने भाषण रोक दिया और तब तक शांत खड़े रहे, जब तक अजान पूरी नहीं हो गई। इससे पूर्व तथाकथित गौरक्षकों को भी उन्होंने सार्वजनिक चेतावनी दी थी। इसके बाद सख्ती बढ़ी और 'मॉब लिंचिंग' पर अंकुश भी लगा।

इसके बावजूद देश के भीतर सांस्कृतिक विलगाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है। हमें इस कुप्रवृत्ति से मिलकर वैसे ही निपटना होगा, जैसे विभाजन के बाद निपटे थे।

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

जीना इसी का नाम है

जुमदे योमगाम गामलिन
समाजसेवी

दिहाड़ी मजदूर से नशा-मुक्ति योद्धा बनने का सफर

एक मां ही नशे के जाल में फंसे किशोरों की तड़प को समझ सकती थी... फिर एक सरहदी सूबे की नौजवान नस्ल यदि नशे की गिरफ्त में हो, तो यह देश के लिए खतरे की बात है। मगर सलाम है जुमदे जैसी माओं को, जो मानवता के साथ-साथ देश की अनमोल सेवा कर रही हैं!

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने आज से 120 साल पहले लिखा था, *जदि तोर डाक शुने केउ ना आसे/ तबे एकला चलो रे।* (अगर कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनता, तो अकेले ही आगे बढ़ो) गुरुदेव के दशकों बाद मजरूह सुल्तानपुरी ने एक शेर कहा, *मैं अकेला ही चला था जानिब-ए-मंजिल मगर/ लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।* पता नहीं, इन दोनों कालजयी रचनाकारों के साहित्य को जुमदे योमगाम गामलिन ने पढ़ा है या नहीं, पर उनकी कार-कर्दगी इन दोनों के फलसफे की जिंदा इबारत है। नशाखोरी के जाल में फंसे नौजवानों की निःस्वार्थ सेवाओं के लिए भारत सरकार ने हाल ही में उन्हें 'पद्मश्री' से नवाजा है।

चीन की सरहद से लगे दक्षिण सियांग जिले (अरुणाचल) में एक छोटा सा गांव है अक्कर योमगाम। इसी गांव के बेहद गरीब परिवार में आज से साठ साल पहले जुमदे पैदा हुईं। बहुत छोटी थीं, तभी पिता (ताजुम योमगाम) का साया सिर से उठ गया। अकेली मां (याकी योमगाम) के कंधे पर तीन-तीन नन्ही बेटियों की परवरिश का भार आ गया था। जुमदे सबसे बड़ी संतान थीं लिहाजा किशोरावस्था में ही दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ी। रोज के दो रुपये मिला करते, जिससे वह अपनी पढ़ाई के अलावा छोटी बहनों की जरूरतें पूरी करतीं। मगर हर रोज काम नहीं मिलता था। ऐसे में, नौवीं कक्षा के बाद जुमदे को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मगर बड़ा सहारा हुआ, जब कुछ ही दिनों बाद 1980 में उन्हें इसी शिक्षा के आधार पर अरुणाचल सरकार के ग्रामीण विकास विभाग (अब महिला एवं बाल विकास विभाग) में ग्रामसेविका की नौकरी मिल गई।

जुमदे की मानो सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई थी, वह बहुत खुश थीं, मगर वह यह भी जानती थीं कि विभागीय तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी बुनियादी डिग्रियां बहुत जरूरी हैं। इसलिए उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया। असम बोर्ड से प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में मैट्रिक की परीक्षा पास करके वह सांध्य कॉलेज से प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स की डिग्री हासिल करने में भी कामयाब रहीं। काम के प्रति जुमदे की प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्हें समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) विभाग में नई जिम्मेदारी मिली। इस भूमिका में उन्हें गांव-गांव घूमकर महिलाओं के सशक्तीकरण और बच्चों के पोषण से जुड़े काम करने थे। जुमदे को मनचाहा काम मिल गया था। स्त्रियों के आत्मनिर्भर बनने की अहमियत को उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था?

उन्होंने स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित कर अनेक महिलाओं के लिए उनके जरिये अपनी आजीविका कमाने का रास्ता बनाया। जुमदे औरतों से कहतीं कि उन्हें जिस भी काम में महारत हासिल है, उससे ही वे पैसे कमा सकती हैं। उन्होंने उन्हें पेंसिल व मोमबत्ती बनाकर या सिलाई-कढ़ाई के काम के

जरिये आत्मनिर्भर बनने को प्रोत्साहित किया। जन-सहायता के इन कामों में वह इस कदर रम गई थीं कि उन्हें पता ही नहीं चला, उनका बेटा कब नशे की लत का शिकार बन गया? उसके व्यवहार में आए बदलाव को जब जुमदे ने नोटिस किया, तब जाकर उन्हें इस बारे में मालूम चला। उस समय तक वह इसके दुष्प्रभावों के बारे में बहुत कुछ जानती भी नहीं थीं।

दरअसल, उस पूरे इलाके में अफीम की खेती हुआ करती थी। इसलिए इसका सेवन वहां सामान्य बात थी। मगर यदा-कदा पीने और लती होने के फर्क के प्रति वह अब जागरूक थीं। अपने बेटे की हालत वह किसी को बता भी नहीं सकती थीं, मगर नशे के लिए उसकी बेचैनी और तड़प उन्हें तोड़ देती। आखिरकार एक बेबस मां की तरह रोने के बजाय जुमदे ने इस स्थिति से लड़ने का फैसला किया। अपने बेटे के इलाज के साथ-साथ उन्होंने इलाके के तमाम नौनिहालों को नशा मुक्त माहौल देने का प्रण ले लिया। वह साल 2011 था। जुमदे तब अपर सियांग के गेकू सर्किल में सीडीपीओ के पद पर तैनात थीं। अपने इलाके में उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ स्थानीय समाज को शिक्षित करने की मुहिम छेड़ दी। शुरू-शुरू में लोगों ने बहुत हतोत्साहित किया। कोई तंज करता कि अपने बेटे को तो संभाल न पाईं, दुनिया सुधारने चली हैं! कोई इन सबमें उलझने के बजाय कुछ और करने, स्कूल खोलने की सलाह देता।

मगर एक मां ही नशे के जाल में फंसे किशोरों की तड़प को समझ सकती थी। जुमदे ने स्व-सहायता समूहों और महिलाओं को ड्रग्स (अफीम की खेती) के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। संयोग से उन दिनों एक युवा ऊर्जावान आईएएस परवेज तारिक डीसी बनकर वहां आए थे। जुमदे उनसे मिलीं और इस गंभीर समस्या को उनके सामने रखा। डीसी फौरन उनके साथ खड़े हो गए। उनकी मदद से अफीम की खेती बंद कराई गई व गांव-गांव में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान छेड़ा गया। समान सोच वाली नौ महिलाओं के साथ जुमदे ने आलो शहर में 2014 में 'मदर्स विजन' नाम से एक संस्था की शुरुआत की। इन सबका कोई अपना ड्रग्स के जाल में फंसा था। फिर कई लोग जुड़े। कुछ वर्षों बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर जुमदे पूर्णतः इस सेवा में निःस्वार्थ भाव से जुट गईं।

ड्रग्स के लती लोगों को उससे छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने एक 'रिहैब सेंटर' चलाना शुरू किया। इससे पूरी तरह ठीक होकर निकले कई लड़के न सिर्फ समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए, बल्कि कई सरकारी नौकरियों में आ गए, तो

अपने इलाके में उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ स्थानीय समाज को शिक्षित करने की मुहिम छेड़ दी। शुरू में लोगों ने बहुत हतोत्साहित किया। कोई तंज करता कि अपने बेटे को तो संभाल न पाईं, दुनिया सुधारने चली हैं! कोई इन सबमें उलझने के बजाय कुछ और करने की सलाह देता।

कई दूसरे युवा दीगर रिहैब सेंटर में पीड़ितों की मदद कर रहे हैं।

जुमदे की वह एक पहल देखते-देखते समूचे अरुणाचल के सैकड़ों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। पिछले एक दशक में 700 से भी अधिक युवा यहां से ठीक होकर अपने-अपने परिवार में लौट चुके हैं। एक सरहदी सूबे की नौजवान नस्ल यदि नशे की गिरफ्त में हो, तो यह देश के लिए खतरे की बात है। मगर सलाम है जुमदे जैसी माओं को, जो मानवता के साथ-साथ देश की अनमोल सेवा कर रही हैं!

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा

जुर्गिस बिलिनिस
किताब तस्करों के राजा

किताबों की तस्करी का बेताज बादशाह

हाथ या जेब जब खाली हो, तो आसपास मुसीबतें मंडराने लगती हैं। शीत ऋतु की बर्फीली रात थी, वह एक जगह लाचार-परेशान दुबककर बैठे थे। उन्हें पता था कि जेब में धन न हो, तो ठंड भी जानलेवा हो जाती है। एक ही चिंता थी, कैसे कमाएं धन? कौन देगा धन?

वक्त की मार ने उन्हें 14 की उम्र में ही अपने घर-परिवार का मालिक बना दिया था और जिम्मेदारियों ने वक्त से पहले वयस्क। हाथ से कलम छूट गई थी और उसकी जगह खुरपी ने ले ली थी। कंधे पर भाई-बहन की भी जिम्मेदारी थी और अक्सर हालात के सामने मजबूर होना पड़ता था। कदम-कदम पर अन्याय होता था, दूसरों के साथ होने वाले अन्याय पर भी खूब गुस्सा आता था, पर कायदे से संघर्ष में परेशानी होती थी। परेशानी की एकमात्र वजह थी, पर्याप्त शिक्षित न होना।

अन्याय के खिलाफ संघर्ष की इच्छा ने ही उस युवा को 22 की उम्र में प्रेरित किया कि वह फिर से पढ़ाई शुरू करे। खैर, तीन साल की पढ़ाई में पांच साल लग गए। चौथे साल की पढ़ाई के लिए वह गांव से शहर काउनास जा रहे थे, पर रास्ते में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। फिर क्या, हाथ या जेब जब खाली हो, तो आसपास मुसीबतें मंडराने लगती हैं। उस युवा के साथ भी ऐसा ही हुआ। लगने लगा कि फिर लौटकर गांव जाना होगा और खेती से फिर धन अर्जित करना होगा। शीत ऋतु की बर्फीली रात थी, वह एक जगह लाचार-परेशान दुबककर बैठे थे। उन्हें पता था कि जेब में धन न हो, तो सिर्फ ठंड ही जानलेवा हो जाती है। एक ही चिंता थी, कैसे कमाएं धन? कौन देगा धन?

शायद युवक की परेशानी को पास बैठे दो राहगीरों ने पहचान लिया। परस्पर परिचय हुआ। युवक ने अपनी राम कहानी सुनाई और कहा कि उसे धन चाहिए, ताकि पढ़ाई पूरी कर सके। अच्छा हो कि उसे जल्दी पैसे कमाने का कोई तरीका मिल जाए।

एक राहगीर ने कहा कि हम जो काम करते हैं, वह तुम भी कर सकते हो। एक के बदले दो-तीन कमा सकते हो। सीमा पार जाना है, वहां से किताबें लेकर इस पार आना है। यहां के लोगों को किताबें बेच देना है। बस, हो गई कमाई।

युवक ने खुशी से कहा था, यह तो अच्छा काम है, मैं करूंगा। काम में जोखिम है, पर जोखिम तो हरेक काम में है।

उसी पल युवक ने धन के लिए यह काम शुरू कर दिया। किसी तरह से सीमा पार करना और वहां से किताबें छिपाकर लिथुआनियाई क्षेत्र में लाकर बेचने का धंधा चल पड़ा। किताबों की तस्करी का पेशा रास आ गया। धीरे-धीरे यह भी आभास हुआ कि यह काम किसी राष्ट्रसेवा से कम नहीं है। मामला यह था कि रूस के राजा ने लिथुआनियाई भाषा, लिपि और उसके किसी भी प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो लोग अपनी लिथुआनियाई भाषा में कुछ पढ़ना चाहते थे, उन्हें तस्करों की मदद से ही किताबें हासिल होती थीं। खैर, बहुत जल्दी ही पढ़ने-लिखने वाले लिथुआनियाई समाज के बीच युवक जुर्गिस बिलिनिस का नाम कानों-कान प्रसिद्ध होने लगा। कई बार मुंहमांगी किताब की मुंहमांगी कीमत मिलती थी और कई बार किसी जरूरतमंद को वह मुफ्त में ही किताबें भेंट कर दिया करते थे। वह किताब तस्करी की नई-नई तरकीबें आजमाते थे। हर बार तस्करी का अंदाज बदल जाता था।

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि बिलिनिस ने किताबों की तस्करी में 32 साल बिताए, पर बमुश्किल छह बार पकड़े गए। पिटाई भी हुई और जेल भी, पर वह जान गए थे कि उनका काम केवल तस्करी नहीं है, वह एक भाषा को विलुप्त होने से बचाने के अभियान में शामिल हैं। इस अभियान की कामयाबी में ही लिथुआनिया देश की आजादी छिपी है।

खैर, एक दिन आया, जब लिथुआनियाई भाषा से प्रतिबंध हटा और बिलिनिस ने अपना काम बंद किया। उसके बाद ही अधिकतर रूसियों और लिथुआनियाइयों को बिलिनिस के बारे में पता चला। लोग जान पाए कि बिलिनिस किताब तस्करी के राजा थे और उन्होंने पुस्तक तस्करों का मजबूत संगठन बनाया था। वह किसी जगह ज्यादा रुकते न थे और रात-रात भर पैदल ही आना-जाना करते थे। पीछे पड़ी पुलिस को चकमा देने में माहिर थे। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा किताबों की तस्करी में लगा दिया और दूसरे देश में लिथुआनियाई साहित्य छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस तक स्थापित किया। समय-समय पर जरूरत देख अखबार भी निकाला। उन्हें एक लोकनायक जैसी प्रतिष्ठा हासिल हुई। उन्हें लिथुआनिया की स्वतंत्रता के विचार की घोषणा करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में पहचाना गया। लोगों ने साफ तौर पर जाना कि पुस्तकों के प्रहार से भी साम्राज्यवाद को पराजित किया जा सकता है। अफसोस, लिथुआनिया की आजादी से महज एक माह पहले जुर्गिस बिलिनिस (1846-1918) संसार छोड़ गए। उनके जन्मदिन 16 मार्च को दुनिया उन्हें याद करती है और इस दिन पुस्तक वाहक दिवस या 'डे ऑफ बुक स्मगलर्स' मनाया जाता है।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

और मेरे साहित्य का डॉन मर गया

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

सोचता ही रह गया कि अब जाऊं कि अब जाऊं, कि जाकर महाकुंभ के अवसर पर संगम में डुबकी लगाऊं और अब तक के अपने सारे साहित्यिक-असाहित्यिक पाप-वाप धोकर आ जाऊं, पुण्य कमाऊं। मैं जितना सोचता, उतना ही डरता। जितना डरता, उतना ही सोचता कि क्या करूं, क्या न करूं? जाऊं कि न जाऊं? जाने से सिर्फ पुण्य मिलेगा, मगर साहित्य तो हाथ से चला जाएगा और फिर डर के मारे खुद से कहने लगता कि रे मन, अच्छी तरह से सोच ले कि तुझे क्या करना है? इतिहास में नाम लिखवाना है या फिर कटवाना है?

एक तरफ, हर वक्त 'पॉलिटिकली करेक्ट' रहने की मेरी बुरी आदत और दूसरी तरफ, महाकुंभ से पुण्य लाभ उठाने का मौका! मगर इन दिनों पॉलिटिकली करेक्ट रहने की लाइन इस कदर तनी हुई रहती है कि जरा सा इधर-उधर हुए कि गए। मेरा डर कहता, जरा सोच, तू महाकुंभ गया, तो तेरे कॉमरेड तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? सेकूलर साथी क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक दोस्त क्या कहेंगे? प्रगतिवादी, जनवादी, जसम वाले साथी क्या सोचेंगे? पुराने-नए हस्ताक्षर वीर क्या कहेंगे?

वे कहेंगे कि देखा, कैसा गद्दार निकला? हम तो पहले से जानते थे कि एक दिन इसका पतन होगा ही, पर यह इतनी जल्दी और इतना गिरेगा, सोचा नहीं था। यह तो एकदम पतनशील निकला और वह दिन दूर नहीं, जब इसे एक कन्फर्म्ड रिएक्शनरी, फासिस्ट, अनडेमोक्रेटिक, निरंकुशतावादी, हिंदुत्ववादी, सनातनवादी, भगवा गेरुआवादी, केसरियावादी, रूढ़िवादी, सांप्रदायिक, कंजर्वेटिव, एंटी प्रोग्रेसिव, वैज्ञानिक दृष्टि का दुश्मन, आजादी का दुश्मन, संविधान का शत्रु और साहित्य का दुश्मन हो जाना है।

मैं सोचता रहता और इतनी सारी गालियों की बौछार एक साथ आते देख सहम जाता, मन ही मन डरता रहता कि ऐसा सोचते हुए मुझे किसी ने भांप तो नहीं लिया? हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहने का अभ्यस्त मेरा मन मुझे डराने लगता कि बेटा, ऐसी गलती कभी न करना। एक बार लाइन के पार गया, तो तू हिंदी साहित्य से तड़ीपार कर दिया जाएगा! इसलिए जो करना, सोच-समझकर करना, नहीं तो जो तूने अपनी मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओत्से तुंगवादी, चे ग्वेरा-फिदेल कास्त्रोवादी, लूकाचवादी, लूनाचास्कीवादी टाइप पहचान बनाई है, वह एक पल में ध्वस्त हो जाएगी। और ऐसे ही सोचते व डरते हुए महाकुंभ निकल गया और मैं बच गया।

लेकिन महाकुंभ गया, तो होली आ गई और मैं फिर दुविधा में था कि होली मनाऊं कि न मनाऊं; होली खेलूं कि न खेलूं? अचानक भान हुआ, साहित्य को डराने वाला तो उसके भीतर ही है। सरकार, राज्य-सत्ता, कानून आदि तो बहुत बाद में आते हैं, पहले आता है साहित्य का अपना माफिया, जो हर साहित्य-कला को अपनी तरह से हांकना चाहता है। अगर तू साहित्य को इस माफिया के डर से आजाद करना चाहता है, तो पहले उसे उसके अंदरूनी डर से आजाद कर। ऐसा डॉन सूरदास, तुलसीदास के जमाने में भी रहा और बिहारी, घनानंद के जमाने में भी। छायावाद के जमाने में भी रहा और प्रगतिवाद के जमाने में तो डॉन ही डॉन रहे, जो आज तक हुंकारते-फुंफकारते रहते हैं।

ऐसा सोचते ही मैं समझ गया कि अगर साहित्य को निडर करना है, तो सबसे पहले इस डरावने डॉन से निपटना होगा। जब तक वह है, तब तक कोई साहित्य हजार आजादी के बाद भी आजाद नहीं! और उसे आजाद करना है, तो डॉन को एकदम गैर-जरूरी बनाकर उसे साहित्य से हंकालना होगा, जिस तरह तुलसीदास ने अपने वक्त के डॉनों को धता बताते हुए कहा था : *धूत कहौ अवधूत कहौ रजपूत कहौ जोलहा कहौ कोउ/ काहू की बेटी सों बेटा न ब्याहब काहू की जाति बिगार न सोउ।*

सच कहूं, इन लाइनों को पढ़ते ही मेरे साहित्य का डॉन मर गया और मैं निडर हो गया। इस तरह अपन ने जमकर खेली होली।

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

कर्म ही मनुष्य को गौरव या पतन की ओर ले जाते हैं

चिंतित करता पंजाब

अमृतसर के एक मंदिर में बम फेंके जाने की घटना गंभीर चिंता का कारण बननी चाहिए, क्योंकि हाल के समय में यह पहली बार है, जब किसी हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया और वह भी होली की रात। इसके पहले कई पुलिस चौकियों और थानों पर इसी तरह बम फेंके गए हैं। चौकियों और थानों के बाद मंदिर को निशाना बनाया जाना आतंकी तत्वों के बढ़ते दुस्साहस को बयान करने के साथ यह भी रेखांकित कर रहा है कि पंजाब के सांप्रदायिक सद्भाव पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की मानें तो मंदिर पर हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ का हाथ है, लेकिन प्रबल आशंका यही है कि बम फेंकने का काम खालिस्तान समर्थक तत्वों ने किया होगा। परिस्थितियां भी यही संकेत कर रही हैं। यह घटना कितनी गंभीर है, इसका पता इससे भी चलता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यह स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य के माहौल को बिगाड़ने की साजिश की जा रही है, लेकिन केवल इतना कहने से काम चलने वाला नहीं है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को राज्य की गिरती कानून एवं व्यवस्था पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा और इस क्रम में खालिस्तान समर्थक तत्वों के विरुद्ध कठोरता का परिचय देना होगा।

अतीत में पंजाब को आतंकवाद की आग में झोंकने वाले खालिस्तान समर्थक तत्व किसी नरमी के हकदार नहीं। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें हर तरह का सहयोग और समर्थन देने में लगा हुआ है। इसका प्रमाण पाकिस्तान से हथियारों और नशीले पदार्थों की बढ़ती तस्करी से मिलता है। पंजाब और साथ ही केंद्र सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकतीं कि इस तस्करी में खालिस्तान समर्थक तत्व शामिल हैं। इन तत्वों को पाकिस्तान के साथ पश्चिमी देशों के खालिस्तान समर्थकों से ही सहयोग नहीं मिल रहा है, बल्कि पंजाब में भी कुछ समूह और संगठन ऐसे हैं, जो उनकी गतिविधियों पर मौन रहना पसंद करते हैं। खेद की बात यह है कि इनमें कुछ राजनीतिक और धार्मिक समूह भी हैं। ऐसे संकीर्ण समूह यह ध्यान रखें तो बेहतर कि आतंक और अलगाव पैदा करने वाली घटनाओं के खिलाफ जानबूझकर चुप्पी साधे रहना एक तरह से अपराध में भागीदारी करने जैसा है। खालिस्तान समर्थकों की हरकतों पर पंजाब के कुछ समूहों का मौन इन तत्वों का दुस्साहस बढ़ाने का ही काम कर रहा है। इसी दुस्साहस के चलते वे आतंक पैदा करने और साथ ही हिंदू-सिख रिश्तों में दरार डालने वाली हरकतें कर रहे हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय में पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या की जा चुकी है। इन हत्याओं की जिम्मेदारी खालिस्तान समर्थक तत्वों ने ली है। गत दिवस भी एक हिंदू नेता को जान से मारने की धमकी दी गई।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

उत्तराखंड ने ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे सुधारों और परिवर्तनों को लेकर सकारात्मक रवैया रहा है। केंद्र सरकार ऊर्जा सुधारों के साथ ही हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र के ऐसे अभियानों के साथ कदमताल करने का लाभ प्रदेश को विद्युत पारेषण से लेकर आम उपभोक्ता के लिए विद्युत आपूर्ति नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के रूप में मिल रहा है। इस क्रम में अब स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। इसे लेकर हो रही आशंका के समाधान के लिए स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहल करते हुए अपने शासकीय आवास पर यह मीटर लगाया। साथ ही समस्त मंत्रियों, विधायकों एवं अधिकारियों के सरकारी एवं निजी आवासों पर भी इस योजना को क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। यही नहीं, उन्होंने शासकीय आवास के बाद ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा में अपने निजी आवास पर भी स्मार्ट मीटर स्थापित कराया। इस योजना को जून, 2026 तक प्रदेश में समस्त उपभोक्ताओं के लिए लागू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने से मीटर रीडिंग में किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नहीं रहेगी। साथ में गलत बिलिंग की आम शिकायत दूर होगी और उपभोक्ताओं को रियल टाइम बिजली खपत की जानकारी मिल सकेगी। यद्यपि, तकनीकी का उपयोग कर ऊर्जा सुधार करने के प्रत्यक्ष लाभ मिल रहे हैं, लेकिन आमजन का विश्वास जीतने के लिए विभाग और उसके कार्मिकों की कार्यप्रणाली में भी सुधार अपेक्षित है।

> प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिलों में गड़बड़ी की शिकायतें दूर करने में बड़ी सहायता मिलने की उम्मीद है

नाकामी की पोल खोलता नदियों का प्रदूषण

संजय गुप्त

सभी दल नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे प्रदूषित बनी हुई हैं। यह राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है

अवधेश राजपूत

जलशक्ति मंत्रालय की ओर से संसद में दी गई यह जानकारी निराश करने वाली है कि नदियों के प्रदूषण को दूर करने का काम सही तरह नहीं हो पा रहा है। यह स्वीकारोक्ति इसलिए चिंताजनक है, क्योंकि एक लंबे समय से कहा जा रहा है कि नदियों में सीवरों का गैर शोधित पानी नहीं गिरने दिया जाएगा। बीते दिनों संसद में दी गई जानकारी से यह पता चल रहा है कि सीवेज सिस्टम की खामी से नदियों को प्रदूषण मुक्त करने में बाधा आ रही है। 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही जब गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने का अभियान नए सिरे से शुरू किया और इसके लिए एक नई व्यवस्था बनाई, तब यह उम्मीद बंधी थी कि इस नदी को प्रदूषण मुक्त करने के साथ अन्य नदियों को प्रदूषित होने से रोकने में सफलता मिलेगी, लेकिन स्थिति यह है कि अभी गंगा को भी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सका है।

नदियों में सीवरों और गंदे नालों का पानी बिना शोधित किए न जाने पाए, यह देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और उनके नगर निकायों की है, लेकिन वे इसमें कोताही बरत रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अभी भी नदियों का प्रदूषण जारी है। इसका कारण यह है कि जहां सीवेज शोधन संयंत्र पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं, वहीं अनेक शहरों के गंदे नाले अभी तक इन संयंत्रों से नहीं जोड़े जा सके हैं। दुनिया के अन्य देशों की तरह अपने देश में भी तमाम शहर नदियों किनारे बसे हुए हैं। समय के साथ नदियों के तट पर आबादी का घनत्व भी बढ़ रहा है। इस आबादी के एक बड़े हिस्से के पास सीवेज सिस्टम नहीं है, क्योंकि वह अनधिकृत कालोनियों में अधिक रहती है। इसके अलावा शहरों का जो सीवेज सिस्टम है, वह पुराना पड़ चुका है। समस्या इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि सीवेज सिस्टम पर्याप्त क्षमता के नहीं हैं। वे सीवरों का पूरा गंदा पानी शोधित नहीं कर पाते। इससे सीवरों का गैर शोधित पानी सीधे नदियों में जाता है। यह स्थिति महानगरों में भी है। पिछले दिनों दिल्ली में सत्ता बदलने के बाद से यमुना की सफाई पर खूब चर्चा हो रही है। चुनाव में यमुना का प्रदूषण एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी सरकार भी यमुना को साफ करने की बात करती थी, लेकिन वह नाकाम रही। इसका एक कारण राज्य और केंद्र सरकार का झगड़ा भी रहा। इस झगड़े की वजह से यमुना की सफाई प्राथमिकता नहीं बन सकी।

शायद ही कोई दल हो, जो नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने की बात न करता हो, लेकिन इसके बाद भी वे प्रदूषित बनी हुई हैं। यह राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है। नदियों के प्रदूषित होने का एक बड़ा कारण नगर नियोजन से संबंधित नौकरशाही का नकारापन भी है। नौकरशाही ने नदियों किनारे होने वाली अनियोजित बसाहट को रोकने में उदासीनता का ही परिचय दिया है। उन्होंने इसे लेकर सरकारों को आगाह भी नहीं किया। नदियों के प्रदूषण में नौकरशाही की भूमिका पर कभी कोई ठोस चर्चा नहीं हुई। अच्छा हो कि सरकार इस पर कोई श्वेतपत्र लाए कि नदियां क्यों प्रदूषित हैं? श्वेतपत्र में इसका भी उल्लेख किया जाए कि जब नदियों किनारे बसाहट हो रही था, तब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी बढ़ती आबादी के लिए उपयुक्त सीवेज सिस्टम का निर्माण क्यों नहीं करा रहे थे? यदि यह मान लिया जाए कि पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आखिर इसका क्या मतलब कि अब भी ध्यान न दिया जाए। एक ऐसे समय जब केंद्र के साथ राज्य सरकारों की ओर से नदियों को साफ करने के दावे किए जा रहे हैं, तब सीवेज सिस्टम में सुधार न हो पाना, गंदे नालों का सीवेज शोधन संयंत्रों से न जुड़ पाना और इन संयंत्रों का पूरी क्षमता से काम न कर पाना चकित करता है। अरबों रुपये सीवेज व्यवस्था को दुरुस्थ करने में खर्च किए जा चुके हैं, पर यही तथ्य बार-बार सामने आता है कि यह व्यवस्था अपर्याप्त और असंतोषजनक है। सीवेज व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बनाए गए कई सीवेज शोधन संयंत्र एक-दो साल चलने के बाद ही बंद हो जाते हैं। आज उन अनेक शहरों की सीवेज व्यवस्था सही तरह काम कर रही है, जिनका निर्माण अंग्रेजों ने कराया था, लेकिन हमारे इंजीनियर हर किस्म के आधारभूत ढांचे का निर्माण इस तरह करते हैं कि वह दो-चार साल में ही कमजोर पड़ जाता है या अपर्याप्त साबित हो जाता है।

नदियों में प्रदूषण केवल सीवेज सिस्टम की खराबी से ही नहीं होता, बल्कि उद्योगों के अपशिष्ट जल से भी होता है। गंभीर बात यह है कि तमाम उद्योग अपने विषाक्त जल को शोधित करने के बजाय उसे रिवर्स बोरिंग कर जमीन में समाहित कर देते हैं। यह अपराध है, लेकिन उस पर रोक इसलिए नहीं लग रही है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकारी ऐसे उद्योगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते। इसका नतीजा यह है कि उद्योग जानबूझकर भूजल को दूषित कर रहे हैं। यह दूषित जल भूगर्भ जल को विषैला करता है और अनेक बीमारियों का कारण बनता है। पंजाब में कैंसर के मामले बढ़ने के पीछे भूमिगत जल के प्रदूषण को ही माना जा रहा है। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने वाली व्यवस्था तब सुधरेगी, जब शासन-प्रशासन के साथ आम जनमानस भी सचेत होगा।

सरकारी कर्मचारी और विशेष रूप से इंजीनियरों पर यह दारोमदार होता है कि वे बेहतर इंजीनियरिंग और गुणवत्ता वाले निर्माण कराएं, लेकिन इसमें शिथिलता ही देखने को मिलती है। यह किसी से छिपा भी नहीं, लेकिन इसके बाद भी इंजीनियरों को जवाबदेह बनाने और उन्हें उनके घटिया निर्माण के लिए दंडित करने का काम नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सड़कों के निर्माण और डिजाइनिंग में खामी इसलिए देखने को मिल रही है, क्योंकि इंजीनियर उनका निर्माण सही तरह नहीं करते। यह हाल एनएचएआइ के इंजीनियरों के साथ अन्य सरकारी विभागों का भी है। आज जब हम संकल्प ले रहे हैं कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है, तब यदि बेसिक इंजीनियरिंग में भी दक्षता हासिल नहीं की जा पा रही है तो यह शर्म की बात है।

response@jagran.com

पूरा देश ही रेल के सफर में

हास्य-व्यंग्य

सूर्यकुमार पांडेय

> अपने से कम आयु के व्यक्ति को देखते ही हम लोग उपदेश की मुद्रा में आ जाया करते हैं

https://t.me/AllNewsPaperPaid

इन दिनों हर कोई सीने में जलन और आंखों में तूफान लिए हुए है। वह भी मुझको इसी मनोदशा में मिले। अपना पिट्ठू बैग लादे हुए आटो रिक्शे पर ठीक मेरी बगल में बैठे हुए थे। मैं उन्हें जानता नहीं था, लेकिन उम्र में मुझसे 20-30 साल छोटे तो रहे ही होंगे। अपने से कम आयु के व्यक्ति को देखते ही हम लोग उपदेश की मुद्रा में आ जाया करते हैं। यह मनुष्य की ऐसी आदत है, जो विरासत के तौर पर उसको प्राप्त होती है। पहले के जमाने के हमारे पुरखों की देन है यह, जिसको संभालना ही नहीं होता है, वरना यथासमय उपयोग में भी लाना पड़ता है। हम अवसर की तलाश में रहते हैं कि कब मौका मिले और अपने तजुर्बे की गठरी को खोल कर ज्ञान का अनमोल रत्न लुटाएं।

मैंने उनसे कहा, 'अपनी पीठ का सामान सामने रख लीजिए। दिक्कत हो रही होगी।' उन्होंने नाक-भौं सिकोड़ी और कहने लगे, 'सामान मेरा और पीठ भी मेरी। आपको क्या परेशानी है? मैंने आपकी पीठ पर तो अपना यह बैग रखा नहीं है। चुपचाप बैठे रहिए। मैं जल्दी में हूं। रेलवे स्टेशन पहुंचकर टिकट का जुगाड़ करना है।' मैंने कहा, 'रिजर्वेशन नहीं है क्या? आजकल तो लोग महीनों पहले अपना टिकट बना लेते हैं। आनलाइन की सुविधा है। आप तो नए जमाने वाले हैं।' मैंने अपने आपको उपदेश की मुद्रा से दस कदम पीछे हटा लिया। वह बोले, 'यह सब मुझको मत समझाइए। आप क्या समझ रहे हैं। रिजर्वेशन वाला टिकट मेरे मोबाइल में है। तीन महीने पहले करा लिया था। वेटिंग मिला था, सोचा था, इतने दिनों में कंफर्म हो ही जाएगा। नहीं हो पाया। यही तो टेंशन है।' सच है। आज हर कोई टेंशन में जी रहा है। वाई-फाई न आए तो टेंशन। वाटर सप्लाई न आए तो टेंशन। काम वाली बाई न आए तो टेंशन। महंगाई की टेंशन तो है ही, जब जाब नहीं पाई थी तो अलग टेंशन थी। अब प्राइवेट इंप्लाई हो गए हैं तो वर्क टार्गेट पूरा न हो पाने का टेंशन है। इस दौर में सारा माहौल ही तनावपूर्ण चल रहा है।

आटो रिक्शा स्टेशन के सामने पहुंच चुका था। वह अपना पिट्ठू बैग लादे हुए इतनी हड़बड़ी में उतरे और भागे कि आटो चालक को किराया तक देना भूल गए। उसने आवाज दी, तब कहीं जाकर उसको पैसे मिले। संयोग से एक घंटे बाद वह फिर वहीं स्टेशन के बाहर दिखाई दे गए। मैंने कहा, 'अरे, आप तो वापस आ गए! क्या जा नहीं रहे हैं!' वह झुंझला पड़े और बोले, 'हां, नहीं जा रहा हूं, आपसे क्या मतलब? 'मैंने गलती से उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। वह बिलबिला उठे थे। मैं बोला, 'तो ट्रेन छूट गई होगी?' वह कहने लगे, 'न छूटी, न कैंसिल हुई और न लेट हुई। बस पूछिए मत। अब इस जिंदगी में त्योहार के पहले और बाद में कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। बाप रे, इतनी भीड़! तिल तक धरने की जगह नहीं। भाई लोगों ने बोगी के फुटबोर्ड तक पर पैर नहीं रखने दिया। ऐसा लग रहा है, जैसे पूरा देश ही रेल के सफर में है।'

मैंने मरहम लगाने की नीयत से कहा, 'आप सच कह रहे हैं, भीड़ में घुसना भाड़ में घुसने के बराबर होता है।' वैसे वह भी मुझे भाड़ के भुने हुए चने जैसे दिखाई पड़ रहे थे। वह भुनभुनाते हुए बोले, 'इस भीड़ का इलाज किसी के पास भी नहीं।' मैंने कहा, 'अब अगले एक महीने तक बाहर की यात्रा स्थगित कर दीजिए। अभी तो यह होली के बाद की भीड़ है। इसके बाद गर्मियों की छुट्टियों वाली भीड़ की गाड़ी भी पिछले सिग्नल पर खड़ी मिलेगी। न जाने यह भीड़ हमें कहां ले जाएगी?' वसीम बरेलवी ने ठीक ही लिखा है, हर शख्स भागता है यहां भीड़ की तरफ, और यह भी चाहता है, उसे रास्ता मिले।' वह ठंडे होते हुए बोले, 'जो इस भीड़ में रास्ता पा लेता है, वह खुशकिस्मत है।'

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | विदेश पढ़ने गए भारतीय छात्र (वर्ष 2024)

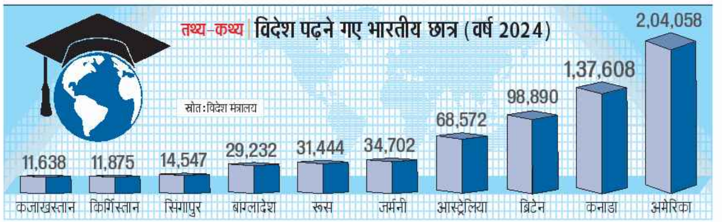

ऊर्जा

कर्तव्य एवं दायित्व बोध

उन्नत समाज निर्माण के लिए नागरिकों में कर्तव्य-बोध और दायित्व-बोध का होना बहुत जरूरी होता है। यानी नागरिकों में कर्तव्य की चेतना का जागरण और दायित्व की चेतना का जागरण होना जरूरी होता है। आखिर दंड और यंत्रणा से कब तक काम चलेगा? क्या पूरे जीवन-काल तक आदमी नियंत्रण में रहेगा? यह सच्चाई है कि भयभीत समाज सदा रोगग्रस्त रहता है, वह कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। भय सबसे बड़ी बीमारी है। जब भय होता है तब समाज में दायित्व और कर्तव्य की चेतना नहीं जगती। जिस समाज में कर्तव्य और दायित्व की चेतना जाग जाती है उसे डरने की जरूरत नहीं होती है। आदर्श समाज व्यवस्था में चरित्र निर्माण का दायित्व हर व्यक्ति से जुड़ा होता है। आज के साहित्य का एक शब्द है-'भोगा हुआ यथार्थ'। हमें केवल कल्पना में नहीं जीना चाहिए। कल्पना तब तक अर्थवान नहीं होती जब तक कि 'भोगे हुए यथार्थ' पर हम नहीं चल पाते हैं। हमारा जीवन यथार्थ एवं कर्तव्यपरायण होना चाहिए। कर्तव्यपरायणता की पहली शर्त है-निष्ठा और जागरूकता। जिस व्यक्ति की कर्तव्यपालन में निष्ठा है, वह प्रमाद, अन्याय और मुफ्तखोरी जैसा कोई काम नहीं कर सकता है। कर्तव्य-भावना की कमी का कारण राष्ट्रीय प्रेम की न्यूनता भी है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा तो प्रमाद जैसी स्थिति को पनपने का अवसर ही नहीं मिलेगा।

जीवन में बहुत कुछ बेहतरीन होना बाकी है। कई खूबसूरत क्षण रास्ते में हमारी प्रतीक्षा में हैं। हमारी कई उम्मीदें को अभी उड़ान भरनी है। कई हैरतों से मुलाकात होनी है। कई सुख बाहें फैलाए खड़े हैं, पर समस्या यह है कि हम कर्तव्य-बोध और दायित्व-बोध को भूल कर बेध्यानी में जिए जा रहे हैं। दुनिया हमारी ओर मुंह किए खड़ी है और हम कहीं और ही उदास बने खड़े हैं। अपने भरोसे को मजबूत बनाएं, दुनिया में बहुत कुछ आपके लिए है।

ललित गर्ग

रिकार्ड गर्मी से बढ़ा समुद्र का स्तर

मुकुल व्यास

> समुद्र के निरंतर विस्तार से तटीय शहर और पारिस्थितिकी तंत्र बदल रहे हैं

समुद्रों में उथल-पुथल होती रहती है। वे कभी भी स्थिर नहीं रहते। वे बदलते रहते हैं, मंथन करते हैं और विभिन्न ज्ञात और अज्ञात शक्तियों से जूझते रहते हैं। ज्वार आते जाते हैं और समुद्री धाराएं दुनिया भर में घूमती हैं। उनके गहरे पानी में प्राचीन रहस्य छिपे हुए हैं। फिर भी, हाल के दशकों में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है और वह है समुद्र के स्तर में बहुत तेजी से वृद्धि। विज्ञानियों को यह उम्मीद नहीं थी कि समुद्री स्तर इतनी तेजी से बढ़ेगा। समुद्र के निरंतर विस्तार से तटीय शहर और पारिस्थितिकी तंत्र बदल रहे हैं। तूफान के बनने के तरीके में भी परिवर्तन हो रहा है। 2024 में वैश्विक समुद्र का स्तर प्रति वर्ष 0.59 सेंटीमीटर की दर से बढ़ा। यह आंकड़ा में छोटा लग सकता है, लेकिन जब पृथ्वी के महासागरों की विशालता पर नजर डाली जाए तो यह दर चौंकाने वाली है। विज्ञानियों ने प्रति वर्ष 0.43 सेंटीमीटर की वृद्धि की उम्मीद की थी। इसके बजाय वृद्धि तेजी से हुई, जो मुख्य रूप से गर्म होते समुद्री जल के विस्तार की वजह से हुई।

पिछले साल रिकार्ड गर्मी पड़ी और वैश्विक तापमान ने 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को भी पार कर दिया। वैसे हर साल थोड़ा अलग होता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि समुद्रों के जल स्तर का बढ़ना जारी है, और वृद्धि की दर लगातार तेज होती जा रही है। तीन दशकों के उपग्रह डाटा इस प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। समुद्रों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है और वे अधिक से अधिक किनारों को निगल रहे हैं और जमीन पर आगे बढ़ रहे हैं।

समुद्री स्तर को ऊंचा उठाने वाले कारणों में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पिछले कई सालों से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण बर्फ का पिघलना था। ग्लेशियर और बर्फ की चादरें अपने जमे हुए द्रव्यमान को समुद्र में बहा देती हैं। अभी तक बढ़े हुए जल स्तर में लगभग दो-तिहाई हिस्सा पिघली बर्फ से आता था। जबकि बाकी योगदान तापीय विस्तार से होता था। तापीय विस्तार तब होता है जब गर्मी को अवशोषित करने के कारण समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन 2024 में यह संतुलन उलट गया। समुद्र गर्म होने लगे। अब समुद्र के स्तर में दो-तिहाई वृद्धि अकेले तापीय विस्तार से होती है। यह बदलाव एक गहरी समस्या का संकेत देता है। भले ही ग्लेशियर कल पिघलना बंद कर दें, लेकिन महासागर फिर भी बढ़ेंगे। पहले से अवशोषित गर्मी सदियों नहीं तो सालों तक पानी का विस्तार करती रहेगी। समुद्र के स्तर बढ़ने पर नजर रखने के लिए सटीकता की आवश्यकता होती है। उपग्रहों के माध्यम से विज्ञानियों को समुद्र की ऊंचाई को मापने की क्षमता मिली है। उपग्रह 1993 से पृथ्वी के पानी पर लगातार नजर रख रहे हैं। पिछली सदी के अंतिम दशक की शुरुआत से समुद्र का स्तर लगभग 10 सेंटीमीटर बढ़ गया है। समुद्र के स्तर में वृद्धि आने वाले समय के बारे में एक बड़ी चेतावनी है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

क्या-क्या करेंगे पीके?

प्रशांत किशोर उर्फ पीके पहले चुनावी रणनीतिकार थे। अब नेता बन गए हैं। अपनी पार्टी बनाकर बिहार की राजनीति में दो वर्षों से माथापच्ची कर रहे हैं। स्थापित और पुराने दलों से ज्यादा चर्चा में हैं, लेकिन बातों में विरोधाभास झलकता है। कभी कहते हैं कि चुनाव लड़वाएंगे। अगले ही दिन कहते हैं कि चुनाव खुद ही लड़ेंगे। हाल ही में उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार में राघोपुर सीट से खुद प्रत्याशी बनने के संकेत भी दिए हैं। पिछले महीने के आखिर में जब वह तमिलनाडु गए थे तो वहां विजय थलापति की एक नवोदित पार्टी टीवीके को चुनाव लड़ाने का वादा कर आए। विजय तमिल फिल्मों के सुपर स्टार हैं और दोनों दोस्त भी हैं। विजय को बिहार आने का न्योता भी दे आए हैं। इन सबके बीच चर्चा गरम है कि अकेले पीके क्या-क्या करेंगे? बिहार में चुनाव लड़ेंगे कि तमिलनाडु में मित्र की मदद करने जाएंगे। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में मात्र तीन महीने का अंतर है। पीके खुद बिहार में दो वर्षों से सक्रिय हैं, पर अभी तक पांव नहीं जमा पाए हैं। ऐसे में वह विजय को कैसे और कितनी मदद कर पाएंगे यह तो वक्त ही बताएगा।

राजरंग

फूटा आक्रोश

जब मैदान अपना हो और कप्तान से लेकर पिच भी अपने हिसाब से हो, फिर भी बल्लेबाजी मनोनुकूल न हो तो निराश होना लाजिमी है। सियासत के मैदान में भी बीते दिनों ऐसे ही एक दृश्य ने लोकसभा में सबका ध्यान खींचा। दरअसल अंडमान-निकोबार से भाजपा के पांच बार के सांसद विष्णु पद रे सदन में अचानक आक्रोश से फूट पड़े और उसकी तपिश से सत्तापक्ष के संसदीय रणनीतिकारों को दो-चार होना पड़ा। उनके गुस्से का सबसे ज्यादा निशाना सदन में भाजपा के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल की ओर था। रविशंकर प्रसाद से लेकर संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू को भी उनके आक्रोश को थामने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। गुस्से के बीच रे लगातार यह कहते सुने गए कि सरकार अपनी है, मगर उनके जैसे सांसदों के काम बार-बार प्रयासों के बावजूद नहीं हो पाते। काम नहीं होने से लेकर शिकायतों की सुनवाई न हो पाने के मसले को वह सदन में उठाना चाहते थे, मगर पार्टी के मुख्य सचेतक की वक्ताओं की सूची में उनका नाम नहीं था। इसीलिए रे सदन में ही यह कहते हुए फूट पड़े कि सरकार अपनी, प्रशासन अपना, फिर भी भाजपा के सांसद होते हुए जनप्रतिनिधि के रूप में उनके काम नहीं हो पाते तो सदन में माननीय बने रहने का औचित्य ही क्या है?

भाजपा का 'राहुल प्रेम'

भाजपा का 'राहुल प्रेम' जगजाहिर है। सत्ताधारी पार्टी नेता प्रतिपक्ष पर कोई भी हमला करने से नहीं चूकती है। यहां तक कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं भी उसके निशाने पर होती हैं। राहुल गांधी वियतनाम के दौरे पर हैं, इस पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस में यह मुद्दा उठाते हुए चुटकी ली कि नए साल के बाद दूसरी बार राहुल गांधी वियतनाम गए हैं। तंज कसते हुए पूछा कि आखिर बार-बार वह वियतनाम क्यों जा रहे हैं? इसके पहले भी भाजपा कांग्रेस नेता की कुछ अन्य देशों की यात्राओं पर चुटकी लेती रही है।

जब मंत्री जी भूले कि वही हैं मंत्री

संसद में सवालों का जवाब देने का कभी-कभी ऐसा दबाव होता है कि कई बार मंत्री खुद भी भूल जाते हैं कि वही मंत्री हैं। ऐसा ही एक नजारा बीते हफ्ते संसद में देखने को मिला जब अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी राज्यसभा में सदस्यों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस क्रम में सूर्य घर योजना से जुड़े सवालों का जवाब देने के दौरान मंत्री महोदय प्रवाह में माननीय सांसद की जगह यह कहते चले गए कि मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं...। मंत्री की इस भूल पर सदस्य चुटकी ले रहे थे, पर जोशी को यह समझ नहीं आ रहा था कि सांसद हंस क्यों रहे हैं। बाद में उन्हें भी भूल का अहसास हुआ और सदस्यों के साथ मुस्कुराने लगे।

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

चिंतित करता पंजाब

अमृतसर के एक मंदिर में बम फेंके जाने की घटना गंभीर चिंता का कारण बननी चाहिए, क्योंकि हाल के समय में यह पहली बार है, जब किसी हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया और वह भी होली की रात। इसके पहले कई पुलिस चौकियों और थानों पर इसी तरह बम फेंके गए हैं। चौकियों और थानों के बाद मंदिर को निशाना बनाया जाना आतंकी तत्वों के बढ़ते दुस्साहस को बयान करने के साथ यह भी रेखांकित कर रहा है कि पंजाब के सांप्रदायिक सद्भाव पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की मानें तो मंदिर पर हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ का हाथ है, लेकिन प्रबल आशंका यही है कि बम फेंकने का काम खालिस्तान समर्थक तत्वों ने किया होगा। परिस्थितियां भी यही संकेत कर रही हैं। यह घटना कितनी गंभीर है, इसका पता इससे भी चलता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यह स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य के माहौल को बिगाड़ने की साजिश की जा रही है, लेकिन केवल इतना कहने से काम चलने वाला नहीं है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को राज्य की गिरती कानून एवं व्यवस्था पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा और इस क्रम में खालिस्तान समर्थक तत्वों के विरुद्ध कठोरता का परिचय देना होगा।

अतीत में पंजाब को आतंकवाद की आग में झोंकने वाले खालिस्तान समर्थक तत्व किसी नरमी के हकदार नहीं। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें हर तरह का सहयोग और समर्थन देने में लगा हुआ है। इसका प्रमाण पाकिस्तान से हथियारों और नशीले पदार्थों की बढ़ती तस्करी से मिलता है। पंजाब और साथ ही केंद्र सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकतीं कि इस तस्करी में खालिस्तान समर्थक तत्व शामिल हैं। इन तत्वों को पाकिस्तान के साथ पश्चिमी देशों के खालिस्तान समर्थकों से ही सहयोग नहीं मिल रहा है, बल्कि पंजाब में भी कुछ समूह और संगठन ऐसे हैं, जो उनकी गतिविधियों पर मौन रहना पसंद करते हैं। खेद की बात यह है कि इनमें कुछ राजनीतिक और धार्मिक समूह भी हैं। ऐसे संकीर्ण समूह यह ध्यान रखें तो बेहतर कि आतंक और अलगाव पैदा करने वाली घटनाओं के खिलाफ जानबूझकर चुप्पी साधे रहना एक तरह से अपराध में भागीदारी करने जैसा है। खालिस्तान समर्थकों की हरकतों पर पंजाब के कुछ समूहों का मौन इन तत्वों का दुस्साहस बढ़ाने का ही काम कर रहा है। इसी दुस्साहस के चलते वे आतंक पैदा करने और साथ ही हिंदू-सिख रिश्तों में दरार डालने वाली हरकतें कर रहे हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय में पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या की जा चुकी है। इन हत्याओं की जिम्मेदारी खालिस्तान समर्थक तत्वों ने ली है। गत दिवस भी एक हिंदू नेता को जान से मारने की धमकी दी गई।

सख्ती जरूरी

होली पर रंग में भंग नहीं पड़े, इसके लिए यातायात पुलिस की ओर से की गई सख्ती सराहनीय हैं। इस वर्ष यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान भले ही काफी कटे, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों और घायलों की संख्या में कमी भी देखी गई। हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए यातायात पुलिस के 1,100 हवलदार व सिपाहियों की तैनाती की गई थी। 500 जोनल अफसर, 50 ट्रैफिक इंस्पेक्टर व 16 एसीपी भी तैनात थे।

हुड़दंग से बचा जाना चाहिए, त्योहार चाहे कोई भी हो, कुछ ऐसा किया जाए जो दूसरों को भी प्रेरित-प्रोत्साहित करे

इसमे कोई संदेह नहीं कि होली पर लोग होश खो बैठते हैं, कहीं शराब तो कहीं भांग के नशे में वाहन चलाने पर दुर्घटना का शिकार होते हैं और झगड़ा भी कर बैठते हैं। यही नहीं, केमिकल युक्त रंगों और स्प्रे का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं करते। इसके चलते बहुत लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इससे बचा जाना चाहिए। त्योहार चाहे कोई भी हो, कुछ ऐसा किया जाए जो दूसरों को भी प्रेरित-प्रोत्साहित करे। नाते-रिश्तेदारों और यार-दोस्तों के साथ-साथ उनका भी मुंह मीठा कराएं जो कहने को तो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। चाहे वह घर के नौकर-नौकरानी हों या चौकीदार, प्रेस करने वाले हों या सफाईकर्मी। समय मिले तो एक चक्कर अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम का भी लगाया जा सकता है। आपका थोड़ा सा वक्त उन्हें कितनी खुशी देगा, आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो दिल को मिलने वाली खुशी और सुकून में शोर शराबे एवं हुडदंग की कमी महसूस ही नहीं होगी।

कह के रहेंगे माधव जोशी

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या राज्य के बजट से रुपये का चिह्न हटाकर स्टालिन सरकार अलगाववाद को हवा दे रही है?

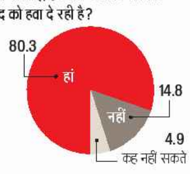

आज का सवाल

आयुष्मान कार्ड के लिए 70 वर्ष और उससे अधिक की उम्र सीमा को कम करके 60 वर्ष किया जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

नाकामी की पोल खोलता नदियों का प्रदूषण

संजय गुप्त

सभी दल नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे प्रदूषित बनी हुई हैं। यह राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है

जलशक्ति मंत्रालय की ओर से संसद में दी गई यह जानकारी निराश करने वाली है कि नदियों के प्रदूषण को दूर करने का काम सही तरह नहीं हो पा रहा है। यह स्वीकारोक्ति इसलिए चिंताजनक है, क्योंकि एक लंबे समय से कहा जा रहा है कि नदियों में सीवरों का गैर शोधित पानी नहीं गिरने दिया जाएगा। बीते दिनों संसद में दी गई जानकारी से यह पता चल रहा है कि सीवेज सिस्टम की खामी से नदियों को प्रदूषण मुक्त करने में बाधा आ रही है। 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही जब गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने का अभियान नए सिरे से शुरू किया और इसके लिए एक नई व्यवस्था बनाई, तब यह उम्मीद बंधी थी कि इस नदी को प्रदूषण मुक्त करने के साथ अन्य नदियों को प्रदूषित होने से रोकने में सफलता मिलेगी, लेकिन स्थिति यह है कि अभी गंगा को भी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सका है।

नदियों में सीवरों और गंदे नालों का पानी बिना शोधित किए न जाने पाए, यह देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और उनके नगर निकायों की है, लेकिन वे इसमें कोताही बरत रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अभी भी नदियों का प्रदूषण जारी है। इसका कारण यह है कि जहां सीवेज शोधन संयंत्र पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं, वहीं अनेक शहरों के गंदे नाले अभी तक इन संयंत्रों से नहीं जोड़े जा सके हैं। दुनिया के अन्य देशों की तरह अपने देश में भी तमाम शहर नदियों किनारे बसे हुए हैं। समय के साथ नदियों के तट पर आबादी का घनत्व भी बढ़ रहा है। इस आबादी के एक बड़े हिस्से के पास सीवेज सिस्टम नहीं है, क्योंकि वह अनधिकृत कालोनियों में अधिक रहती है। इसके अलावा शहरों का जो सीवेज सिस्टम है, वह पुराना पड़ चुका है। समस्या इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि सीवेज सिस्टम पर्याप्त क्षमता के नहीं हैं। वे सीवरों का पूरा गंदा पानी शोधित नहीं कर पाते। इसके चलते सीवरों का गैर शोधित पानी सीधे नदियों में जाता है। यह स्थिति महानगरों में भी है। पिछले दिनों दिल्ली में सत्ता बदलने के बाद से यमुना की सफाई पर खूब चर्चा हो रही है। चुनाव में यमुना का प्रदूषण एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी सरकार भी यमुना को साफ करने की बात करती थी, लेकिन वह नाकाम रही। इसका एक कारण राज्य और केंद्र सरकार का झगड़ा भी रहा। इस झगड़े की वजह से यमुना की सफाई प्राथमिकता नहीं बन सकी।

शायद ही कोई दल हो, जो नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने की बात न करता हो, लेकिन इसके बाद भी वे प्रदूषित बनी हुई हैं। यह राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है। नदियों के प्रदूषित होने का एक बड़ा कारण नगर नियोजन से संबंधित नौकरशाही का नकारापन भी है। नौकरशाही ने नदियों किनारे होने वाली अनियोजित बसाहट को रोकने में उदासीनता का ही परिचय दिया है। उन्होंने इसे लेकर सरकारों को आगाह भी नहीं किया। नदियों के प्रदूषण में नौकरशाही की भूमिका पर कभी कोई ठोस चर्चा नहीं हुई। अच्छा हो कि सरकार इस पर कोई श्वेतपत्र लाए कि नदियां क्यों प्रदूषित हैं? श्वेतपत्र में इसका भी उल्लेख किया जाए कि जब नदियों किनारे बसाहट हो रही था, तब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी बढ़ती आबादी के लिए उपयुक्त सीवेज सिस्टम का निर्माण क्यों नहीं करा रहे थे? यदि यह मान लिया जाए कि पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आखिर इसका क्या मतलब कि अब भी ध्यान न दिया जाए। एक ऐसे समय जब केंद्र के साथ राज्य सरकारों की ओर से नदियों को साफ करने के दावे किए जा रहे हैं, तब सीवेज सिस्टम में सुधार न हो पाना, गंदे नालों का सीवेज शोधन संयंत्रों से न जुड़ पाना और इन संयंत्रों का पूरी क्षमता से काम न कर पाना चकित करता है। अरबों रुपये सीवेज व्यवस्था को दुरुस्थ करने में खर्च किए जा चुके हैं, पर यही तथ्य बार-बार सामने आता है कि यह व्यवस्था अपर्याप्त और असंतोषजनक है। सीवेज व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बनाए गए कई सीवेज शोधन संयंत्र एक-दो साल चलने के बाद ही बंद हो जाते हैं। आज उन अनेक शहरों की सीवेज व्यवस्था सही तरह काम कर रही है, जिनका निर्माण अंग्रेजों ने कराया था, लेकिन हमारे इंजीनियर हर किस्म के आधारभूत ढांचे का निर्माण इस तरह करते हैं कि वह दो-चार साल में ही कमजोर पड़ जाता है या अपर्याप्त साबित हो जाता है।

अवधेश राजपूत

नदियों में प्रदूषण केवल सीवेज सिस्टम की खराबी से ही नहीं होता, बल्कि उद्योगों के अपशिष्ट जल से भी होता है। गंभीर बात यह है कि तमाम उद्योग अपने विषाक्त जल को शोधित करने के बजाय उसे रिवर्स बोरिंग कर जमीन में समाहित कर देते हैं। यह अपराध है, लेकिन उस पर रोक इसलिए नहीं लग रही है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकारी ऐसे उद्योगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते। इसका नतीजा यह है कि उद्योग जानबूझकर भूजल को दूषित कर रहे हैं। यह दूषित जल भूगर्भ जल को विषैला करता है और अनेक बीमारियों का कारण बनता है। पंजाब में कैंसर के मामले बढ़ने के पीछे भूमिगत जल के प्रदूषण को ही माना जा रहा है। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने वाली व्यवस्था तब सुधरेगी, जब शासन-प्रशासन के साथ आम जनमानस भी सचेत होगा।

सरकारी कर्मचारी और विशेष रूप से इंजीनियरों पर यह दारोमदार होता है कि वे बेहतर इंजीनियरिंग और गुणवत्ता वाले निर्माण कराएं, लेकिन इसमें शिथिलता ही देखने को मिलती है। यह किसी से छिपा भी नहीं, लेकिन इसके बाद भी इंजीनियरों को जवाबदेह बनाने और उन्हें उनके घटिया निर्माण के लिए दंडित करने का काम नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सड़कों के निर्माण और डिजाइनिंग में खामी इसलिए देखने को मिल रही है, क्योंकि इंजीनियर उनका निर्माण सही तरह नहीं करते। यह हाल एनएचएआइ के इंजीनियरों के साथ अन्य सरकारी विभागों का भी है। आज जब हम संकल्प ले रहे हैं कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है, तब यदि बेसिक इंजीनियरिंग में भी दक्षता हासिल नहीं की जा पा रही है तो यह शर्म की बात है।

response@jagran.com

पूरा देश ही रेल के सफर में

हास्य-व्यंग्य

इन दिनों हर कोई सीने में जलन और आंखों में तूफान लिए हुए है। वह भी मुझको इसी मनोदशा में मिले। अपना पिट्ठू बैग लादे हुए आटो रिक्शे पर ठीक मेरी बगल में बैठे हुए थे। मैं उन्हें जानता नहीं था, लेकिन उम्र में मुझसे 20-30 साल छोटे तो रहे ही होंगे। अपने से कम आयु के व्यक्ति को देखते ही हम लोग उपदेश की मुद्रा में आ जाया करते हैं। यह मनुष्य की ऐसी आदत है, जो विरासत के तौर पर उसको प्राप्त होती है। पहले के जमाने के हमारे पुरखों की देन है यह, जिसको संभालना ही नहीं होता है, वरना यथासमय उपयोग में भी लाना पड़ता है। हम अवसर की तलाश में रहते हैं कि कब मौका मिले और अपने तजुर्बे की गठरी को खोल कर ज्ञान का अनमोल रत्न लुटाएं।

सूर्यकुमार पांडेय

अपने से कम आयु के व्यक्ति को देखते ही हम लोग उपदेश की मुद्रा में आ जाया करते हैं

मैंने उनसे कहा, 'अपनी पीठ का सामान सामने रख लीजिए। दिक्कत हो रही होगी।' उन्होंने नाक-भौं सिकोड़ी और कहने लगे, 'सामान मेरा और पीठ भी मेरी। आपको क्या परेशानी है? मैंने आपकी पीठ पर तो अपना यह बैग रखा नहीं है। चुपचाप बैठे रहिए। मैं जल्दी में हूं। रेलवे स्टेशन पहुंचकर टिकट का जुगाड़ करना है।' मैंने कहा, 'रिजर्वेशन नहीं है क्या? आजकल तो लोग महीनों पहले अपना टिकट बना लेते हैं। आनलाइन की सुविधा है। आप तो नए जमाने वाले हैं।' मैंने अपने आपको उपदेश की मुद्रा से दस कदम पीछे हटा लिया। वह बोले, 'यह सब मुझको मत समझाइए। आप क्या समझ रहे हैं। रिजर्वेशन वाला टिकट मेरे मोबाइल में है। तीन महीने पहले करा लिया था। वेटिंग मिला था, सोचा था, इतने दिनों में कंफर्म हो ही जाएगा। नहीं हो पाया। यही तो टेंशन है।' सच है। आज हर कोई टेंशन में जी रहा है। वाई-फाई न आए तो टेंशन। वाटर सप्लाई न आए तो टेंशन। काम वाली बाई न आए तो टेंशन। महंगाई की टेंशन तो है ही, जब जाब नहीं पाई थी तो अलग टेंशन थी। अब प्राइवेट इंप्लाई हो गए हैं तो वर्क टार्गेट पूरा न हो पाने का टेंशन है। इस दौर में सारा माहौल ही तनावपूर्ण चल रहा है।

आटो रिक्शा स्टेशन के सामने पहुंच चुका था। वह अपना पिट्ठू बैग लादे हुए इतनी हड़बड़ी में उतरे और भागे कि आटो चालक को किराया तक देना भूल गए। उसने आवाज दी, तब कहीं जाकर उसको पैसे मिले। संयोग से एक घंटे बाद वह फिर मुझको वहीं स्टेशन के बाहर दिखाई दे गए। मैंने कहा, 'अरे, आप तो वापस आ गए! क्या जा नहीं रहे हैं!' वह झुंझला पड़े और बोले, 'हां, नहीं जा रहा हूं, आपसे क्या मतलब?' मैंने गलती से उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। वह बिलबिला उठे थे। मैं बोला, 'तो ट्रेन छूट गई होगी?' वह कहने लगे, 'न छूटी, न कैंसिल हुई और न लेट हुई। बस पूछिए मत। अब इस जिंदगी में त्योहार के पहले और बाद में कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। बाप रे, इतनी भीड़! तिल तक धरने की जगह नहीं। भाई लोगों ने बोगी के फुटबोर्ड तक पर पैर नहीं रखने दिया। ऐसा लग रहा है, जैसे पूरा देश ही रेल के सफर में है।'

मैंने मरहम लगाने की नीयत से कहा, 'आप सच कह रहे हैं, भीड़ में घुसना भाड़ में घुसने के बराबर होता है।' वैसे वह भी मुझे भाड़ के भुने हुए चने जैसे दिखाई पड़ रहे थे। वह भुनभुनाते हुए बोले, 'इस भीड़ का इलाज किसी के पास भी नहीं।' मैंने कहा, 'अब अगले एक महीने तक बाहर की यात्रा स्थगित कर दीजिए। अभी तो यह होली के बाद की भीड़ है। इसके बाद गर्मियों की छुट्टियों वाली भीड़ की गाड़ी भी पिछले सिग्नल पर खड़ी मिलेगी। न जाने यह भीड़ हमें कहां ले जाएगी?' वसीम बरेलवी ने ठीक ही लिखा है, हर शख्स भागता है यहां भीड़ की तरफ, और यह भी चाहता है, उसे रास्ता मिले।' वह ठंडे होते हुए बोले, 'जो इस भीड़ में रास्ता पा लेता है, वह खुशकिस्मत है।'

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

तथ्य-कथ्य विदेश पढ़ने गए भारतीय छात्र (वर्ष 2024)

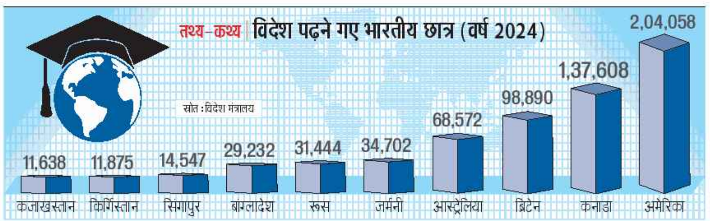

ऊर्जा

कर्तव्य एवं दायित्व बोध

उन्नत समाज निर्माण के लिए नागरिकों में कर्तव्य-बोध और दायित्व-बोध का होना बहुत जरूरी होता है। यानी नागरिकों में कर्तव्य की चेतना का जागरण और दायित्व की चेतना का जागरण होना जरूरी होता है। आखिर दंड और यंत्रणा से कब तक काम चलेगा? क्या पूरे जीवन-काल तक आदमी नियंत्रण में रहेगा? यह सच्चाई है कि भयभीत समाज सदा रोगग्रस्त रहता है, वह कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। भय सबसे बड़ी बीमारी है। जब भय होता है तब समाज में दायित्व और कर्तव्य की चेतना नहीं जगती। जिस समाज में कर्तव्य और दायित्व की चेतना जाग जाती है उसे डरने की जरूरत नहीं होती है।

आदर्श समाज व्यवस्था में चरित्र निर्माण का दायित्व हर व्यक्ति से जुड़ा होता है। आज के साहित्य का एक शब्द है-'भोगा हुआ यथार्थ'। हमें केवल कल्पना में नहीं जीना चाहिए। कल्पना तब तक अर्थवान नहीं होती जब तक कि 'भोगे हुए यथार्थ' पर हम नहीं चल पाते हैं। हमारा जीवन यथार्थ एवं कर्तव्यपरायण होना चाहिए। कर्तव्यपरायणता की पहली शर्त है-निष्ठा और जागरूकता। जिस व्यक्ति की कर्तव्यपालन में निष्ठा है, वह प्रमाद, अन्याय और मुफ्तखोरी जैसा कोई काम नहीं कर सकता है। कर्तव्य-भावना की कमी का कारण राष्ट्रीय प्रेम की न्यूनता भी है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा तो प्रमाद जैसी स्थिति को पनपने का अवसर ही नहीं मिलेगा।

जीवन में बहुत कुछ बेहतरीन होना बाकी है। कई खूबसूरत क्षण रास्ते में हमारी प्रतीक्षा में हैं। हमारी कई उम्मीदों को अभी उड़ान भरनी है। कई हैरतों से मुलाकात होनी है। कई सुख बाहें फैलाए खड़े हैं, पर समस्या यह है कि हम कर्तव्य-बोध और दायित्व-बोध को भूल कर बेध्यानी में जिए जा रहे हैं। दुनिया हमारी ओर मुंह किए खड़ी है और हम कहीं और ही उदास बने खड़े हैं। अपने भरोसे को मजबूत बनाएं, दुनिया में बहुत कुछ आपके लिए है।

ललित गर्ग

क्या-क्या करेंगे पीके?

प्रशांत किशोर उर्फ पीके पहले चुनावी रणनीतिकार थे। अब नेता बन गए हैं। अपनी पार्टी बनाकर बिहार की राजनीति में दो वर्षों से माथापच्ची कर रहे हैं। स्थापित और पुराने दलों से ज्यादा चर्चा में हैं, लेकिन बातों में विरोधाभास झलकता है। कभी कहते हैं कि चुनाव लड़वाएंगे। अगले ही दिन कहते हैं कि चुनाव खुद ही लड़ेंगे। हाल ही में उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार में राघोपुर सीट से खुद प्रत्याशी बनने के संकेत भी दिए हैं। पिछले महीने के आखिर में जब वह तमिलनाडु गए थे तो वहां विजय थलापति की एक नवोदित पार्टी टीवीके को चुनाव लड़ाने का वादा कर आए। विजय तमिल फिल्मों के सुपर स्टार हैं और दोनों दोस्त भी हैं। विजय को बिहार आने का न्योता भी दे आए हैं। इन सबके बीच चर्चा गरम है कि अकेले पीके क्या-क्या करेंगे? बिहार में चुनाव लड़ेंगे कि तमिलनाडु में मित्र की मदद करने जाएंगे। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में मात्र तीन महीने का अंतर है। पीके खुद बिहार में दो वर्षों से सक्रिय हैं, पर अभी तक पांव नहीं जमा पाए हैं। ऐसे में वह विजय को कैसे और कितनी मदद कर पाएंगे यह तो वक्त ही बताएगा।

राजरंग

फूटा आक्रोश

जब मैदान अपना हो और कप्तान से लेकर पिच भी अपने हिसाब से हो, फिर भी बल्लेबाजी मनोनुकूल न हो तो निराश होना लाजिमी है। सियासत के मैदान में भी बीते दिनों ऐसे ही एक दृश्य ने लोकसभा में सबका ध्यान खींचा। दरअसल अंडमान-निकोबार से भाजपा के पांच बार के सांसद विष्णु पद रे सदन में अचानक आक्रोश से फूट पड़े और उसकी तपिश से सत्तापक्ष के संसदीय रणनीतिकारों को दो-चार होना पड़ा। उनके गुस्से का सबसे ज्यादा निशाना सदन में भाजपा के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल की ओर था। रविशंकर प्रसाद से लेकर संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू को भी उनके आक्रोश को थामने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। गुस्से के बीच रे लगातार यह कहते सुने गए कि सरकार अपनी है, मगर उनके जैसे सांसदों के काम बार-बार प्रयासों के बावजूद नहीं हो पाते। काम नहीं होने से लेकर शिकायतों की सुनवाई न हो पाने के मसले को वह सदन में उठाना चाहते थे, मगर पार्टी के मुख्य सचेतक की वक्ताओं की सूची में उनका नाम नहीं था। इसीलिए रे सदन में ही यह कहते हुए फूट पड़े कि सरकार अपनी, प्रशासन अपना, फिर भी भाजपा के सांसद होते हुए जनप्रतिनिधि के रूप में उनके काम नहीं हो पाते तो सदन में माननीय बने रहने का औचित्य ही क्या है?

भाजपा का 'राहुल प्रेम'

भाजपा का 'राहुल प्रेम' जगजाहिर है। सत्ताधारी पार्टी नेता प्रतिपक्ष पर कोई भी हमला करने से नहीं चूकती है। यहां तक कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं भी उसके निशाने पर होती हैं। राहुल गांधी वियतनाम के दौरे पर हैं, इस पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस में यह मुद्दा उठाते हुए चुटकी ली कि नए साल के बाद दूसरी बार राहुल गांधी वियतनाम गए हैं। तंज कसते हुए पूछा कि आखिर बार-बार वह वियतनाम क्यों जा रहे हैं? इसके पहले भी भाजपा कांग्रेस नेता की कुछ अन्य देशों की यात्राओं पर चुटकी लेती रही है।

जब मंत्री जी भूले कि वही हैं मंत्री

संसद में सवालों का जवाब देने का कभी-कभी ऐसा दबाव होता है कि कई बार मंत्री खुद भी भूल जाते हैं कि वही मंत्री हैं। ऐसा ही एक नजारा बीते हफ्ते संसद में देखने को मिला जब अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी राज्यसभा में सदस्यों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस क्रम में सूर्य घर योजना से जुड़े सवालों का जवाब देने के दौरान मंत्री महोदय प्रवाह में माननीय सांसद की जगह यह कहते चले गए कि मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं...। मंत्री की इस भूल पर सदस्य चुटकी ले रहे थे, लेकिन जोशी को यह समझ नहीं आ रहा था कि सांसद हंस क्यों रहे हैं। बाद में उन्हें भी अपनी भूल का अहसास हुआ और वह भी सदस्यों के साथ मुस्कुराने लगे।

पोस्ट

जब दुनिया के बहुत से देशों में एलन मस्क के सेटेलाइट इंटरनेट की धूम है। जब भारत में भी स्टारलिंक के सेटेलाइट इंटरनेट का इंतजार मानो खत्म ही होने वाला है और एयरटेल एवं जियो पहले से 5जी सेवा दे ही रहे हैं, तब बीएसएनएल की 4जी सर्विस का क्या भविष्य है?
शरद शर्मा@sharadsharma1

लाडकी बहिन योजना के चलते महाराष्ट्र का वित्तीय घाटा और कर्ज बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र का इस साल का वित्तीय घाटा 45,000 करोड़ रुपये है और उस पर 8.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। रेवड़ी राजनीति के दम पर सत्ता हासिल करने वाली पार्टियों को यह सोचना होगा कि वे देश का भला कर रही हैं या वोट देने वाले देशवासियों को मूर्ख बना रही हैं।
अजय कुमार@AjayKumarJourno

राज्य सरकारें रेवड़ियां बांटने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कहीं आम लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही हैं, तो कहीं दूसरे विभागों की आवंटित राशि में कटौती कर रही हैं। याद रखिए- रेवड़ियां बांटने से गरीबी दूर नहीं होती, बल्कि यथास्थिति को ही मजबूती मिलती है। अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जनपथ

जाकर बंग्लादेश यदि तुम छेड़ोगे रार,
फिर तो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे चार।
टुकड़े होंगे चार रोक ना तुम पाओगे,
इकहत्तर दोहराय बाद में पछताओगे।
ढाका को उकसाय बनो मत ज्यादा धाकड़,
सिंध-बलोचिस्तान संभालो पहले जाकर!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 35 अंक 240

****

“ एक व्यापार शुल्क दूसरे को जन्म देता है, फिर तीसरे को, जब तक कि यह व्यापार युद्ध में न बदल जाएं। - मार्क मैककिन्न

यह टैरिफबाजी ट्रंप की घातक ईजाद नहीं है। यह अमेरिकी राजनीति की घुट्टी में मिला है। ट्रंप के राजनीतिक पुरखों की सियायत का ईंट-गारा इसी संरक्षणवाद से बना था। इसलिए लोगों को ट्रंप में अमेरिकी इतिहास के टैरिफ सूरमा 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकेनले दिखते हैं।

अमेरिकी टैरिफबाजी का फसाना

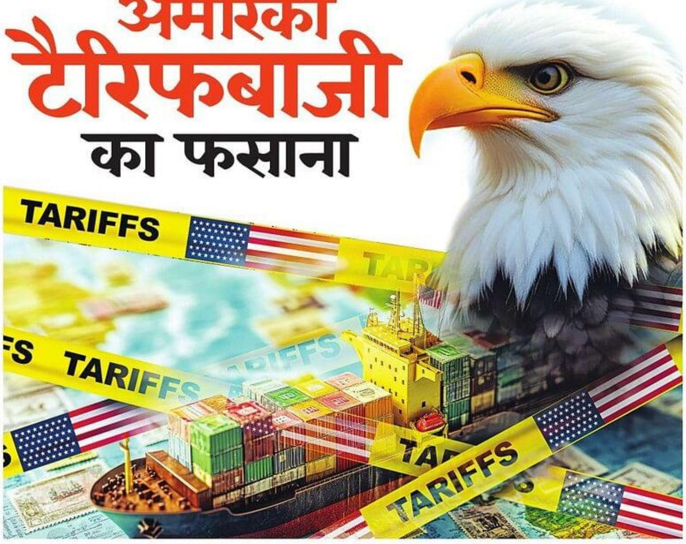

अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकेनले व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। वह हैरिसन की हार का बदला लेने वाले हैं। अमेरिकी उद्योग जगत मुतमइन है कि सीमा शुल्क के मामले में कुछ बड़ा होने वाला है। मैकनले ने रेसीप्रोकल (जैसे को तैसा) टैरिफ की बुनियाद रखी है।

अंशुमान तिवारी
वरिष्ठ पत्रकार

जिगर मुरादाबादी से माजरत के साथ- *एक लफ्ज-ए टैरिफ का इतना-सा फसाना है/ सिमटे तो सियासत है, फैले तो जमाना है।* दुनिया हैरां है। बौराए ट्रंप टैरिफ का चाबुक लिए जिस किसी को पीट रहे हैं। कनाडा, मेक्सिको, यूरोप और चीन तो पलट कर चढ़ लिए, भारत उन्हें मना रहा है। ट्रंप के पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और अब उस बाजार में माल बेचने के बदले वह वसूली कर रहे हैं। एक पूरी पीढ़ी ने ऐसा दौर न देखा होगा, जब पूरे ब्रह्मांड को आर्थिक उदारीकरण का ज्ञान देने वाला अमेरिका संरक्षणवादी बनकर दुनिया में ट्रेड जंग की यलगार कर रहा है। ट्रंप को अपने देश में महंगाई, बेरोजगारी और मंदी आने की तनिक भी चिंता नहीं है।

अगर आपको लगता है कि ट्रंप कुछ अनोखा कर रहे हैं, तो टाइम मशीन में बैठिए, क्योंकि हम आपको अमेरिकी इतिहास की पिछली सदियों का त्वरित सफर कराने वाले हैं, जहां आपको पता चलेगा कि यह टैरिफबाजी ट्रंप की घातक ईजाद नहीं है। यह तो अमेरिकी राजनीति की घुट्टी में मिला है। ट्रंप रिपब्लिकन हैं और उनके राजनीतिक पुरखों की सियायत का ईंट-गारा इसी संरक्षणवाद से बना था। इसलिए तो लोगों को ट्रंप में अमेरिकी इतिहास के टैरिफ सूरमा 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकेनले दिखते हैं। ट्रंप अपने इस पुरखे के बड़े मुरीद भी हैं। ट्रंप के टैरिफ उस्ताद यानी मरहूम विलियम मैकेनले से मिलने से पहले टाइम मशीन 19वीं सदी के अंत में आ गई है। यह 6 जुलाई, 1854 है। जैक्सन, मिशीगन में ओक के पेड़ों के झुरमुट में अमेरिकी सियासत को सदियों तक प्रभावित करने वाली रिपब्लिकन पार्टी की नींव रखी जा रही है। 10,000 लोगों के इस समूह को दो अभियानों ने जोड़ा है। एक है, गुलामी से मुक्ति और दूसरा, देशी उद्योगों को संरक्षण। अमेरिकी आकाश में विचरते हुए आप नए औद्योगीकरण की चहल-पहल महसूस कर सकते हैं। अलबत्ता राजनीतिक गलियारों में टहलते हुए आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन की कंपनियां तेजी से अमेरिका में आ रही हैं। देश के उद्योगपति घरेलू उद्योगों के संरक्षण और मुक्त व्यापार के बीच बंटे हैं। अखबारों में ब्रिटेन और अमेरिका के तनावपूर्ण आर्थिक अतीत का जिक्र है, जब नेपोलियन वाले युद्धों के दौरान ब्रिटेन में अमेरिका पर व्यापार प्रतिबंध लगाए थे। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने अपनी शुरुआत से ऊंचे टैरिफ यानी देसी बाजार को विदेशियों के लिए सीमित रखने की नीति को अपनी बुनियादी आर्थिक सोच का आधार बना लिया। अब हम वाशिंगटन में हैं। वक्त है 1861 का। आपके सामने जो शख्सियत दिख रही है, वह अब्राहम लिंकन हैं। जरा कांग्रेस की बैठक के भीतर चलिए। वहां मॉरिल टैरिफ ऐक्ट पास हो रहा है। इसका नामकरण कांगेस सदस्य जस्टिन मॉरिल के नाम पर हुआ। राष्ट्रपति लिंकन ऊंचे सीमा शुल्क यानी टैरिफ के बड़े पैरोकार हैं। वह नहीं चाहते हैं कि विदेशी सामान या पूंजी अमेरिका में आए। इस कानून के बाद पहली बार अमेरिका में सीमा शुल्कों का पूरा ढांचा बदल गया है। बीते दशकों में डेमोक्रेट्स ने शुल्क दरें कम रखी थीं, मगर रिपब्लिकन ऊंचे टैरिफ का राज ले आए हैं। अमेरिकी आर्थिक नीतियों की धुरी बदल गई है। अब टाइम मशीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ आचार्य विलियम मैकेनले की दौर की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका में घरेलू उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी का आधार बढ़ रहा है। अमेरिकी सियासत पर उद्योग का दबदबा उफान पर है। 1889 के चुनाव से अमेरिका में ऊंचे सीमा शुल्क की राजनीति गरमा गई थी। राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने सीमा शुल्क ऊंचे रखकर आयात महंगा करने की बुनियाद रख दी थी। डेमाक्रेट प्रत्याशी ग्रोवर क्लीवलैंड बाजार खोलने यानी सीमा शुल्क घटाने के हिमायती थे और वह जीत गए। यह 1897 है और अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकेनले व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। वह हैरिसन की हार का बदला लेने वाले हैं। अमेरिकी उद्योग जगत मुतमइन है कि सीमा शुल्क के मामले में कुछ बड़ा होने वाला है। मैकेनले ने अमेरिका में टैरिफ रिकॉर्ड 48 फीसदी तक बढ़ा दिए हैं। उनके कानून में सभी उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं। मैकेनले ने रेसीप्रोकल (जैसे को तैसा) टैरिफ की बुनियाद रखी है, यानी जो देश जितनी ड्यूटी लगाएगा, अमेरिका भी उसके उत्पादों पर उतना सीमा शुल्क लगाएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर जो रेसीप्रोकल टैरिफ थोपने जा रहे हैं, वह विलियम मैकेनले की रुल बुक से निकले हैं। ट्रंप भी अपने गुरु मैकेनले की तरह मानते हैं कि आयात महंगा करने से अमेरिका में अमीरी आएगी और रोजगार बढ़ेंगे। वह कहते हैं कि ऊंचे सीमा शुल्क के दौर में अमेरिका सबसे समृद्ध था। ट्रंप का इशारा 19वीं सदी के अंत से 20 वीं सदी के मध्य युग की तरफ है। मैकेनले के फैसले विवादित हो रहे हैं। अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, उपभोक्ता परेशान हैं, और उद्योगों की पौ-बारह है। भष्टाचार की खबरें सुर्खियों में हैं। मार्क ट्वेन के उपन्यास के बारे में सुना आपने? उन्होंने उस दौर को *गिल्डेड एज* कहा है और इसी नाम से उपन्यास लिखा है। यह सोना मढ़ी समृद्धि है, जिसके भीतर महंगाई और गरीबी भरी है। अब हम अमेरिका के जिस दौर में पहुंच रहे हैं, वह बड़ा कुख्यात है। यह 1929 का साल है। व्हाइट हाउस की कुर्सी पर रिपब्लिकन राष्ट्रपति हरबर्ट हूवर हैं। हूवर की पार्टी के दो सदस्यों स्मूट और हाउले द्वारा पेश नए कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अमेरिका में औसत सीमा शुल्क दर यानी टैरिफ 48 हो गए हैं। यह पहला मौका है, जब अमेरिका के 1028 अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर बताया है कि यह संरक्षणवाद अमेरिका को बर्बाद कर रहा है, देश में मंदी आ रही है, मगर हूवर ने किसी की नहीं सुनी। स्टॉक मार्केट के चीथड़े उड़ रहे हैं। दो साल के भीतर व्यापार करीब 60 फीसदी टूट गया। अमेरिका महामंदी में धंस गया है। इधर जर्मनी और जापान का उग्र राष्ट्रवाद दुनिया की सूरत बदलने जा रहा है।

टाइम मशीन
अतीत से सुनें वर्तमान की धड़कन ■ हर पखवाड़े

विलियम मैकेन्ले

टाइम मशीन अब 2025 के वाशिंगटन की तरफ निकल चुकी है। आपकी सीट पर रखे दस्तावेजों को पढ़ने से पता चलेगा कि सिविल वार से पहले विश्वयुद्ध तक अमेरिका में अधिकांश मौकों पर रिपब्लिकन सत्ता में थे। इसलिए सीमा शुल्क की दरें 50 फीसदी तक हो गई थीं। डगलस ए इर्विन की मशहूर किताब *क्लैशिंग ओवर कॉमर्स, ए हिस्ट्री ऑफ यूएस ट्रेड पॉलिसी* बताती है कि अमेरिका के इतिहास के पहले 70 वर्षों में राजनीति सीमा शुल्क बढ़ाने की हिमायती नहीं थी। राजस्व संभालने के लिए इनका इस्तेमाल होता था, मगर सिविल वार के बाद जब अमेरिका में राजनीतिक ताकत दक्षिण से निकल कर उत्तर में आ गई, तो देसी उद्योगों का संरक्षण सियासत चमकाने का फार्मूला हो गया।

हम वाशिंगटन में उतर रहे हैं। ट्रंप सीमा शुल्क का चाबुक फटकारते हुए अपने टैरिफ उस्ताद मैकेनले को याद कर रहे हैं और शेयर बाजार सीमा शुल्क बढ़ने के बाद अमेरिका में मंदी की आहट सुनाई दे रही है। हम फिर मिलते हैं, अगले सफर पर...

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

पुलस्त्यजी बोले, ‘त्रिविध भक्ति (मानस भक्ति, वाचिक भक्ति और कायिक भक्ति) के अलावा भी तीन प्रकार की भक्ति है-लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक भक्ति।

कैसे बना जाता है ब्रह्मभक्त

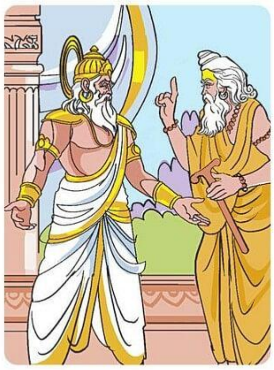

एक बार भीष्म ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, ‘ब्रह्मन! भक्ति कितने प्रकार की होती हैं और कैसी भक्ति करने से मनुष्य, ब्रह्मा का भक्त कहलाता है? मनुष्यों में किस तरह के लोग ब्रह्म-भक्त माने गए हैं?’ भीष्म का प्रश्न सुनकर पुलस्त्यजी बोले, ‘कुरुनंदन! शास्त्रों में तीन प्रकार की भक्ति बताई गई है-मानस भक्ति, वाचिक भक्ति और कायिक भक्ति। ध्यान धारण करके बुद्धि के द्वारा वेदों के अर्थ पर जब विचार किया जाता है, तो उसे मानस भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति से ब्रह्माजी प्रसन्न होते हैं। मंत्र जप, वेद-पाठ तथा आरण्यकों के जप के माध्यम से होने वाली भक्ति वाचिक भक्ति कहलाती है। और अंत में, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले व्रत, उपवास, नियम, कृच्छ्र, सांतपन तथा चांद्रायण आदि भिन्न-भिन्न प्रकार के व्रतों से, ब्रह्मकृच्छ्र नामक उपवास द्वारा एवं अन्य तरह के शुभ नियमों के अनुष्ठान से जब भगवान की आराधना की जाती है, तब उसको कायिक भक्ति कहते हैं। द्विजातियों में मुख्य रूप से ये तीन प्रकार की त्रिविध भक्ति बताई गई हैं।’ भीष्म ने अगला प्रश्न किया- ‘मैंने सुना है कि इन तीन के अलावा भक्ति के तीन भेद और हैं। क्या आप मुझे उनके विषय में बता सकते हैं?’

धूप आने दो

पुलस्त्यजी बोले, ‘आप सही कहते हैं। त्रिविध भक्ति के अलावा भी तीन प्रकार की भक्ति है-लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक भक्ति। अब मैं आपको इनके विषय में बताता हूं।

गाय के घी, दूध और दही, रन, दीप, कुश, जल, चंदन, माला, विविध धातुओं तथा पदार्थ; काले अगर की सुगंध से युक्त एवं घी और गूगुल से बने हुए धूप, आभूषण, सुवर्ण और रत्न आदि से निर्मित हार, नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकार के फल-मूलों के उपहार तथा नैवेद्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्माजी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से जो पूजा करता है, वह लौकिक भक्ति मानी गई है। सामान्य तौर पर मनुष्य इसी प्रकार से भक्ति करते हैं। इसके बाद, *ऋग्वेद, यजुर्वेद* तथा *सामवेद* के मंत्रों का जप और संहिताओं का अध्यापन आदि कर्म यदि ब्रह्माजी को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, तो ऐसी भक्ति को वैदिक भक्ति कहा गया है। इसके अतिरिक्त, वेद-मंत्रों के उच्चारण के साथ हविष्य की आहुति देकर जो यज्ञ-क्रिया आदि संपन्न की जाती है, उसे भी वैदिक भक्ति कहा जाता है। अमावस्या अथवा पूर्णिमा को जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञों में जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है तथा देवताओं को जो पुरोडाश और चरु अर्पण किए जाते हैं-ये सब भी वैदिक भक्ति के ही अंतर्गत आते हैं। इष्टि, धृति, यज्ञ-संबंधी सोमपान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, मेघ और सूर्य की उपासना के उद्देश्य से किए हुए जितने भी कर्म हैं, उन सबके देवता भी ब्रह्माजी ही हैं। भीष्म! अब मैं तुम्हें आध्यात्मिक भक्ति के बारे में बताता हूं। ब्रह्माजी की आध्यात्मिक भक्ति दो प्रकार की मानी गई है- एक सांख्यज भक्ति और दूसरी योगज भक्ति। इन दोनों में भी भेद होता है। प्रधान (मूल प्रकृति) आदि प्राकृत तत्व संख्या में चौबीस हैं। वे सब तत्व जड़ एवं भोग्य माने जाते हैं। उनका भोक्ता पुरुष पच्चीसवां तत्व है, और वह चेतन तत्व है। इस प्रकार संख्या पूर्वक प्रकृति और पुरुष के तत्व को ठीक-ठीक जान लेना ही सांख्यज भक्ति है। इसे सत्पुरुषों ने सांख्य-शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है। ब्रह्माजी की योगज भक्ति के अंतर्गत प्रतिदिन प्राणायाम के साथ ध्यान लगाना चाहिए, इंद्रियों के संयम का अभ्यास करना और समस्त इंद्रियों को अपने हृदय में धारण करके ब्रह्माजी का श्रद्धापूर्वक ध्यान करना चाहिए। हृदय के भीतर कमल है और यह माना जाता है कि उस कमल की कर्णिका पर ब्रह्माजी रहते हैं। वे रक्त-वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके नेत्र सुंदर हैं। उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं। यज्ञोपवीत उनकी कमर के ऊपर तक लटका हुआ है, उनके शरीर का वर्ण लाल है, चार भुजाएं शोभा पा रही हैं तथा हाथों में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। इस प्रकार के ध्यान की स्थिरता योगजन्य मानस सिद्धि है; ब्रह्माजी के प्रति इस प्रकार भक्ति करने को पराभक्ति माना गया है। जो मनुष्य भगवान ब्रह्माजी में पराभक्ति को धारण करता है, उसे शास्त्रों में ब्रह्म-भक्त कहते हैं।’

अव्यक्तात् प्रसृतं ज्ञानं ततो बुद्धिस्ततो मनः।
मनः श्रोत्रादिभिर्युक्तं शब्दादीन् साधु पश्यति।।

अर्थात अव्यक्त परमात्मा ज्ञान से प्रसारित हुआ है। ज्ञान से बुद्धि और बुद्धि से मन प्रकट हुआ है। वह मन ही श्रोत्र आदि इंद्रियों से युक्त होकर शब्द आदि विषयों का भलीभांति अनुभव करता है।

-शांतिपर्व 204/11
(प्रजापति मनु का महर्षि बृहस्पति को उपदेश)

प्रस्तुति : विवेक चौरसिया

खरीदारी का ऐसा जुनून किस काम का

जांसी डन

जब भी कुछ खरीदना हो, तो पहले सोचें कि वह चीज अगले तीस दिन में आपके कितने काम आने वाली है।

वसंत के आते ही मैंने मौसमी परंपरा के अनुसार, अपने सामान की छंटनी शुरू कर दी। सफाई के दौरान मेरे हाथ में बर्तनों का एक नया सेट पड़ गया, जिसका मैंने एक दशक से इस्तेमाल नहीं किया। घर में नया सामान भरने की इच्छा पर लगाम लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। स्थायित्व सलाहकार और *नो न्यू थिंग्स* की लेखिका एशली पाइपर कहती हैं, ‘जब आप शॉपिंग टैप बंद कर देते हैं, तब आप पैसा बचाते हैं और यह पर्यावरण के अनुकूल भी होता है।’ मैंने पाइपर और अन्य विशेषज्ञों से अनावश्यक चीजों की खरीदारी पर लगाम लगाने के कुछ तरीके पूछे, जो सुविधाजनक भी हों। पाइपर कहती हैं कि खरीदारी करना ‘सहज अनुभव’ हो गया है, एक बटन दबाते ही आप कोई भी चीज खरीद लेते हैं। इसे रोकने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन दुकानों से जुड़े खातों से अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी हटा दें, फिर पर्स में से क्रेडिट कार्ड को निकालकर रख दें और गहरी सांस लेते हुए सोचें कि क्या मुझे वाकई इस सामान की जरूरत है? इसके अलावा, दुकानदारों से आने वाले ईमेल और नोटिफिकेशनों को ब्लॉक कर दें।’ पाइपर लिखती हैं, ‘आप बनाना रिपब्लिक (राजनीतिक व आर्थिक रूप से अस्थिर देश) की आपातकाल स्थिति में तो हैं नहीं, जो इन संदेशों को अनुमति देते हैं, कि पता नहीं कब कौन-सी खबर आ जाए।’ *जेंटल : रेस्ट मोर, स्ट्रेस लेस एंड लिव द लाइफ यू एक्चुअली वांट* की लेखिका कर्टनी कार्वर कहती हैं कि उन्हें जब भी कुछ खरीदना होता है, तो सबसे पहले वह खुद से सवाल करती हैं कि क्या यह चीज आज या अगले तीस दिनों में काम आएगी? आदर्शों की नकल के संबंध में लोगों को आगाह करते हुए कार्वर अपना संस्मरण सुनाते हुए कहती हैं कि वह बचपन में *सेक्स एंड द सिटी* सीरियल की अभिनेत्री कैरी ब्रैडशॉ के सैंडलों से काफी प्रभावित थीं। उन्होंने ठीक वैसी ही सैंडल खरीदीं, जबकि वह उनको पहनकर ठीक से चल नहीं सकती थीं।’ एशली पाइपर कहती हैं कि जब भी महीने का कोई सामान खरीदना हो, तो अपने पुराने सामान की सूची उठाएं और मिलान करें कि कितनी चीजें बाकी हैं और अब वे ही चीजें खरीदें, जो बहुत जरूरी हों।

वह कहती हैं कि कभी-कभार उपयोग में आने वाली चीजों को किराये पर लेने का विचार करें। आयोजन विशेषज्ञ और ‘लाइफस्टाइल्ड’ की लेखक शीरा गिल कहती हैं कि शादी जैसे आयोजनों में वह दोस्तों से कपड़ों की अदला-बदली कर ही काम चला लेती हैं। अतः विशेषज्ञों का कहना है, जब किसी वस्तु को खरीदे बिना किराये पर लेकर या परिचित से मांगकर काम चल सकता है, तो फिर उसको बेवजह खरीदने की क्या जरूरत है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स से

अध्ययन कक्ष

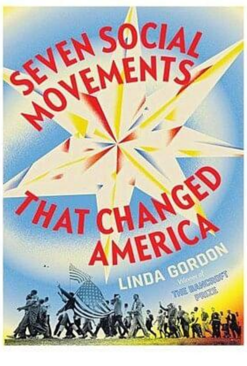

सेवन सोशल मूवमेंट्स दैट चेंज्ड अमेरिका

लेखिका : लिंडा गॉर्डन

प्रकाशक : लिवराइट
मूल्य : 3,049 रुपये
(हार्डकवर)

वे आंदोलन, जिन्होंने अमेरिका को बदला

लिंडा गॉर्डन की किताब में उन सात सामाजिक आंदोलनों पर विचार किया गया है, जिन्होंने अमेरिका को बदल दिया। उनके लेखन में कोई सामान्य सूत्र ढूंढना तो मुश्किल है, लेकिन उन्होंने इन आंदोलनों में नेतृत्व के ऐसे सूत्र जरूर खोज निकाले, जो आज भी प्रासंगिक हैं।

जब सत्ता के शीर्ष से एक विशिष्ट सोच के साथ कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो उसकी ताकत को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अमेरिका में फिलहाल यही हो रहा है। लेकिन इन स्थितियों को समझने क लिए उस सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन को समझना होगा, जिसकी वजह से ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) आंदोलन के ध्वजवाहक राष्ट्रपति ट्रंप का उत्थान हुआ। इतिहासकार लिंडा गॉर्डन ने अपनी *सेवन सोशल मूवमेंट्स दैट चेंज्ड अमेरिका* पुस्तक में लिखा है, ‘सामाजिक आंदोलनों ने दुनिया को उतनी ही बार और उतनी ही गहराई से बदला है, जितना कि युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं और चुनावों ने।’ ये आंदोलन लोकतंत्र से जुड़े होते हैं, क्योंकि वे जन राजनीतिक शक्ति का उत्पाद हैं और इसके प्रसार में एक कारक भी हैं। उनकी पुस्तक के एक अध्याय में 1920 के दशक में कु क्लुक्स क्लान (केकेके) के पुनरुत्थान का वर्णन है, जिसके मध्यवर्गीय सदस्यों ने कट्टरता को मुख्यधारा में ला दिया था। पुस्तक में उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध के सेटलमेंट हाउस आंदोलन से लेकर, जिसका उद्देश्य गरीबी और असमानता को कम करना था, बीसवीं सदी के महिला मुक्ति संघर्ष तक फैले हैं, जो अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन था। इस बीच वह 1920 के दशक के क्लान के उत्थान और पतन; वृद्धावस्था पेंशन के लिए अभियान; महामंदी के दौरान बेरोजगारों के बीच सक्रियता का उभार; जिम क्रो अलबामा में मोंटगोमरी बस का बायकॉट; और सीजर चावेज के नेतृत्व में यूनाइटेड फार्म वर्कर्स यूनियन की भी पड़ताल करती हैं। उन्होंने सामाजिक आंदोलनों का विविध उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो बड़े पैमाने पर, सहभागितापूर्ण सक्रियता से संचालित होते हैं और चुनावी राजनीति से परे, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उद्देश्य से चलाए गए, जिससे लगता है कि सामाजिक आंदोलन की उनकी परिभाषा अनिवार्य रूप से अस्पष्ट है। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण गॉर्डन के लिए सामान्य सूत्र तलाशना मुश्किल होता है, लेकिन वह कुछ सूत्र ढूंढ ही लेती है। जैसे, करिश्माई नेतृत्व अक्सर दोधारी होता है। यह एक प्रेरक शक्ति हो सकती है, जो आंदोलन को महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ-साथ दिशा भी देती है। वह फ्रांसिस टाउनसेंड नामक एक डॉक्टर की अजीब कहानी बताती हैं, जिन्होंने 67 वर्ष की आयु में ऐसा आंदोलन खड़ा किया, जिसे गॉर्डन ‘1930 के दशक का सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन’ कहती हैं। बुजुर्गों की पेंशन के लिए टाउनसेंड का आह्वान 1935 के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के रूप में परिणत हुआ। अपने अनुभव से गॉर्डन याद करती हैं कि कैसे ‘एक-दूसरे की भावनात्मक जरूरतों’ का जवाब देने की प्रतिबद्धता कभी-कभी ‘कुशल निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर सकती है।’ ऐसी प्रतिबद्धताओं के पीछे महान प्रेरणा थी- इच्छित दुनिया का निर्माण करना था। इसके अलावा, गॉर्डन ने जिन दूसरी लहर की नारीवादियों के बारे में लिखा है, वे अब भी अपने कुछ विचारों को अमेरिकी मुख्यधारा में लाने में प्रभावी रही हैं। गॉर्डन लिखती हैं, ‘युवा पीढ़ी की महिलाएं आश्चर्यचकित और स्तब्ध हो जाती हैं, जब उन्हें उन कानूनों और प्रथाओं के बारे में पता चलता है, जो आधी सदी पहले महिलाओं के जीवन को सीमित कर रहे थे।’

अभियान

amarujala.com
अमर उजाला

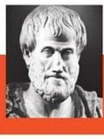

“जो लोग आलोचनाओं से बचना चाहते हैं, उनके लिए एकमात्र तरीका है कुछ भी काम नहीं करना। अगर हम कोई काम करेंगे तो आलोचना तो होगी। - अरस्तु

Hindi@mithelesh
▪ मिथिलेश बारिया

गोल चबूतरा

पंखा अब धीरे-धीरे आवाजें करने लगा है,
चलो इस घर की खामोशी से,
किसी को शिकायत तो है...

कौन कहता है बचपन पर किसी का जोर नहीं,
मैंने लोहे की जंजीरों से बंधी,
बच्चों की साइकिलें देखी हैं...

रानी ने बेच दिया था अपना राज्य

झरोखा

14 मार्च, 1489 का दिन इतिहास में एक अनोखी घटना के लिए दर्ज है। इस दिन साइप्रस की कैथरीन कॉर्नारो ने अपना राज्य वेनिस गणराज्य को बेच दिया था। कैथरीन कॉर्नारो कुलीन परिवार की थीं और 1474 में साइप्रस की रानी बनीं। पति किंग जेम्स द्वितीय की मृत्यु के बाद साइप्रस की सत्ता उनके हाथ में आई। उनके गद्दी पर बैठते ही वेनिस गणराज्य ने साइप्रस पर नियंत्रण पाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। वेनिस ने कैथरीन को उनके ही राज्य में अलग-थलग कर दिया और धीरे-धीरे उनकी प्रशासनिक शक्तियों पर भी कब्जा कर लिया। वह वेनिस गणराज्य के सामने पूरी तरह बेबस हो गईं। उनके पास खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, सिवाय अपने राज्य वेनिस को सौंपने के। इस तरह 1489 में कैथरीन को औपचारिक रूप से राज्य का नियंत्रण वेनिस को सौंपना पड़ा। कैथरीन को वेनिस लाया गया और असोलो नामक एक छोटा क्षेत्र रहने के लिए दिया गया। उन्होंने शेष जीवन वहीं बिताया। वेनिस ने साइप्रस को अपने व्यापारिक और नौसैनिक केंद्र के रूप में विकसित किया। हालांकि 1571 में ओटोमन साम्राज्य ने वेनिस से साइप्रस को छीन लिया और इस तरह वेनिस का आधिपत्य खत्म हो गया।

▪ संजय अधिकारी, अल्मोड़ा

चुनावों में यमुना की सफाई को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं और फिर उनको भुला दिया जाता है। वास्तव में यमुना को स्वच्छ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस, मजबूत इच्छाशक्ति के साथ एक ईमानदार पहल करने की जरूरत है।

यमुना को चाहिए ईमानदार प्रयास

समझनी होगी जिम्मेदारी

चिट्ठी 1

दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार यमुना की सफाई को लेकर कुछ ज्यादा ही सरगर्मी देखने को मिली। हर पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया। इसका अच्छा परिणाम यह रहा कि सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने यमुना की सफाई को चुनौती के तौर पर लिया है।

खासकर विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के विरोध करने के मिजाज को देखते हुए भाजपा इस मसले पर कोई कोताही नहीं बरतना चाहेगी, बल्कि जल्द से जल्द इसे पूरा करेगी। इसके शुरुआती संकेत दिखने भी लगे हैं। अब तक यमुना से 1300 मीट्रिक टन गाद और कचरा निकाला जा चुका है।

वास्तव में, देखा जाए तो यमुना की सफाई इतनी भी मुश्किल नहीं है, जितना सरकारों ने बना दिया। दिल्ली में यमुना की गंदगी का मुख्य कारण उसमें मिलने वाले 22 बड़े नाले हैं। वे हमेशा गंदगी से अटे रहते हैं। सरकार को सबसे पहले इनसे निपटना होगा। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। दिल्ली में कई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बंद पड़े हैं। इनको चालू कर क्षमता वृद्धि करना और कुछ नए एसटीपी स्थापित करना सरकार के एजेंडे में है। इसके बाद दिल्ली में एसटीपी की क्षमता उतनी ही हो जाएगी, जितनी 22 नालों से गंदगी निकलती है। प्रत्येक नाले को एसटीपी से जोड़ा जाएगा। ये सब काम दो साल में आराम से किए जा सकते हैं।

जिस तरह पिछली सरकार को यमुना के मुद्दे पर छीछालेदर झेलनी पड़ी और चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा, मौजूदा सरकार यह गलती नहीं दोहराना चाहेगी। एक बात साफ है कि अन्य मुद्दों पर सरकार जैसे भी काम करे, लेकिन आने वाले दिनों में यमुना के मुद्दे पर काफी सुधार देखने को मिल सकता है।

▪ एमएम राजावत, शाजापुर

स्क्रीन की चमक तले 'अंधेरा'

चिट्ठी 2

मोबाइल की चमक हमें एक ऐसे अंधेरे समुद्र में ले जा रही है, जहां रिश्तों की गर्माहट खो जाती है और अनजान भीड़ हमें घेर लेती है। घर में सब एक छत के नीचे होते हुए भी एक-दूसरे से मीलों दूर हैं। हर कोई मोबाइल स्क्रीन की आभासी दुनिया में गुम है, जहां दिखाव करने की होड़ लगी हुई है, लेकिन अपनापन नहीं है।

जो तकनीक हमें जोड़ने के लिए बनी थी, लोगों के बीच की दूरियां मिटाने के लिए आई थी, हकीकत में वह रिश्तों को निगल रही है। दिलों के बीच ऐसी खाइयां बन गई हैं, जिनको पाटना अब किसी पहाड़ को हिलाने जैसा हो गया है। कभी घर वह स्थान होता था, जहां शामें हंसी-खुशी से गूंजती थीं। माता-पिता बच्चों के साथ बैठकर दिनभर की बातें करते थे, दादा-दादी की कहानियां सबको जोड़ती थीं, हर पल एक खुशनुमा अहसास होता था। अब माता-पिता हों या बच्चे, सब फोन में मशगूल हैं। कोई सोशल मीडिया चला रहा है तो कोई गेम में मस्त है। हर कोई बनावटी जिंदगी जी रहा है और सामने खड़ा इन्सान बुत बन चुका है। बातें करना तो बेईमानी हो गई है।

बुजुर्ग तो बस कोने में बैठे एक उम्मीद बनकर रह गए हैं कि कोई उनसे दो पल बात कर लेगा, लेकिन उनकी आवाज नोटिफिकेशन की चीख में दब चुकी है। उनकी जिंदगी के सबक मोबाइल के आगे गुम हो गए हैं। सोशल मीडिया पर हंसते-मुस्कुराते चेहरे हैं और घर के भीतर सन्नाटा पसरा रहता है। हमें वास्तविकता को समझना होगा।

▪ प्रो. आरके जैन, बड़वानी

नशे में बर्बाद होती युवा पीढ़ी

चिट्ठी 3

होली से पहले पकड़ी गई ड्रग्स से पता चलता है कि देश किस तरह ड्रग्स की गिरफ्त में आ चुका है। किस तरह हमारा युवा नशे में लड़खड़ा रहा है।

रंगपर्व होली पर तो शराब, गांजा, भांग जैसे नशीले पदार्थों के सेवन को जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया गया है। नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ने से आपराधिक गतिविधियों में भी इजाफा हो रहा है। नशे के चलते मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, बंगलूरू जैसे महानगरों में अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है।

दूसरी तरफ सूखे नशे की लत में पड़कर स्कूल-कॉलेज के छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। पिछले कुछ माह में मुंबई नारकोटिक्स इकाई ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर बड़ी मात्रा में चरस, कोकीन, गांजा, स्मैक की खेप बरामद की है। देश में बड़े पैमाने पर ड्रग्स तस्करी का कारोबार हो रहा है। बड़े-बड़े रिसॉर्ट, पिकनिक स्पॉट, मुख्य सड़कों के आसपास ढाबों और स्कूल-कॉलेज परिसर के आसपास इसकी आपूर्ति ज्यादा होती है।

सवाल यह भी है कि इतने बड़े पैमाने पर ये सब हो रहा है और हमारा सुरक्षा तंत्र कुछ नहीं कर पा रहा है। इतने राज्यों की पुलिस है, अलग-अलग एजेंसिया हैं। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। यह देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसकी चपेट में आकर परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आर्थिक चपत लग रही है। यह देश की सुरक्षा के लिए भी चिंताजनक है। ड्रग्स तस्करी की कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने होंगे।

▪ संजीव ठाकुर, रायपुर

इनकी चिट्ठियां भी सराहनीय रहीं | बलिया से राहुल उपाध्याय, रुड़की से डॉ. श्रीगोपाल नारसन, कुरुक्षेत्र से मुनीष भाटिया, पिथौरागढ़ से सुनील कुमार महला, जालंधर से राजेश कुमार चौहान, गाजियाबाद से ललित शंकर, दिल्ली से योगेश कुमार गोयल, आजमगढ़ से अवनीश कुमार गुप्ता, शिवपुरी से प्रमोद भार्गव, पटना से मुकेश कुमार मनन

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

'रेसट्रैक प्लाया' में पत्थर चलते हैं...

पत्थर, इन्सानों की तरह खिसकते हैं और पीछे लकीरें भी छोड़ जाते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है।

दुनियाभर में कई रहस्यमयी स्थान हैं, लेकिन अमेरिका में कैलिफोर्निया और नेवादा के बीच स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क की 'रेसट्रैक प्लाया' झील खुद-ब-खुद चलने वाले पत्थरों के कारण सबसे अनोखी और आश्चर्यजनक है। यहां पत्थर बिना किसी बाहरी सहायता के धीरे-धीरे खिसकते रहते हैं और अपने पीछे लंबी लकीरें छोड़ देते हैं, जो देखने पर हर किसी को अचंभित कर देते हैं।

डेथ वैली एक विशाल और शुष्क रेगिस्तान है, जहां बारिश बहुत कम होती है। 'रेसट्रैक प्लाया' इसी रेगिस्तान में स्थित एक सूखी झील है, जहां ये रहस्यमयी पत्थर पाए जाते हैं। इन पत्थरों का वजन दो-तीन किलोग्राम से लेकर तीन कुंतल तक होता है। हालांकि किसी ने भी प्रत्यक्ष रूप से पत्थरों को चलते हुए नहीं देखा है, लेकिन उनके पीछे बनी लंबी लकीरों से साबित होता है कि पत्थर खिसकते हैं।

ये लकीरें कभी सीधी, कभी टेढ़ी-मेढ़ी और कभी घुमावदार होती हैं। इसको लेकर कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें चुंबकीय प्रभाव, भूकंप और अदृश्य ऊर्जा आदि शामिल हैं, लेकिन किसी का भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। 2014 में वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोगों और समय-समय पर किए गए अवलोकनों के आधार पर कुछ हद तक वाजिब कारण खोजा। उनके अनुसार, सर्दियों के दौरान झील के तल पर हल्की बर्फ की परत बनती है। जब सूरज निकलता है तो बर्फ पिघलकर पतली स्लैब में बदल जाती है। हल्की हवा और पानी के बहाव से बर्फ खिसकने लगती है, जिससे पत्थर भी साथ में धीरे-धीरे सरकते हैं। हालांकि यह सिद्धांत अभी पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है। विज्ञान भले ही पत्थरों के खिसकने को लेकर किसी ठोस निष्कर्ष पर न पहुंचा हो, लेकिन यह रहस्य पर्यटकों को खूब भाता है। यहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं।

▪ अलका चौधरी, जींद

अभिनय और 'दर्शन' का संगम

1931 में जब महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू लंदन में थे तो मशहूर हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन (बाएं बैठे हुए) उनसे मिले थे।

▪ पीयूष गुलाटी, चंडीगढ़

छायानट

गाने का सेट बनाने में लग गए दो साल

1960 में आई फिल्म 'मुगल-ए-आजम' को बनने में 14 वर्ष का समय लगा। फिल्म के एक गाने का सेट बनने में ही दो साल लग गए थे। गाना था- 'जब प्यार किया तो डरना क्या'। गाने में जब अभिनेत्री मधुबाला नाचती हैं तो महल में लगे सभी शीशों में दिखती हैं, लेकिन इसे फिल्माना आसान नहीं था। एक समय तो इस सीन को क्रिएट करना लगभग नामुमकिन-सा हो गया था। हॉलीवुड से भी विशेषज्ञों को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। मामला 15 लाख रुपये की लागत से तैयार शीशमहल को तुड़वाने तक पहुंच गया, लेकिन फिर सिनेमेटोग्राफर आरडी माथुर ने एक तरकीब निकाली। दरअसल, कैमरा लगाते ही उसकी रोशनी शीशों से टकरा जाती थी। इसे रोकने के लिए रिफ्लेक्टर्स लगाए गए, लेकिन उन पर लाइट पड़ती तो आंखें चौंधिया जाती थीं और शूटिंग करना मुश्किल हो जाता था। माथुर को कैमरे से सेट पर एक ऐसा कोना दिखा, जहां लाइट बाउंस हो रही थी। वहां से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। फिर रंग-बिरंगे शीशों में अनारकली बनीं मधुबाला ही घूमती नजर आईं और यह हिंदी सिनेमा में आइकॉनिक सीन बन गया।

▪ सुरभि गौतम, आगरा

ये दुनिया एक सौदा नहीं है

ट्रंप चीन और भारत के बीच बिना किसी अंतर के व्यापार करने के लिए तैयार हैं। लेन-देन और सौदेबाजी करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में यह दुनिया कहां जाएगी?

पी चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय मंत्री

मैग्ना कार्टा को अधिकारों का पहला चार्टर माना जाता है, जिस पर 1215 में ब्रिटेन के राजा ने सहमति दी थी। आइसलैंड में 1262 में स्थापित 'अलथिंग' को दुनिया की पहली संसद माना जाता है। 1341 ई. में प्रथम द्विसदनीय विधायिका का इतिहास ब्रिटेन में मिलता है। किसी देश का पहला लिखित संविधान 1600 में सैन मैरिनो गणराज्य का था। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का श्रेय फ्रांसीसी दार्शनिक मांटेस्क्यू द्वारा 1748 में प्रकाशित 'स्पिरिट ऑफ लॉज' को दिया जाता है। किसी देश की न्यायिक शक्ति पहली बार 24 सितंबर, 1789 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में निहित की गई थी।

खतरे में अच्छाई

सांविधानिक इतिहास के सबसे अच्छे सबक अमेरिकी संविधान में सन्निहित थे और इसे भारत के संविधान निर्माताओं सहित कई देशों द्वारा अपनाया गया है। स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक ऐसी नई विश्व व्यवस्था बनाने का वादा किया, जो युद्ध, गरीबी और बीमारी को खत्म कर देगी। इसमें वे काफी हद तक सफल भी हुए। हालांकि नई व्यवस्था स्थानीय युद्धों को समाप्त नहीं कर सकी, लेकिन दुनिया ने इससे पहले आठ दशकों में अभूतपूर्व विकास और व्यापक समृद्धि तथा शांति भी कभी नहीं देखी थी। ऐसे में विशेष रूप से 20 जनवरी, 2025 के बाद के घटनाक्रम, जो दुनिया को एक स्वार्थी और सत्तावादी ढांचे में पुनः ढलने की धमकी देते हैं, उनके लिए एक बड़ा झटका है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का पद अपनी विशाल शक्तियों के कारण अद्वितीय है। इसकी पुष्टि यह तथ्य भी करता है कि अमेरिका विश्व का सबसे धनी देश है। इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए विलियम मैककिनले ने संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र का विस्तार किया और प्यूर्टो रिको, गुआम, फिलीपींस तथा हवाई पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाते हुए विदेशियों तथा असंतुष्टों को हिरासत में लेने या उन्हें निर्वासित करने के लिए कार्यकारी आदेशों का उपयोग किया। बराक ओबामा ने युद्ध शक्ति अधिनियम, 1973 के तहत अमेरिकी कांग्रेस की अनुमति के बिना ही लीबिया में युद्ध शुरू कर दिया। अन्य राष्ट्रपतियों ने भी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गैर-सांविधानिक काम किए और बच निकले।

विश्व व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करना

संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप से ज्यादा किसी ने भी ऐसा नहीं किया। आठ दशकों तक अनेक तरह के दुस्साहस के बाद भी अमेरिका को स्वतंत्र, लोकतांत्रिक देशों का नेता और विश्व व्यवस्था का संरक्षक माना जाता रहा। शांति, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक वैश्विक संस्थाओं की स्थापना की गई। हालांकि ट्रंप के नेतृत्व में मात्र आठ सप्ताह में ही अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) और संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को आर्थिक मदद बंद करने या रोकने की धमकी दी है। ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) को बंद कर दिया है और दुनियाभर में दर्जनों कार्यक्रमों को रोक दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि वह नाटो और यूरोपीय सहयोगियों को भी छोड़ सकते हैं। घरेलू स्तर पर दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के दबाव में उन्होंने अमेरिकी सरकार के ढांचे को खत्म करना शुरू कर दिया है। हजारों लोगों की छंटनी कर दी है और शिक्षा विभाग को भी वह बंद करने वाले हैं।

ट्रंप के नेतृत्व में दोस्त (राष्ट्रपति जेलेंस्की) दुश्मन बन गए हैं और दुश्मन (राष्ट्रपति पुतिन) दोस्त बन गए हैं। उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के साथ ही ग्रीनलैंड को खुले तौर पर यह कहते हुए संयुत राज्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है कि "हम इसे किसी न किसी तरह से हासिल कर लेंगे।"

ट्रंप शत्रु (चीन) और मित्र (भारत) के बीच बिना किसी अंतर के व्यापार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि "मैंने अपनी पूरी जिंदगी सौदे ही किए हैं।" राष्ट्रपति जेलेंस्की को आमंत्रित कर अपमानित करने और बाहर निकालने के बाद उन्हें तब वापस बुलाया, "जब वह संभवतः महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए।" ट्रंप ने इसे 'बदला' कहा।

दुनिया पर छाए काले बादल

लेन-देन और सौदेबाजी करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में दुनिया कहां जाएगी? और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं?

दुनिया के लिए ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग एक तानाशाह ग्रुप बना लेंगे और क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे। अमेरिका की नजर पनामा नहर, कनाडा, ग्रीनलैंड और गाजा पर है, रूस पहले ही क्रीमिया, अब्खाजिया और दक्षिण ओसेशिया पर कब्जा कर चुका है और अब वह यूक्रेन तथा शायद जॉर्जिया चाहता है, जबकि तिब्बत और हांगकांग को जबरन अपने में मिलाने के बाद चीन की ताइवान तथा भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों के अलावा दक्षिण चीन सागर एवं उसके द्वीपों पर कब्जा करने की इच्छा किसी से छिपी नहीं है। ये तीनों देश दुनिया को अपने प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित करेंगे और उनकी खनिज संपदाओं पर अपना प्रभाव जमाएंगे। भारत, चीन के सामने कमजोर होगा और न तो अमेरिका और न ही रूस इसमें मदद करेगा। भारत को अमेरिका से अधिक से अधिक सैन्य उपकरणों को खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा। भारत को अपने हित साधने के लिए अमेरिका से कम टैरिफ पर अधिक सामान आयात करने पड़ेंगे। अमेरिका और रूस के बीच तनाव कम होने का मतलब यह होगा कि रूसी तेल अब सस्ते दामों पर उपलब्ध नहीं होगा। भारत को ब्रिक्स को कम महत्व देने के लिए मनाया जा सकता है। क्वाड को चीन का शत्रु नहीं माना जाएगा। अपने साझा संरक्षक यूएस के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश आपसी संबंधों को और बेहतर बनाएंगे। अगर ट्रंप टैरिफ की लड़ाई शुरू करते हैं तो यह नियम के आधार पर चलने वाले विश्व व्यापार को उलट देगा और भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। जर्मनी और फ्रांस की ही तरह भारत को भी अपनी रक्षा करनी होगी।

प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा महसूस हो सकता है कि ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती भारत को मुश्किलों से उबार लेगी, लेकिन ऐसी संभावना न के बराबर ही है। ट्रंप स्वार्थी और अहंकारी, दोनों हैं। अगर उनकी वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह भी हो जाए तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है।

Licensed by The Indian Express Limited

प्रकृति का राग पतझड़ हमारे लिए एक सीख

डॉ. महेश परिमल

खुला आकाश

पतझड़ एक विचार है- समय का, परिवर्तन का, जीवन का, संघर्ष का। जब पेड़ से पूरे पत्ते नाता तोड़ देते हैं, तब पेड़ कितना कुरूप दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर कोंपलें फूटती हैं और पेड़ हरा-भरा हो जाता है।

इन दिनों हम सब रास्ते में गिरे सूखे पत्तों को देख रहे होंगे। हमारा मस्तिष्क कहता है कि अब मौसम पतझड़ का है। दिन की धूप दिनों-दिन तीखी होती जा रही है। हवाएं तेज चलने लगी हैं, पत्तों की सरसराहट भी कुछ परिवर्तन का आभास देती है। बंद खिड़की के पास सोने से हवा की ध्वनि भी कुछ नएपन का संकेत देने लगी है।

इन सबका आशय यही है कि प्रकृति अपना बाना बदलने लगी है। इन्सानों की भाषा में कहा जा सकता है कि प्रकृति अपना चोला बदलने लगी है, पर प्रकृति के इस परिवर्तन पर यदि थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए तो हम समझेंगे कि यह प्रकृति के विश्राम का क्षण है। कुछ नया करने के पहले इन्सान भी कुछ सोचता है। प्रकृति भी इस प्रयास में है, क्योंकि उसके पास अब भी हमें देने के लिए बहुत कुछ है। यह हम पर निर्भर करता है कि प्रकृति से क्या लें और कितना लें?

पतझड़ यानी उन पुराने पत्तों का शाखा से नाता तोड़ना, जो अब पीले होकर कुम्हलाने लगे थे। उनमें जीनव रस नहीं था। पूरे साल उन्होंने पेड़ का साथ दिया। अब वे अपनी भूमिका समाप्त कर चल पड़े हैं धरतीपुत्र बन खाद बनने को। यहां भी उन्होंने उदारता से पल्ला नहीं झाडा, वे धरती पर जाकर भी उसे उर्वरा बनाने में लग जाएंगे। ऐसा महान संकल्प लेकर वे आए और हमें छोटा-सा संदेश देकर चले गए।

पतझड़ एक विचार है- समय का, परिवर्तन का, जीवन का, संघर्ष का। जब पेड़ से पूरे पत्ते नाता तोड़ देते हैं, तब पेड़ कितना कुरूप दिखाई देता है। लोग उसकी ओर देखकर आहें भरते हैं कि कभी यह भी हरा था। इसके पत्तों की सरसराहट कितनी भली लगती थी। इसकी छांव में हमने खूब मौज-मस्ती की है, पर अब इसमें वह बात कहां? पेड़ पर इस तरह के कटाक्ष करने वालों, थोड़ा ठहर जाओ। अभी पेड़ बाहरी विश्राम के क्षणों में है। उसने सीख देने के लिए पत्तों को अपने से दूर किया है। आज पत्तेविहीन हो गया तो आपने जरा भी देर नहीं की। अभी तो आपने इसका बाहरी स्वरूप ही देखा है। कुछ दिन बाद ही इसमें नए पत्तों की कोंपलें फूटेंगी, तब देखना। कोमल, नरम, मुलायम पत्तों की बहार। वे आते रहेंगे पूरी मस्ती के साथ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब पेड़ पूरी तरह से हरियाली से ढक गया।

हमारे जीवन में भी पतझड़ आ रहा है, गिरते विचारों का और लगातार आ रहा है। हमारे विचार देश, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा और परोपकार विहीन हैं। यदि है तो केवल स्वार्थ, धन-लिप्सा, मक्कारी, धूर्तता, बेईमानी, झूठ-फरेब, लूट-खसोट। इन विसंगतियों के साथ हम कुछ भी कर रहे हैं। कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। अब पेड़ तो हैं नहीं, इसलिए इस पतझड़ में मनुष्य के विचार गिरने लगे हैं। इस मौसम के बाद पेड़ों की रंगत तो बदल जाती है, लेकिन इन्सानों की नहीं बदलती। उसे तो पुराने विचारों ने इस तरह जकड़ लिया है कि नए विचारों का प्रवेश ही बंद हो गया है। जब तक पुराने विचारों का खात्मा नहीं होगा, तब तक जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा।

सौदागर से सौदागरी

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

> दुनिया को संचालित करने के लिए, सत्तावादी शासक एक 'क्लब' बनाएंगे- ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग। वे अपने मनचाहे इलाकों को हड़प लेंगे। तीनों देश, दुनिया को 'प्रभाव के क्षेत्रों' में विभाजित करने और संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में संसाधनों का दोहन करने का प्रयास करेंगे। भारत, चीन के सामने कमजोर होगा और न तो अमेरिका उसकी मदद करेगा, और न ही रूस।

माना जाता है कि अधिकारों का पहला चार्टर 1215 में इंग्लैंड के सम्राट द्वारा स्वीकृत 'मैग्ना कार्टा' है। यह भी माना जाता है कि दुनिया की पहली संसद आइसलैंड में 1262 में स्थापित 'अलथिंग' थी। ब्रिटेन में पहली द्विसदनीय विधायिका की तलाश 1341 में हुई थी। दुनिया का पहला लिखित संविधान 1600 में सैन मैरिनो गणराज्य द्वारा तैयार किया गया था। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का श्रेय फ्रांसीसी दार्शनिक मांटेस्क्यू द्वारा 1748 में प्रकाशित 'कानून की भावना' को दिया जाता है। किसी देश की न्यायिक शक्ति पहली बार 24 सितंबर, 1789 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में निहित की गई थी।

खतरे में अच्छाई

सांविधानिक इतिहास के महान और बेहतरीन पाठ अमेरिकी संविधान में निहित हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं सहित अनेक देशों ने इनकी नकल की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देशों ने एक नई विश्व-व्यवस्था बनाने का वादा किया था, जिसमें युद्ध, गरीबी और बीमारी को समाप्त करने का संकल्प था। इसमें वे काफी हद तक सफल भी हुए। हालांकि नई व्यवस्था स्थानीय युद्धों को समाप्त नहीं कर सकी, मगर इससे पहले, बीते आठ दशकों की तुलना में, दुनिया ने ऐसा अमन, अभूतपूर्व विकास और व्यापक समृद्धि कभी नहीं देखी थी।

इसलिए, यह एक बड़ा झटका है कि पिछले तीन वर्षों के घटनाक्रम- और, खासकर, 20 जनवरी, 2025 के बाद के घटनाक्रम- दुनिया को एक स्वार्थी और सत्तावादी सांचे में ढालने की धौंस देते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय अपनी विशाल, निर्दिष्ट और अनिर्दिष्ट शक्तियों के कारण अद्वितीय है, इस तथ्य से यह जाहिर होता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है। उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विलियम मैककिनले ने संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र का विस्तार किया और प्यूर्टो रिको, गुआम, फिलीपींस और हवाई पर कब्जा कर लिया। वुडरो विल्सन और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने स्वतंत्र अभिव्यक्ति को दबा दिया और विदेशियों तथा विद्रोहियों को हिरासत में लेने या निर्वासित करने के लिए कार्यकारी आदेशों का इस्तेमाल किया। बराक ओबामा ने युद्ध शक्ति अधिनियम, 1973 के तहत अमेरिकी कांग्रेस की अनुमति के बिना, लीबिया में युद्ध शुरू कर दिया था। अन्य राष्ट्रपतियों ने अपने कार्यालय की सीमाओं को जांचा-परखा और स्पष्ट रूप से वे असंवैधानिक कृत्यों से बच निकले।

विश्व व्यवस्था पर प्रहार

संयुक्त राज्य अमेरिका के सैंतालीसवें राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप से ज्यादा, किसी राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल नहीं किया। आठ दशकों तक, विचलन और दुस्साहस के बावजूद, अमेरिका को स्वतंत्र, लोकतांत्रिक देशों का अगुआ और विश्व व्यवस्था का संरक्षक माना जाता था। शांति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कई वैश्विक संस्थान बनाए गए। हालांकि, ट्रंप साहब के सत्ता संभालने के बमुश्किल आठ हफ्तों के भीतर, अमेरिका ने डब्लूएचओ को त्याग दिया और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी), संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को वित्तीय मदद देने से इनकार करने या रोकने की धमकी दी है। ट्रंप साहब ने यूएसएड को बंद कर दिया और दुनिया भर में दर्जनों कार्यक्रमों को रोक दिया है। वे नाटो और यूरोपीय सहयोगियों को छोड़ सकते हैं।

घरेलू स्तर पर, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के उकसावे पर, ट्रंप साहब ने अमेरिकी सरकार के ढांचे को खत्म करना शुरू कर दिया है। उन्होंने हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया है और शिक्षा विभाग को बंद करने की आशंका है।

ट्रंप साहब के शासन में, दोस्त दुश्मन बन गए हैं (राष्ट्रपति जेलेंस्की) और दुश्मन दोस्त बन सकते हैं (राष्ट्रपति पुतिन)। ट्रंप कनाडा को अमेरिका का इक्यावनवां राज्य बनाना चाहते हैं और उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल होने के लिए खुला आमंत्रण दिया है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा है कि 'हम इसे किसी न किसी तरह हासिल करेंगे'।

ट्रंप साहब ने दुश्मन (चीन) और दोस्त (भारत) के बीच कोई अंतर नहीं रखा है, और वे हर तरह के सौदे करने को तैयार हैं। 'मैंने अपनी पूरी जिंदगी सौदेबाजी की है', उन्होंने शेखी बघारते हुए कहा था और राष्ट्रपति जेलेंस्की को आमंत्रित करने, अपमानित करने और बाहर निकालने के बाद, उन्होंने उन्हें वापस आमंत्रित किया- 'जब वे शायद महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो जाएं'। ट्रंप साहब ने इसे 'बदला' कहा।

दुनिया पर काले बादल

अमेरिका के एक सौदागर राष्ट्रपति और कबूलनामे वाले सौदेबाज के साथ दुनिया कहां जाएगी? और भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं?

दुनिया को संचालित करने के लिए, सत्तावादी शासक एक 'क्लब' बनाएंगे- ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग। वे अपने मनचाहे इलाकों को हड़प लेंगे- अमेरिका की नजर पनामा नहर, कनाडा, ग्रीनलैंड और गाजा पर है; रूस, जो पहले ही क्रीमिया, अब्खाजिया और दक्षिण ओसेशिया पर कब्जा कर चुका है, और यूक्रेन तथा शायद जार्जिया पर कब्जा करना चाहता है; और चीन, तिब्बत और हांगकांग को जबरन अपने में मिलाने के बाद, ताइवान, भारत के महत्त्वपूर्ण हिस्सों और दक्षिण चीन सागर तथा उसके द्वीपों पर कब्जा करने की अपनी इच्छा दबाए नहीं रख सका है। तीनों देश, दुनिया को 'प्रभाव के क्षेत्रों' में विभाजित करने और संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में संसाधनों का दोहन करने का प्रयास करेंगे। भारत, चीन के सामने कमजोर होगा और न तो अमेरिका उसकी मदद करेगा, और न ही रूस।

भारत को अमेरिका से अधिक सैन्य उपकरण खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा। उसे कम शुल्क पर अमेरिका से अधिक सामान आयात करने पर बाध्य होना पड़ेगा। अमेरिका और रूस के बीच तनाव कम होने का मतलब यह होगा कि रूसी तेल अब सस्ते दामों पर उपलब्ध नहीं होगा। भारत को 'ब्रिक्स' को कम महत्त्व देने के लिए 'मनाया' जा सकता है। 'क्वाड' को चीन के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने साझा संरक्षक, अमेरिका के तहत घनिष्ठ संबंध बनाएंगे। अगर ट्रंप साहब 'टैरिफ युद्ध' शुरू करते हैं, तो यह नियम-आधारित विश्व व्यापार को पलट देगा और भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। जर्मनी और फ्रांस ने महसूस किया है कि भारत को अपनी रक्षा खुद करनी होगी।

मोदी साहब सोचते हैं कि ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती भारत को बचा लेगी। मगर ऐसा कोई मौका नहीं आने वाला है। ट्रंप स्वार्थी और अहंकारी हैं, और उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि उनकी वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। दुनिया के लोगो, चार साल तक और इंतजार करो।

आंगन के सांप

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

> पिछले सप्ताह ट्रेन को बंधक बनाने वालों ने औरतों और बच्चों को ढाल बना कर अपना बचाव करने की कोशिश की थी। कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं, लेकिन पूरी खबर किसी को नहीं मालूम अभी तक, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने असलियत छिपाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। कभी न कभी हकीकत सामने आ ही जाएगी। पर, सवाल है कि क्या पाकिस्तान के सैनिक शासक आतंकवादी गुटों को तैयार करना बंद कर देंगे या नहीं?

दशकों से पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने दहशत को बढ़ावा दिया है, सो पिछले सप्ताह जब बलूच आतंकवादियों ने एक ट्रेन में सौ से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाया, तो दुनिया के मीडिया ने उसे खास तवज्जो नहीं दी। भारत में वह खबर सुर्खियों में रही एक दो दिन, लेकिन वह दर्द जो होना चाहिए बेगुनाह लोगों को मारा जाता देख कर, वह नहीं दिखा। कैसे दिखेगा, जब हमारे देश के अंदर इतनी बार बेगुनाह लोगों का पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ऐसे शिकार किया है जैसे वे इंसान ही न हों। मुंबई में आज भी जब उन जगहों से गुजरती हूं, जहां अजमल कसाब और उसके साथियों ने लोगों को मारा था, तो 26/11 की यादें ताजा हो जाती हैं। पाकिस्तान को कई बार नसीहत दी है दुनिया के बड़े नेताओं ने कि आतंकवादियों को पालना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इस मुल्क के सैनिक शासकों ने किसी की नहीं सुनी। एक बार जब अमेरिकी राजनेता हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान में थीं बतौर खास सरकारी मेहमान, उन्होंने अपने भाषण में खुलकर कहा था कि जो लोग सांप पालते हैं अपने आंगन में, उन्हें याद रखना चाहिए कि कभी न कभी वे सांप उनको डंस सकते हैं। इस नसीहत के बावजूद, पाकिस्तान पालता रहा आतंकवादियों को, शरण देता रहा उसामा बिन लादेन जैसे दहशतगर्दों को।

अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है, और आज वहां महिलाओं को पूरी तरह अदृश्य कर दिया गया है। महिलाएं न बाहर जा सकती हैं बिना बुर्के में खुद को लपेटे, न नौकरी कर सकती हैं, न पढ़ सकती हैं। कुछ महीने पहले तालिबान शासकों का फरमान आया कि उन्हें खिड़कियों पर नहीं आना चाहिए, ताकि गलती से भी कोई उनको देख न ले। पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने तालिबान को न पाला-पोसा होता, तो शायद तालिबान नाम की यह जिहादी संस्था होती ही नहीं। जबसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, हम जैसे पत्रकारों के लिए पाकिस्तान आना-जाना तकरीबन पूरी तरह बंद हो गया है, मगर एक जमाना था जब हम वहां जाया करते थे, जब भी कोई बड़ी राजनीतिक घटना होती थी।

उन दिनों मैं अक्सर जाया करती थी पाकिस्तान, सो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह आतंकवादियों को खास मेहमान की तरह रखा जाता है उस देश में। पेशावर में मैं मिली हूं उन सारे अफगान जिहादी नेताओं से, जो आगे जाकर अफगानिस्तान के शासक बने थे। लाहौर के एक गुरुद्वारे में मैं मिली हूं खालिस्तानी आतंकवादियों से, और देखा है कि किस तरह हाफिज सईद जैसे दरिंदे को सरकारी संरक्षण में रखा गया है। एक बार जब मैं वापस भारत आ रही थी तो एअरपोर्ट पर एक सिपाही मिला, जिसने मुझसे कहा कि 'आप सिखों को हमारे सदर जिया उल-हक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बहुत मदद की है आपकी।'

मैंने मुस्कराकर उसकी बात टाल दी थी, लेकिन वापस दिल्ली आकर अपने लेख में विस्तार से लिखा था कि कैसे मैं ननकाना साहब गुरुद्वारे में गई थी और वहां लोगों से बातें की, तो मालूम हुआ कि आपरेशन ब्लू स्टार के बाद भिंडरांवाले के कई नौजवान साथी यहां आए थे और उनको आतंकवाद का प्रशिक्षण पाकिस्तानी सेना के अफसरों से मिला था। वापस जब अपने पंजाब में आए, तो एक पूरे दशक तक इतना आतंक फैलाया था कि शाम के छह बजने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता था डर के मारे। हर गांव में हुआ करते थे उनके जासूस और हथियारबंद सिपाही, हर गुरुद्वारे के अंदर हुआ करते थे इनके अड्डे। दहशत के उस दौर को समाप्त किया था केपीएस गिल ने, आतंकवादियों के साथ वही सलूक करके, जो वे किया करते थे पुलिसवालों के साथ, और उनके साथ भी जो उनकी नजर में पुलिस के मुखबिर थे।

पंजाब में हालत सुधरे, तो पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंक फैलाया और घाटी के शहरों-कस्बों में वही हाल हुआ, जो पंजाब में कभी था। रात होने से पहले लोग अपने घर लौट जाते थे। कश्मीर में इसलिए कि जिहादियों को आम लोगों का काफी समर्थन मिला, जिहादी आतंकवाद को समाप्त करने में देर भी लगी और सख्ती भी बरतनी पड़ी इतनी कि आज भी श्रीनगर की हर दूसरी गली में पहरा देते हैं हमारे सैनिक और सुरक्षाकर्मी। मुंबई हमले के बाद हमारी सरकार ने सबूत दिए पाकिस्तान को कि हमले के दौरान जो दस हत्यारे इस शहर में भेजे गए थे, वे हर कदम पर किसी पाकिस्तानी फौजी अफसर से संपर्क करके आगे बढ़ रहे थे। इन सबूतों को लेकर फिल्में बनी हैं, किताबें लिखी गई हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान सरकार मानने को तैयार नहीं है कि उस हमले के पीछे उसकी सेना थी।

सो, अब जब पाकिस्तान के अंदर ही हमले कर रहे हैं उसी किस्म के लोग, जिनको प्रशिक्षित किया था पाकिस्तानी सेना ने, तो हम क्यों आंसू बहाएं? पिछले सप्ताह ट्रेन को बंधक बनाने वालों ने औरतों और बच्चों को ढाल बना कर अपना बचाव करने की कोशिश की थी। कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं, लेकिन पूरी खबर किसी को नहीं मालूम अभी तक, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने असलियत छिपाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। कभी न कभी हकीकत सामने आ ही जाएगी। पर, सवाल है कि क्या पाकिस्तान के सैनिक शासक आतंकवादी गुटों को तैयार करना बंद कर देंगे या नहीं? मेरा खयाल है कि इनमें से कई गुट अब बेकाबू हो चुके हैं और वे अपने आकाओं को डंसने लगे हैं। जब कोई अपने आंगन में सांप पालता है, तो ऐसा ही होता है।

जोखिम के उपकरण

शिक्षा

ज्योति सिडाना

> यह भी सच है कि समाज पुन: बैलगाड़ी या सरल तकनीक वाले दौर की ओर नहीं लौट सकता, लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ समायोजन बैठाया जा सकता है ताकि डिजिटल उपकरण केवल सहायक की भूमिका में रहे। जीवन पर हावी होकर हमारे अस्तित्व को चुनौती न दे। समाजविज्ञानी कहते हैं कि यदि हम सफल होना चाहते हैं, तो हमें असफलता की दर को दोगुना करना होगा।

आज के दौर को संकट और जोखिमों का दौर कहा जा सकता है जिनमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम देखे जा सकते हैं। प्राचीन समाज में किसी भी प्रकार की समस्या या जोखिम के लिए अशिक्षा को एक महत्त्वपूर्ण कारण माना जाता था, पर आज के शिक्षित और तकनीकी रूप से विकसित समाज में इस प्रकार के जोखिमों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। एक ऐसा समाज, जिसमें तकनीकी ज्ञान और कौशल का उपयोग कर जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य उत्पीड़नकारी व्यवस्था और शोषण को समाप्त करना तथा समानता स्थापित करना होता है। शिक्षा महज ज्ञान का लेन-देन नहीं, बल्कि समाज को संतुलित विकास की ओर अग्रसर करती है। शिक्षाशास्त्री पाउलो फ्रेरे लिखते हैं कि शिक्षित होने का मतलब उत्पीड़न वाली व्यवस्था में अपनी जगह बना लेना नहीं, बल्कि मनुष्य बनना है और पूर्ण मनुष्य तभी बना जा सकता है जब अमानुषिक बनाने वाले यथार्थ को बदला जाए।

तकनीक का उपयोग समाज और मानव के विकास तथा प्रगति के लिए किया जाए, तब तक तो ठीक है, लेकिन उसका आवश्यकता से अधिक उपयोग या उस पर पूरी तरह निर्भरता ने अनेक तरह के जोखिमों को उत्पन्न कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक संबंध यहां तक कि मनुष्य की सुरक्षा तक खतरे में है। निजता की अवधारणा अब अतीत की घटना हो गई है, क्योंकि आप हर जगह कैमरे की निगरानी में हैं, यानी आपकी जिंदगी का हर पक्ष खुली किताब के समान है जिसे कोई भी पढ़ सकता है, देख सकता है और तो और उसका दुरुपयोग कर सकता है। समाज विज्ञानी अलरिच बैक ऐसे समाज को जोखिम भरे समाज की संज्ञा देते हैं। कुछ खतरे प्राकृतिक होते हैं, जिनका सामना करना चुनौती हो सकता है, क्योंकि वे अनिश्चित होते हैं और उन पर पूर्णतः नियंत्रण करना भी लगभग संभव नहीं होता। मगर तकनीकी खतरे स्वयं मानव द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, जिन्होंने मानव अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है।

सामाजिक असमानता, आर्थिक अस्थिरता, पर्यावरणीय संकट, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां ऐसे खतरे हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मसलन, छोटी उम्र में दिल का दौरा, आंखों का रोग, मोटापा, कैंसर, कंप्यूटर और रोबोट क्रांति के कारण रोजगार के क्षेत्र में अनिश्चितता, तनाव, निराशा, हिंसा, अकेलापन और पर्यावरण संबंधी जोखिम आदि ऐसे खतरे हैं जिनमें तकनीकी विकास ने वृद्धि कर दी है। फिर भी इन जोखिमों से लड़ने या इन्हें रोकने के सार्थक प्रयास दिखाई नहीं दे रहे। संभवतः इसलिए कि विज्ञान और तकनीकी विकास किसी भी देश की प्रगति का सूचक माना जाता है। मगर आश्चर्य की बात है कि तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्र खुद को गैर-तकनीकी राह पर चलने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और हमारे जैसे विकासशील देश विकसित देशों की पंक्ति में शामिल होने और स्वयं को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की होड़ में तकनीक केंद्रित समाज बनते जा रहे हैं। यहां स्वीडन के उदाहरण की चर्चा की जा सकती है। स्वीडन ने वर्ष 2009 में स्कूल-कालेजों में किताबों की जगह स्क्रीन लगाने के लिए बेहिसाब खर्च कर दिए, लेकिन अब वह पुनः किताबें वापस लाने के लिए बड़ी राशि खर्च कर रहा है। आखिर क्यों, यह गहन चिंतन का विषय है। संभवतः उसने शिक्षा के डिजिटलीकरण के खतरों को अनुभव कर लिया, तो क्या विकासशील देश उनके अनुभवों से सबक नहीं ले सकते।

शिक्षा बाजार और मुनाफे की व्यवस्था नहीं, कल्याण और विकास की प्रणाली है। इसलिए विभिन्न तरह के खतरों का सामना करने के लिए सरकारी संस्थानों को बेहतर करना होगा। केवल निजी क्षेत्र को समर्थन देने से विकास नहीं होगा। परंपरागत शिक्षा प्रणाली की खामियों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा सुधारना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उसे पूर्णतः उपेक्षित करना समस्या का समाधान नहीं है। कितनी भी विकसित तकनीक क्यों न हो, वह एक शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती। यह बात अलग है कि कुछ लोग इस बात से असहमति रखते हैं, वे मानते हैं कि एआइ (कृत्रिम मेधा) के विकास के बाद ये संभावनाएं भी गलत साबित हो रही हैं। बच्चों को जन्म देने का काम कृत्रिम कोख करेगी, रोबोट चिकित्सक, शिक्षक, नर्स, परिचारक और ड्राइवर की भूमिकाओं का निर्वाह करेंगे, लेकिन यहां एक महत्त्वपूर्ण सवाल है कि क्या दुनिया के अधिकांश देश, विशेष रूप से विकासशील देश, इस तकनीक के परिणाम भुगतने या उनका सामना करने के लिए तैयार हैं? जहां सरकारी विद्यालयों/महाविद्यालयों में कुर्सी-मेज, शिक्षक और बुनियादी संसाधन तक नहीं हैं, चिकित्सा केंद्रों में जीवनरक्षक सुविधाएं, पर्याप्त चिकित्सक और कर्मचारी नहीं है, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, साइबर अपराध पर नियंत्रण नहीं है, वहां एक विकसित, समृद्ध और खुशहाल समाज की कल्पना यथार्थ से कोसों दूर नजर आती है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ संतुलन बिठाया जाना चाहिए, ताकि डिजिटल उपकरण केवल सहायक की भूमिका में रहें, जीवन पर हावी होकर हमारे अस्तित्व को चुनौती न दें। समाजविज्ञानी कहते हैं कि अगर हम सफल होना चाहते हैं, तो हमें विफलता की दर को दोगुना करना होगा। क्योंकि अगर हम तकनीक के जोखिम को खत्म नहीं कर सकते, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, सिवाय इसके कि हम इस पर नियंत्रण करना सीखें लें। दरअसल, तकनीक या तकनीकी ज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन उसका वह उपयोग नहीं हो रहा, जिससे समाज को फायदा अधिक हो।

इसके विपरीत नई दुनिया में बच्चे, किशोर और युवा सूचनाओं के ऐसे भंवर जाल में फंसते जा रहे हैं, जिससे निकलना उनके बस में नहीं रहा। छोटी उम्र में ही मोबाइल और लैपटाप की ऐसी लत पड़ने लगी है कि यह पीढ़ी इसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मशीनी मानव की जगह सहृदय मानव, काल्पनिक दुनिया की जगह वास्तविक दुनिया और आभासी संबंधों की जगह वास्तविक संबंधों को दोबारा केंद्र में लाया जाए. ऐसा न हो कि आने वाले समय में मशीन मालिक और मानव गुलाम बन जाए, जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

खबर में आने का नया सूत्र

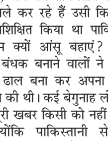

बाखबर

सुधीश पचौरी

> खबर में आने का नया सूत्र है, जानी-मानी हस्तियों को अपमानित करो, खबर बनाओ। चैनल भी ऐसे लोगों को निराश नहीं करते। उनके लिए 'बदतमीजी' भी 'एक संस्कृति' है।

यह इस 'होली' की खबर है कि 'डर' की खबर है, जो 'तनाव' की खबर है। इस होली की बोली में सुरक्षा बलों की टोली है। चैनलों पर पंक्तियां सरकती दिखती हैं: 'इस बार की होली 'शुद्ध सनातनी' होली... 'हिंदुत्व' की होली... लगता है कि इस बार 'होली' की परिभाषा भी सिकुड़ चली है। एक ओर जुमे की नमाज... दूसरी ओर होली का त्योहार..! कई संवाददाता बताते रहे कि संभल में मस्जिदें तिरपाल से ढकी हैं, उत्तर प्रदेश में ढकी हैं। एक चैनल लिखता है: 'अपनेपन का त्योहार... धर्म पर क्यों तकरार... कि मस्जिदों पर तिरपाल... अजीब है हाल'!

एक मौलाना कहते हैं कि यह पहली बार है कि मस्जिदें ढकी गई हैं... फिर एक चैनल पर लाइन कि 'संभल, मुरादाबाद... नमाज ढाई बजे के बाद...'!

जुमे के दिन 'संभल' में होली आयोजन को लेकर एक पुलिस अधिकारी का यह आदेश कि 'जो न खेलें, घर से न निकलें...' बहसों में बना रहता है। इस बार पुरानी दिल्ली में भी पुलिस की गश्त दिखती है, ताकि कोई अवांछित घटना न हो। इतनी 'डरी हुई' होली कभी न दिखी। एक चैनल में पंक्तियां रेंगती हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश में और यूपी के बारह जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कुछ पंक्तियां नेताओं के शुभ संदेश... कि 'होली प्यार से मनाएं', 'भाईचारे से मनाएं'! फिर एक पंक्ति कहती है कि 'प्यार से गले मिलें'। लेकिन ऐसे संदेशों को कौन माने?

फिर भी सभी महामहिमों द्वारा होली की शुभकामनाएं... लेकिन इनमें 'जनसाधरण' की होली कहां? चैनलों में तो 'डर' है, 'तनाव' है!

एक चैनल की एक संवाददाता 'बरसाने' की 'होली' का सीधा प्रसारण दिखा रही है। रंगों के बीच ब्रजबालाओं के साथ नाचती-गाती, 'लट्ठमार होली' की खबर देती हुई वह भी होली की तरंग में लहराती दिखती है। जरा-सा घूंघट काढ़े खूब सजी-धजी तगड़ी-सी ब्रजबालाएं लाठी लिए दिखती हैं और कुछ देर में 'लट्ठमार' होली भी शुरू हो जाती है। अबीर गुलाल की बौछार के बीच सिर पर पाग बांधे हुरिहारों के चेहरों पर इतने रंग हैं कि सब बेपहचान नजर आते हैं। एक हुरिहारा कहता है कि हम 'बरसाने' में आकर अपनी भाभियों के लिए गीत गाएंगे तो वे लाठी लेकर मारना शुरू कर देंगी। हम ढाल सिर पर रख बचते रहेंगे। पिटने पर भी कोई बुरा नहीं मानता। यही 'लट्ठमार' होली है।

एक महिला जरा-सा घूंघट काढ़ कर खुश होकर संवाददाता से कहती है कि आज के दिन औरतें मर्दानी बन जाती हैं... मर्दों के सिर पर जोर से लट्ठ बजाती हैं! पहले ब्रज की औरतें राधा बनकर कान्हा को बुलाने 'नंदगांव' जाती और गाती हैं कि 'कान्हा बरसाने में आइ जइयो बुलाय गई राधा प्यारी...' फिर बहुत से लोग कान्हा का बाना धरण कर अपने सिरों पर पाग बांध और हाथ में ढाल लेकर 'बरसाने' आते हैं। जैसे ही वे हमें छेड़ते हैं, हम उन पर लट्ठ बरसाने लगती हैं और गाने लगती हैं कि कान्हा बरसाने में आ जइयो बुलाय रही राधा प्यारी... एक गोपी उछल-उछल कर लट्ठ मारती रहती है। फिर भाभी-देवर का गीत-संवाद होता है, फिर रंग और लट्ठ बरसते हैं... कैमरे सब तस्वीरें लेते रहते हैं। विदेशी भी रंगों में बेपहचान हो जाते हैं। एक चैनल पर एक हुरिहारा कहता है कि राधे रानी के 'बरसाने' में आकर सारे दुख-दर्द दूर हो जाते हैं।

मस्ती के इन दृश्यों के बीच अचानक एक चैनल की कुछ पंक्तियां फिर डराने लगती हैं..! कहां गए वे एक से एक सुरीले फिल्मी गीत, जो होली के इस दिन खबर चैनलों में खासकर बजाए जाते थे। एक दिन एक विपक्षी नेता एक नामी अभिनेत्री को कमतर करने वाला बयान देकर विवाद पैदा कर देता है। अभिनेत्री के पक्षधर उस पर पिल पड़ते हैं और देर तक तू-तू मैं-मैं होती रहती है। खबर में आने का नया सूत्र है। जानी-मानी हस्तियों को अपमानित करो, खबर बनाओ। चैनल भी ऐसे लोगों को निराश नहीं करते। उनके लिए 'बदतमीजी' भी 'एक संस्कृति' है।

बीता सप्ताह एक दक्षिणी राज्य के एक मुख्यमंत्री के नाम रहा। पहले उन्होंने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' को कोसा, फिर 'त्रिभाषा फार्मूले' के बहाने 'केंद्र' पर 'हिंदी' थोपने का आरोप लगाया, फिर केंद्र द्वारा अपेक्षित धन न देने की शिकायत की, फिर 'परिसीमन' को लोकसभा की वर्तमान सीटों को कम करने वाला बताया, फिर उन्होंने दक्षिणी राज्यों को इकट्ठा कर 'दक्षिण बरक्स उत्तर' किया। केंद्र कहता रहा कि न कोई 'हिंदी' थोप रहा है, न सीटें कम हो रही हैं, लेकिन जब परस्पर 'विश्वास की कमी' हो तो कोई क्या करे..!

अंत में उन्हीं मुख्यमंत्री ने 'रुपए के चिह्न' को बदलकर 'तमिल चिह्न' घोषित कर दिया। एक चर्चा में 'मुद्रा' के 'चिह्न विशेषज्ञ' ने साफ किया कि 'मुद्राचिह्न' तय करने का अधिकार 'रिजर्व बैंक' का है। फिर रुपए के 'स्वीकृत चिह्न' को जिस कलाकार ने बनाया, वह तमिलनाडु के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री का स्नेह पात्र रहा। अब उन्हीं के सुपुत्र मुख्यमंत्री रुपए के उसी चिह्न को खारिज कर रहे हैं, लेकिन जब तक रिजर्व बैंक ही खारिज न करे, वह खारिज नहीं हो सकता है! जय हो 'खारिज संस्कृति' की!

https://t.me/AllNewsPaperPaid

www.readwhere.com

बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक की घटना ने पाकिस्तान के अंतर्कलह को विश्व स्तर पर उजागर कर दिया है। अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान एक रह पाएगा? क्या पाकिस्तान टूट जाएगा? क्या बलूचिस्तान अलग हो जाएगा या क्या पाक बलूचिस्तान को अपने साथ जोड़ कर रख पाएगा? पाकिस्तान बलूचिस्तान में बलूच स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान (एनएपी या नैप) पार्ट-2 चलाने वाला है,जिसके तहत बलूचिस्तान में बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में नैप पार्ट-2 के तहत सभी विदेशी अफगान नागरिकों को हटाने के लिए ऑल ऑउट ऑपरेशन चलाने को लेकर चर्चा हो रही है। पाक हुक्मरान ने पहला नेशनल एक्शन प्लान 2014 में पेशावर सैनिक स्कूल पर हुए हमले के बाद चलाया था। बलूचिस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तान फौज नरसंहार की तरफ बढ़ सकती है, जैसा पहले भी वो कर चुकी है। पाकिस्तान में ट्रेन हाइजैक के पीछे विदेशी मदद के आरोप भारत पर लगाया जा रहा है, जिसे भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। यह पाकिस्तान में अक्सर देखने को मिलता है, जिसमें हर प्रॉब्लेम के लिए भारत पर आरोप मढ़े जाते हैं। पाकिस्तान को बलूच समस्या के कारणों का हल करना चाहिए। पाकिस्तान के आंतरिक हालात का विश्लेषण करता आजकल का यह अंक...

पाक में बलूच बगावत का नया दौर

ट्रेन हाइजैक
प्रभात कुमार राय
विदेश मामलों के जानकार

पाकिस्तान हुकूमत के प्रवक्ता ने बयान जारी किया कि पाक में अंजाम दिए जाने वाले प्रत्येक दहशतगर्द आक्रमण की पृष्ठभूमि में भारत का सक्रिय हाथ हुआ करता है और जाफर एक्सप्रेस को अगवा करने की आतंकी वारदात के पीछे भी भारत की साज़िश है। पाक प्रवक्ता का कहना है कि भारत के साथ मिलकर अफगान सरगनाओं का भी इस वारदात को अंजाम देने में सक्रिय किरदार रहा है। पाक हुकूमत द्वारा आयद किए गए बेबुनियाद इल्जामों का भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा वाजिब प्रति उत्तर दे भी दिया गया। भारत सरकार के प्रवक्ता ने फरमाया कि समस्त विश्व बखूबी जानता है कि पाकिस्तान वैश्विक जिहादी आतंकवादियों की सबसे बड़ी पनाहगाह रहा है।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सशस्त्र बगावत यूं तो तकरीबन सत्तर वर्ष पुरानी हो चुकी है और किसी न किसी तौर पर सन् 1948 से निरंतर जारी रही है। किंतु अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बलूच बगावत का एक नया दौर प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि जिस बड़े स्तर पर बलूच विद्रोहियों ने गुरिल्ला हमले अंजाम दिए हैं, उससे पाक हुकूमत और उसकी फौज थर्रा उठी है। पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान के शहर क्वेटा से पेशावर के मार्ग पर दौड़ रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ट्रैक को बलूच बागियों द्वारा उड़ा दिया गया। ट्रेन पर घात लगाकर बलूच बागियों द्वारा तकरीबन 300 से अधिक नागरिकों और सैनिकों को जाफर एक्सप्रेस से अगवा कर लिया गया। पाक फौज द्वारा सैन्य ऑपरेशन में कुछ नागरिकों और अपने सैनिकों को बलूच विद्रोहियों की पकड़ से मुक्त करा लिया गया। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक अभी तकरीबन सौ से अधिक सैनिक बलूच लिबरेशन आर्मी की पकड़ में विद्यमान हैं। अपनी पुरानी रिवायती फितरत के मुताबिक पाकिस्तान हुकूमत के प्रवक्ता ने बयान जारी कर दिया कि पाकिस्तान में अंजाम दिए जाने वाले प्रत्येक दहशतगर्द आक्रमण की पृष्ठभूमि में भारत का सक्रिय हाथ हुआ करता है और जाफर एक्सप्रेस को अगवा करने की आतंकी वारदात के पीछे भी भारत की साज़िश मौजूद है।

पाक प्रवक्ता का कहना है कि भारत के साथ मिलकर अफगान सरगनाओं का भी इस वारदात को अंजाम देने में सक्रिय किरदार रहा है। पाक हुकूमत द्वारा आयद किए गए बेबुनियाद इल्जामों का भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा वाजिब प्रति उत्तर दे भी दिया गया। भारत सरकार के प्रवक्ता ने फरमाया कि समस्त विश्व बखूबी जानता है कि पाकिस्तान वैश्विक जिहादी आतंकवादियों की सबसे बड़ी पनाहगाह रहा है। अपने नृशंस गुनाहों के लिए किसी दूसरे मुल्क पर बेबुनियाद इल्जाम आयद करने से पहले पाकिस्तान को अपने भीतर भी झांक लेना चाहिए।

अजीत डोभाल के बयान का हवाला

पाकिस्तान को अपने आंतरिक विद्रोह की वारदातों का ठीकरा दूसरे मुल्कों पर नहीं फोड़ना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला अंजाम देने की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा बाकायदा ले ली गई है। पाकिस्तान के हुकूमत परस्त राजनीतिक विश्लेषक आजकल अजीत डोभाल के उस बयान का निरंतर हवाला दे रहे हैं, जो कि बलूचिस्तान को लेकर उन्होंने सन् 2014 में दिया था। अजीत डोभाल ने अपने बयान में फरमाया था कि पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले तो अंजाम दे सकता है, किंतु भारत के प्रतिशोध में आखिरकार पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान को गंवाया जा सकता है। 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान का बाकायदा उल्लेख किया था। नरेंद्र मोदी ने बलूचों के ऊपर अंजाम दिए जा रहे पाकिस्तानी फौज के जुल्मों सितम का प्रश्न भी प्रबलता से उठाया था। उल्लेखनीय है कि पाक फौज द्वारा तकरीबन एक लाख से अधिक बलूचों का कत्ल ओ गारद अंजाम दिया जा चुका है और एक लाख बलूच नागरिक लापता हैं, जिनके विषय में अनुमान है कि उनको भी पाक फौज ने अगवा करके बंदी बना लिया अथवा हलाक कर दिया है। यूं तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज द्वारा अंजाम दिए जा रहे जा रहे नृशंस जुल्मों सितम की सारी दुनिया में ही निरंतर निंदा की जाती रही है। बलूचों के प्रति प्रकट की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक संवेदनाओं के प्रति उत्तर में बलूच लीडर ब्रह्मदग बुगती ने नरेंद्र मोदी को हार्दिक धन्यवाद अदा किया था।

बलूच विद्रोहियों की मदद का इल्जाम

नरेंद्र मोदी द्वारा बलूचिस्तान का उल्लेख करने पर पाक हुक्मरान एकदम बौखला उठे थे। पाकिस्तान के हुक्मरान भारतीय हुकूमत पर खुफिया एजेंसी रॉ के माध्यम से बलूच विद्रोहियों की सक्रिय इमदाद करने का इल्जाम आयद करते रहे हैं। अमेरिकी सीनेट में अमेरिकन सांसदों द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान की फौज के जुल्मों सितम का विस्तार पूर्वक उल्लेख करने के साथ ही साथ बलूचिस्तान को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने की जबरदस्त पैरवी की गई थी। ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा अमेरिका कांग्रेस के समक्ष पाक हुकूमत पर यह इल्जाम आयद किया गया था कि विद्रोही प्रांत बलूचिस्तान में दमनकारी नीतियां अख्तियार करके निरंतर नृशंस तौर पर सैन्य बल प्रयोग कर रहा है। 12 मार्च मंगलवार को बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) द्वारा जाफर एक्सप्रेस पर अंजाम दिए गए आक्रमण के विषय में पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता का कहना है कि ट्रेन को अगवा करने वाले सारे बलूच विद्रोही मार दिए गए हैं और 300 से ज्यादा लोगों को उनके कब्जे से आजाद करा लिया गया है, जबकि बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता ने दावा किया है कि अभी भी पाकिस्तान सेना के 194 सैनिक उनके बंधक हैं। इस संगीन वारदात की वास्तविक सच्चाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन यह तथ्य एकदम स्पष्ट है कि विगत 19 वर्षों से जब से सन 2006 में बलूच लीडर नवाब अकबर खान बुगती की हत्या पाक फौज द्वारा अंजाम दी गई है, तभी से बलूच विद्रोह मंथर और तीव्र गति से निरंतर जारी रहा है। बलूचिस्तान का दुर्गम बोलान इलाका बलूच विद्रोहियों का केंद्र रहा है। बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर रहे चीन के इंजीनियरों के काफिलों पर अनेक दफा बलूच विद्रोहियों ने घात लगाकर आक्रमण अंजाम दिए हैं।

चीन की गतिविधियों का विरोध

बलूच लिबरेशन आर्मी वस्तुतः बलूचिस्तान में चीन की गतिविधियों की निरंतर सशस्त्र मुख़ालिफ़त करती रही है। ग्वादर बंदरगाह के निर्माण में तकरीबन एक लाख चीनी कार्यरत हैं। बलूचों को चीन द्वारा निवेश किए गए 62 मिलियन डॉलर के इस विराट निर्माण कार्य में कदाचित शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में चीनी श्रमिकों के अतिरिक्त केवल पाकिस्तान के पंजाबियों का बोलबाला है। पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान की सरजमीं में अपार खनिज संपदा विद्यमान रही है, किंतु बलूच नागरिक बेहद गरीब हैं और उनकी औसत प्रतिदिन आमदनी 100 रुपये भी नहीं है। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल वस्तुतः पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का तकरीबन आधा है।

बलूच कबीलों की आबादी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में फैली हुई है। ऐतिहासिक तौर पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मध्य कभी भी सामान्य रिश्ते कायम नहीं रहे। बलूच सरदार कलात खान और बलूचिस्तान स्टेट खुद को स्वतंत्र और खुद मुख्तार कायम बनाए रखने का प्रबल पक्षधर रहा था। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश राज के दौर में भी नेपाल और भूटान की तरह बलूचिस्तान को भी स्वायत्तता और आजादी हासिल रही थी। सन् 1947 में भारत के विभाजन के तत्पश्चात निर्मित हुए पाकिस्तान के सर्वोच्च लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने आरंभ में स्वतंत्र बलूचिस्तान स्टेट के अस्तित्व को बाकायदा स्वीकार कर लिया था, किंतु अगले ही वर्ष सन् 1948 में बलूचिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी फौजी ताकत द्वारा जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया। पाकिस्तान हुकूमत द्वारा अंजाम दिए गए इस जबरन संविलय को कलात शासक मीर खान और बलूचों ने कदाचित स्वीकार नहीं किया था। जबरन विलय के विरुद्ध बलूचों ने सन् 1948 से लेकर सन् 1957 तक पाक फौज के विरुद्ध निरंतर सशस्त्र संग्राम किया था। बलूचों के दस वर्षीय सशस्त्र संग्राम का नेतृत्व नौरोज खान नामक एक क्रांतिकारी गोरिल्ला लीडर द्वारा किया गया था।

बलूचों की तकरीबन दो करोड़ आबादी

आखिरकार पाक फौज द्वारा अमेरिका और फ्रांस से हासिल किए गए लड़ाकू विमानों द्वारा बलूचिस्तान पर बर्बर तौर पर कारपेट बमबारी अंजाम दी गई। तब कहीं जाकर कलात खान और नौरोज खान के नेतृत्व में विद्रोही बलूचों ने सन् 1957 में पाकिस्तानी फौज के सामने आत्मसमर्पण किया। पाकिस्तान में बलूचों की आबादी तकरीबन एक करोड़ है। कुल मिलाकर बलूचों की आबादी तकरीबन दो करोड़ है, जोकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में फैली हुई है बलूचिस्तान में बलूचों के मुख्यतः दो धड़े विद्यमान हैं। बलूचों का एक धड़ा बलूच जुबान बोलता है तो दूसरा धड़ा ब्राहू भाषा बोलता है जो कि एक द्रविड़ भाषा है। बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा एक सर्द रेगिस्तान है, जो ईरानी पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यही वह इलाका है जहां पर तेल और प्राकृतिक गैस के अकूत भंडार विद्यमान हैं।

बलूचिस्तान के सुई इलाके से समस्त पाकिस्तान को प्राकृतिक गैस की सप्लाई की जाती रही है। सन 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के पश्चात बलूचों के अंदर भी फिर से एक नई उम्मीद और एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ था। सन् 1973 में पाकिस्तान के जबरन आधिपत्य के विरुद्ध बलूचों ने फिर से हथियार उठा लिए थे। सन् 1973 में बलूच विद्रोहियों का नेतृत्व बलूचिस्तान के मार्क्सवादियों के हाथों में था। मार्क्सवादी बलूच पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के तकरीबन दस हजार मार्क्सवादी बलूच छापामारों ने पाकिस्तान की 10 डिवीजन फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। अमेरिका द्वारा प्रदान किए गए फाइटर जेट्स द्वारा बलूचिस्तान पर नापाक बमों से भयानक बमबारी अंजाम दी गई और बलूचों की बगावत को नृशंसतापूर्वक कुचल दिया गया। बलूच गोरिल्लाओं और पाक फौज के मध्य संघर्ष में हजारों बलूच नागरिक हलाक हो गए थे। पांच हजार से अधिक मार्क्सवादी बलूच विद्रोही और तीन हजार से अधिक पाक सैनिक सन् 1973 से सन् 1975 तक जारी रहे गृहयुद्ध में हताहत हो गए थे। उस वक्त भी पाक हुकूमत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर इल्जाम आयद किया था कि उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से पृथक करने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी रॉ का बाकायदा इस्तेमाल किया था।

पाक के सैन्य आधिपत्य से आजादी की ललक

कह सकते हैं कि समस्त नृशंस सैन्य जुल्मों सितम और दमन के बावजूद बलूचों में पाकिस्तान के सैन्य आधिपत्य से आजादी हासिल कर लेने की आकांक्षा और ललक कभी भी खत्म नहीं हुई। सन् 2000 में नवाब अकबर खान बुगती के नेतृत्व में एक बार फिर से बलूच विद्रोहियों ने हथियार उठा लिए। सन् 2006 में बलूच लीडर अकबर खान बुगती की पाक फौज द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद उनके बेटे ब्रह्मदग बुगती ने बलूच विद्रोहियों का नेतृत्व संभाल लिया है। पाक हुकूमत की गुलामी से पूर्णतः मुक्त होकर ही बलूच अब दम लेंगे। ट्रेन हाइजैक इसी दिशा में बलूचों का एक प्रयास है।

दूसरा बांग्लादेश बनने की राह पर बलूच

बलूचिस्तान
सुनील अमर
वरिष्ठ पत्रकार

पाकिस्तान की आजादी के समय से ही वहां चल रहा बलूचिस्तान प्रान्त का अलगाववादी आन्दोलन अपने इतिहास के सबसे खूंखार दौर में पहुंच गया लगता है। गत सप्ताह वहां हुए जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अपहरण कांड तथा उसके जवाब में हुए सैन्य ऑपरेशन में सैकड़ों लोग मारे गये बताये जा रहे हैं, जिसमें सेना के जवान और नागरिक शामिल थे। अपने देश के सबसे बड़े प्रान्त के साथ किए जा रहे सौतले और उपेक्षित व्यवहार के चलते पाकिस्तान में यह होना ही था। बलूचिस्तान का यह रक्तरंजित कांड किन्हीं मामलों में उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान (आज के बांग्लादेश) जैसा ही लगता है जहां अपने ही क्रूर शासकों के अत्याचार से आजिज आकर जनता ने विद्रोह कर दिया था और एक लम्बे रक्तरंजित आन्दोलन के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। उसी राह पर बलूचिस्तान भी चल रहा है।

ध्यान रहे कि इसी के साथ वहां सिन्ध, खैबर पख्तूनख्वा तथा गिलगित बाल्टिस्तान प्रान्तों में भी लम्बे अरसे से अलगाववादी आन्दोलन चल रहे हैं। जिसे हम बलूचिस्तान कहते हैं उसका कुछ हिस्सा पड़ोसी देश ईरान व अफगानिस्तान में भी है। ईरान का सिस्तान प्रान्त तथा अफगानिस्तान का निमरुज, हेलमन्द और कान्धार का इलाका भी बलूचिस्तान ही है। इसकी भौगोलिक स्थिति और महत्व इसको पाकिस्तान के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बनाता है क्योंकि यह न सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुधारु गाय की तरह है बल्कि यही दक्षिण और मध्य एशिया तथा मध्य पूर्व के लिए उसका सम्पर्क मार्ग भी है।

सामरिक व व्यापारिक महत्व

इसके सामरिक व व्यापारिक महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां ग्वादर बन्दरगाह है जिसे चीन अपने संसाधनों से चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर योजना के तहत विकसित कर रहा है। पाकिस्तान का यह इलाका प्राकृतिक सम्पदाओं यथा- कोयला, गैस, सोना, तांबा तथा खनिज से भरपूर है। यहां चागल जिले में स्थित रेको दिक खदान दुनिया की बड़ी सोने और तांबे की खदानों में गिनी जाती है। यहां के डेरा बुगती इलाके में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। बावजूद इन सबके, विकास और बुनियादी सुविधाओं के नाम पर यह पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा या यूं कहें कि उपेक्षित इलाका है और यही यहां के निवासियों में विद्रोह पनपने का कारण भी है। बता दें कि पाकिस्तान की जीडीपी का 57 प्रतिशत अकेले पंजाब प्रान्त से आता है तो बलूचिस्तान से सिर्फ 05 प्रतिशत! पंजाब और सिन्ध जैसे प्रान्तों में 30 और 25 विश्वविद्यालय हैं तो बलूचिस्तान में सिर्फ 06 और यही वजह है कि पंजाब में साक्षरता दर 66 प्रतिशत है, सिन्ध में 63 और खैबरपख्तूनख्वा में 55 प्रतिशत तो बलूचिस्तान में महज 44 प्रतिशत।

बलूचिस्तान में बदहाल व्यवस्था

गरीबी का आलम यह है कि यहां 70 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। यहां की राजधानी क्वेटा में भी पेयजल की भारी किल्लत रहती है। स्वास्थ्य आदि की बदहाल व्यवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है। लोकतन्त्र के नाम पर सैन्य

तानाशाही ही पाकिस्तान की फितरत है। वही बलूचिस्तान के साथ भी शुरू से होता आया है। असल में सन् 1947 में भारत-पाकिस्तान बनने के समय ही बलूचिस्तान अपने चार प्रिंसली स्टेट- खारन, मकारन, लास बेला और कलात के साथ पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय स्वतन्त्र रहना चाहता था लेकिन सेना के बल पर इसे दबा कर पाकिस्तान में शामिल कराया गया। बलूचिस्तान का विद्रोह सन् 1948 से ही शुरू होता है जब मीर अहमद यार खान जिन्हें कलात का खान कहा जाता था, को अपदस्थ कर पाक सेना ने अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद आधा दर्जन से अधिक बार संगठित विद्रोह किया गया और अभी तक हो रहा है।

सन् 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में हुए सफल विद्रोह तथा स्वतन्त्र बांग्लादेश बन जाने के बाद बलोच विद्रोहियों को लगा कि वे भी इसी तरह अपने प्रान्त को आजाद करा सकते हैं। इससे भयभीत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फ़िक़ार अली भुट्टो ने वर्ष 1973 में बलूचिस्तान की निर्वाचित अकबर खान बुगती की सरकार को बर्खास्त करके वहां बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया जिसमें 80,000 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया। सेना ने अपने ही नागरिक ठिकानों पर बम गिरा कर हजारों नागरिकों को मार डाला। पड़ोसी देश ईरान ने इस डर से पाकिस्तान को समर्थन दे दिया कि कहीं बलोच आन्दोलन का असर उनके अपने देश में भी न फैल जाए। यह लड़ाई चार साल तक चलती रही। भुट्टो को अपदस्थ कर सत्ता पर कब्जा करने वाले जनरल जियाउल हक़ ने बलूचिस्तान से सेना वापस बुलाई। आज बलूचिस्तान में कई विद्रोही गुट हैं जिनमें बलोच लिबरेशन आर्मी (जिसने ट्रेन का अपहरण किया), बलोच रिपब्लिकन आर्मी तथा बलोच लिबरेशन फ्रंट मुख्य हैं। ये सरकार से बलूचिस्तान के लिए स्वायत्तता की मांग करते हैं लेकिन बड़े गुट बांग्लादेश की तरह पूर्ण आजादी की मांग करते हैं। बलूचिस्तान से कई नेता मुख्यमन्त्री व केन्द्रीय मन्त्री भी होते रहे हैं। ऐसे दो नेता - मीर जफरुल्ला खान जमाली वर्ष 2002 में तथा युसुफ रजा गिलानी वर्ष 2008 में पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री भी हुए लेकिन ये भी बलूचिस्तान का कोई भला नहीं कर सके।

गंभीर हो सकता है परिणाम

पूर्वी पाकिस्तान के अलग होकर बांग्लादेश बन जाने के भौगोलिक व राजनीतिक अर्थ अलग थे लेकिन बलूचिस्तान के अलग होने का पाकिस्तान के लिए बहुत गम्भीर परिणाम होगा तथा वह आर्थिक, रणनीतिक व भौगोलिक तौर पर काफी कमजोर हो सकता है। बहरहाल, इस्लामाबाद से ढाका की दूरी 2000 किमी से भी अधिक है और वहां के लिए जमीनी रास्ता न होकर सिर्फ हवाई मार्ग था जो भारत के आसमान से होकर जाता था और महत्वपूर्ण यह था कि भारत और पूर्वी पाकिस्तान की 1600 किमी लम्बी सीमा थी, जिससे ढाका आन्दोलन को भारत से आसानी से मदद मिल जाती थी। लेकिन इस्लामाबाद से क्वेटा की दूरी 900 किमी के करीब है और उसका अपना जमीनी रास्ता है। उत्पीड़न की तमाम समानताओं के बावजूद बांग्लादेश और बलूचिस्तान में रणनीतिक और भौगोलिक अन्तर है। बांग्लादेश के आजाद होते ही सोवियत रूस, भारत, अमेरिका व संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल उसे मान्यता दे दी थी लेकिन बलूचिस्तान आजाद हो भी जाता है तो उसके प्रति अन्तरराष्ट्रीय समुदाय का रवैया शायद ऐसा न हो। फिर भी पाकिस्तान को यह याद रखना होगा कि वह लम्बे समय तक इस क्षेत्र की उपेक्षा और दोहन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पड़ोस अफगानिस्तान और ईरान में भी राजनीतिक और रणनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं और ये दोनों देश बलूचिस्तान को वही मदद करने में सक्षम हैं जो कभी भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को दी थी। राजनीति भी आखिर विकट संभावनाओं का ही खेल है!

चार टुकड़ों में बंट सकता है पाकिस्तान

बिखराव
डॉ. चन्द्र त्रिखा
वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार

क्या यह मान लिया जाए कि देर-सवेर पाकिस्तान भी चार भागों में विभाजित हो जाएगा? बलूचिस्तान में यात्री-रेल का अपहरण इसी आशंका की ओर संकेत करता है। आशंका यह भी व्यक्त की जा सकती है कि एक दशक के बाद पाकिस्तान सिर्फ पाक-पंजाब तक ही सीमित रह जाएगा।

बलूचिस्तान में बदलाव की आग का किस्सा बहुत पुराना है। यह आग दरअसल 1947-48 में ही सुलगनी आरंभ हो गई थी, जब वहां के शासकों ने भारत में विलय का एक प्रस्ताव भारत सरकार को वर्ष 1948 में भेज दिया था। मगर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार नहीं किया था। इस तथ्य का खुलासा वीपी मेनन की नवीनतम कृति में विस्तार से दर्ज है। उधर, बहावलपुर-मुल्तान में भी अलगाववाद की आग सुलगने लगी है। वहां 'सरायकिस्तान' को तत्काल अलग प्रांत का दर्जा देने की मांग पिछले कुछ वर्षों से जारी है। खैबर-पख्तूनवा प्रांत पहले ही अलगाव के तेवर दिखा रहा है। वहां के अनेक संगठन पख्तूनिस्तान की मांग उठा चुके हैं। सिंध कुछ हद तक नियंत्रण में हैं मगर वहां भी 'जीए-सिंध' आंदोलन अभी भी सुलग रहा है।

सीमाएं लांघ चुका आक्रोश

बलूचिस्तान में व्यापक आक्रोश अपनी सीमाएं लांघ चुका है। वहां स्कूली स्तर पर बच्चों में भी गुस्सा उबल रहा है। वैसे भी पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान से बलूचों को खदेड़ने के लिए बार-बार सैन्य कार्रवाई करती रही है। इस कार्रवाई की दो बड़ी वजह हैं। पहली- बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति, जो इसे दुनिया के कुछ सबसे अमीर स्थानों में खड़ा कर देती है। दरअसल, यह इलाका पाक के दक्षिण-पश्चिम में है जिसके क्षेत्रफल में ईरान और अफगानिस्तान की भी जमीनें शामिल हैं। यह 347190 वर्ग किमी में फैला हुआ है।

पाक का सबसे बड़ा प्रांत बलूच

इस हिसाब से यह पाक का सबसे बड़ा प्रांत है। देश का 44 फीसदी भूभाग यहीं है जबकि इतने बड़े क्षेत्र में पाक की कुल आबादी के सिर्फ (3.6) फीसदी यानी 1.49 करोड़ लोग ही रहते हैं। दूसरी वजह यह है कि इसी जमीन के नीचे मौजूद तांबा, सोना, कोयला, यूरेनियम और अन्य खनिजों का अकूत भंडार है। इसी आधार पर यह पाक का सबसे अमीर राज्य भी है। यहां की 'रेको दिक ' खान दुनिया की सोने और तांबे की बड़ी खदानों में से एक है। यह चगाई जिले में है, जहां 590 करोड़ टन खनिज होने का अनुमान है। इसके प्रति टन भंडार में 0.22 ग्राम सोना और 0.41 फीसदी तांबा है। इस हिसाब से इस खान में 40 करोड़ टन सोना छिपा है जिसकी अनुमानित कीमत 174.42 लाख करोड़ रुपये तक हो सकती है।

खनिज भंडारों के बावजूद गरीबी

इसके बावजूद यह इलाका पाकिस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। पाकिस्तान ये बेशकीमती खदानें चीन को देकर अपनी किस्मत चमकाना चाहता है। उस पर 124.5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है जो उसकी जीडीपी का 42

फीसदी है। इस एक रेल-अपहरण से ढेरों अन्य तथ्य भी उजागर हुए हैं। एक तथ्य यह भी है कि समृद्ध खनिज भंडारों के बावजूद बलूचिस्तान में गरीबी अपने चरम पर है। कुछेक दूरदराज़ क्षेत्रों में तो बच्चों, बूढ़ों और औरतों को चुराकर ले जाने और उनके अंगों का (किडनी-लिवर-आंख आदि) महंगे दामों पर अरब देशों व कुछ पाक-पंजाब के अस्पतालों में बेचे जाने की खबरें भी आई हैं। वहां की जवान औरतों के अपहरण और कुछ गांवों में सामूहिक बलात्कार व सामूहिक नरसंहार के किस्से भी चर्चा में रहे हैं। बलूचिस्तान में गरीबी व बदहाली के चलते मानव जीवन संकट में है। बीएलए (बलूच लिबरेशन आर्मी) सरीखे संगठन अब इस बात पर आमादा हैं कि वे एक 'स्वतंत्र बलूचिस्तान' लेकर रहेंगे। यहां का प्राचीन इतिहास यहां पर अतीत में हिन्दू साम्राज्य की गवाही भी देता है।

अलग सरायकिस्तान की मांग

इतना तय है कि बलूच जाति का अतीत इस्लाम से सदियों पहले भी अस्तित्व में था। इनका अपना लिखित इतिहास भी है और साहित्य भी। कमोबेश इसी तर्ज पर अलग सरायकिस्तान प्रांत की मांग भी ज़ोरों पर है। यह मांग भाषा, बोली, संस्कृति, खानपान व पहरावे को लेकर है। पाकिस्तान में इस का प्रभाव क्षेत्र मुल्तान, बहावलपुर व सिंध प्रांत और कुछ पाक-पंजाब का क्षेत्र शामिल है। बाबा फरीद, बाबा बुल्लेशाह, अब्दुल लतीफ मिताई, सचल अलमस्त, 'गुलाम रसूल ' आदि अनेक संत फकीर व अदीब इसी बोली के लोक आधार स्तम्भ हैं।

बोली आधारित प्रांत की मांग

भारतीय क्षेत्रों में जिनमें बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, राजपुरा, पटियाला, सोनीपत, पानीपत, हांसी, रोहतक, कुरुक्षेत्र व कैथल आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर लगभग डेढ़ से दो करोड़ लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। पाकिस्तान में बहावलपुर, मुल्तान व कुछ सिंधी क्षेत्रों में इस बोली, इस भाषा पर आधारित प्रांत की मांग ज़ोरों पर है। पख़्तूनख़्वा प्रदेश में भी अलग देश की मांग प्रबलता से उठाई जा रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी पख्तूनों की सक्रियता का एक विशिष्ट इतिहास है।

सीमांत गांधी अब्दुल खां को हमने भारत-रत्न का सम्मान भी दिया था। इस क्षेत्र का इतिहास भी ईसा से दो सदी पूर्व का है। इस प्रांत की बोली पश्तो है और इनका भी अपना संगीत, अपना साहित्य व अपनी अलग संस्कृति रही है। पाकिस्तान में इन पख्तूनों की आबादी दो करोड़ से भी ज्यादा है।

पाक-पंजाब से है शिकायत

इन तीनों क्षेत्रों की मुख्य शिकायत पाक-पंजाब से है। लगभग 55 प्रतिशत संसाधनों, सेना, राजनीति, न्यायपालिका व उद्योग धंधों पर पाक-पंजाब का कब्ज़ा है। सत्ता के सभी सूत्र पाक-पंजाब के हाथों में हैं। शेष तीनों भागों को सिर्फ शोषण व दमन से बांधा जाता रहा है। विद्रोह, विरोध व अलगाव की अवधारणा, बलूचिस्तान व पख्तूनिस्तान में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। इन्हें लम्बी अवधि तक बंधक बनाए रखना पाक-पंजाब के बस में नहीं है।

सारा प्रकरण भारत के लिए भी दुखद है। एक कमज़ोर, कटा फटा, बगावती तेवर वाला पड़ोसी भी कम खतरनाक नहीं होता। दुखद यह भी है कि हमारे अनेक पीर फकीर भी इसी पाक-पंजाब से रहे हैं। यह बाबा नानक की भी धरती रही है और बाबा फरीद, बुल्लेशाह, फैज़, मंटो, उस्ताद दामन की धरती भी रही है। मगर यह ज़िया उल हक, अयूब खां की भी धरती है जिन्हें इस शेअर में बयान कर सकते हैं-

तुमने खेतों में इन्सानों के सर बोए थे,
अब ज़मीं खून उगलती है तो हैरत क्यों है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी संपादकीय

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

रुपए के निशान पर विवाद !

राजभाषा हिन्दी को लेकर दक्षिण के तमिलनाडु प्रदेश की द्रमुक की एम.के. स्टालिन सरकार जो रुख अपना रही है उसे किसी भी रूप में राष्ट्रहित में नहीं कहा जा सकता। उत्तर और दक्षिण भारत के ऐसे दो ध्रुव हैं जो इस देश की सांस्कृतिक एकता से बंधे हुए हैं इसमें भाषा को लेकर विवाद खड़ा करना किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारतीय संविधान इस देश की सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं को बराबर का सम्मान देता है। इसमें क्षेत्रीय राष्ट्रवाद को ऊपर रखकर सकल राष्ट्रवाद के ऊपर प्रहार करना केवल राजनैतिक हित साधने के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। द्रमुक अपने जन्मकाल से ही हिन्दी विरोधी रही है मगर किसी भी सूरत में इस देश की केन्द्र सरकार ने कभी भी दक्षिण पर हिन्दी लादने की कोशिश नहीं की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हिन्दी को गैर हिन्दी भाषा राज्यों पर लादा नहीं जा रहा है बल्कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता की दृष्टि से जो त्रिभाषा फार्मूला लागू किया जा रहा है उसके सुपरिणाम ही निकल रहे हैं।

उत्तर से दक्षिण जाने वाले भारतीयों को वहां के लोगों के साथ समरस होने में इससे मदद मिलती है और बदले में दक्षिण से उत्तर आने वाले भारतीयों को भी ऐसा ही एहसास होता है। मगर स्टालिन सरकार कह रही है कि केन्द्र की मौजूदा सरकार उन पर हिन्दी लाद रही है। त्रिभाषा फार्मूला 1968 में स्व. इन्दिरा गांधी के शासन के दौरान लागू हुआ था। इसका लाभ यह रहा कि गैर हिन्दी भाषा राज्यों के लोगों को हिन्दी भाषी राज्यों में आने पर काम करने में सुविधा हुई। हिन्दी वैसे भी सबसे सरल और वैज्ञानिक भाषा है। इसे बोलने और लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। यह भारत की हर भाषा से शब्द लेने में यकीन रखती है। मगर जिस प्रकार तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री श्री स्टालिन ने भारत की मुद्रा रुपए के प्रतीक चिन्ह को लेकर विवाद खड़ा किया है वह वास्तव में बहुत चिन्तनीय है और राष्ट्रीय अखंडता के विपरीत है। रुपए का प्रतीक चिन्ह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर व पौंड की तरह पहचाना जाता है लेकिन इसे भारत के ही एक राज्य में बदल कर उसका तमिल रूपान्तरण कर देना किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता। प्रतीक चिन्ह के लिए 2010 में जब वित्त मन्त्री के पद पर भारत रत्न स्व. प्रणव मुखर्जी तो बाकायदा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता हुई थी जिसमें तमिलनाडु के ही युवक डी. उदय कुमार ने बाजी मारी थी और रुपए को एक निशान दिया था। 2010 में यूपीए की मनमोहन सरकार थी जिसमें द्रमुक पार्टी भी शामिल थी। उस समय द्रमुक ने भी इस निशान का सहर्ष स्वागत किया था परन्तु 2025 में श्री स्टालिन इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा केवल राजनैतिक हितों को साधने के लिए किया जा रहा है और तमिल उप-राष्ट्रीयता के भाव को भड़काया जा रहा है। जबकि रुपए का प्रतीक चिन्ह पूरे विश्व में भारतीय मुद्रा को एक विशिष्ट पहचान देता है। ऐसा सब हिन्दी विरोध के नाम पर किया जा रहा है क्योंकि रुपए का प्रतीक चिन्ह हिन्दी देवनागरी लिपी की ही एक सुन्दर कलाकृति है जिसे दक्षिण के ही एक कलाकार ने बनाया। इसमें केन्द्र की मौजूदा सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि 2010 में ही इस निशान को भारत के सभी राज्यों ने अपनाया।

> **रुपए का प्रतीक चिन्ह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर व पौंड की तरह पहचाना जाता है लेकिन इसे भारत के ही एक राज्य में बदल कर उसका तमिल रूपान्तरण कर देना किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता। प्रतीक चिन्ह के लिए 2010 में जब वित्त मन्त्री के पद पर भारत रत्न स्व. प्रणव मुखर्जी तो बाकायदा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता हुई थी जिसमें तमिलनाडु के ही युवक डी. उदयकुमार ने बाजी मारी थी और रुपए को एक निशान दिया था। 2010 में यूपीए की मनमोहन सरकार थी जिसमें द्रमुक पार्टी भी शामिल थी। उस समय द्रमुक ने भी इस निशान का सहर्ष स्वागत किया था परन्तु 2025 में श्री स्टालिन इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा केवल राजनैतिक हितों को साधने के लिए किया जा रहा है**

जहां तक हिन्दी का सवाल है तो दक्षिण के राज्यों के छात्र यदि अपनी मात्रभाषा व अंग्रेजी के अलावा हिन्दी भी पढ़ते हैं तो इसमें बुराई क्या है। हिन्दी के ज्ञान से उन्हें भारत को समग्रता में जानने का बोध ही होता है मगर यह फार्मूला उत्तर भारत के लोगों पर भी लागू होता है। दुखद यह रहा कि 1968 के बाद उत्तर भारत के राज्यों की सरकारों ने विद्यालयों में दक्षिण की कोई एक भाषा पढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, उल्टे अंग्रेजी विरोध के नाम पर अपने छात्रों को अंग्रेजी से दूर रखने का प्रयास किया। अंग्रेजी को ऐच्छिक विषय बना कर उन्होंने विद्यार्थियों के साथ ही अन्याय किया क्योंकि आज पूरे विश्व में भारत की युवा पीढ़ी जिस कम्प्यूटर के साफ्टवेयर की विधा में अग्रणी भूमिका निभा रही है उसके पीछे उसका अंग्रेजी ज्ञान ही है। अत: अंग्रेजी विरोध के नाम पर उसका बहिष्कार करना उचित नहीं था लेकिन श्री स्टालिन ने बात का बत्तंगड़ बनाकर जिस प्रकार हिन्दी का विरोध किया है उसका सम्बन्ध राष्ट्रीय अखंडता से है। निश्चित रूप से जब 1965 में हिन्दी को राजभाषा का व्यावहारिक दर्जा स्व. लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में दिया गया था तो यह भ्रम फैलाया गया था कि अब सारा राजकीय कार्य हिन्दी में ही हुआ करेगा जबकि वास्तविकता इसके विपरीत थी। हिन्दी के साथ अंग्रेजी भी राजकीय भाषा बनी हुई थी। श्री स्टालिन हिन्दी को लेकर जिस तरह से उग्रता दिखा रहे हैं वह उचित नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय अखंडता को अक्षुण्य रखने की कसम उठाकर ही वह मुख्यमन्त्री बने हैं।

उत्तर भारत के लोग दक्षिण के राजनेताओं का भी पूरा सम्मान करते रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु के ही मुख्यमन्त्री रहे स्व. कामराज नाडार है जो कांग्रेस पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। नेहरू काल में लाया गया उनका कामराज फार्मूला हर उत्तर भारतीय को आज भी याद है। यह फार्मूला 1963 में कांग्रेस पार्टी का कायाकल्प करने के लिए तब लाया गया था जब लगभग पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राज था। कामराज राजनीतिज्ञों के लिए आज तक आदर्श माने जाते हैं।

अपने सिद्धांतों और चरित्र को मजबूत...

जब कुछ लोगों को उनका दायरा समझाना पड़ता है,
तो ऐसे हालातों में कभी-कभी सख्त रुख अपनाना पड़ता है,
इतना आसान नहीं है काजल की शीशी के पास रहकर बेदाग रहना,
अपने सिद्धांतों और चरित्र को मजबूत बनाना पड़ता है...!!

गीता पाढा

यूपी की नौकरशाही पर उठे सवाल

मिर्च मसाला
त्रिदीब रमण
gossipguru.in

'विदा लेती शाम ने आसमां के कोतवाल से बस यही चाहा था
जब अंधेरों का शृंगार किए पंख फैलाती यह रात ज़मीं पर उतरे
तो चांद का मुंह काला न हो, पर नासमझ मेघों ने यह भी न होने दिया'

पिछले दिनों अमेरिका में सीपैक (कंजरवेटिव पॉलिटिकल एक्शन कांफ्रेंस) यानी फेडरल एजेंसियों की एक अहम बैठक आहूत थी। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सलाहकार एलन मस्क की बोलने की बारी आई तो उन्होंने नरसंहार के लिए कुचर्चित एक धारधार हथियार 'चैनसॉ' को ब्यूरोक्रेसी की तरफ लहराते हुए यह संकेत दिया कि 'अब ट्रंप सरकार नौकरशाहों के निरंकुश आचरण के पर कतरेगी।' मस्क इस बात से अनजान थे कि सुदूर भारत में भी एक ऐसा ही उपक्रम साधा जा रहा है।

भारतीय नौकरशाही में भ्रष्टाचार की बढ़ती पींगों से सचमुच केंद्र सरकार आक्रांत है और अब इससे निपटने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। माना जाता है कि केंद्र के कहने पर गृह मंत्रालय ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के खुलासे वाकई चौंकाने वाले हैं, अब से पहले भ्रष्ट नौकरशाही के मामले में पहली

अंगुली नार्थ ईस्ट राज्यों की तरफ उठती रही है, इसके बाद भ्रष्टाचार में दक्षिण के राज्यों की ब्यूरोक्रेसी का नंबर आता था।

सूत्र बताते हैं कि गृह मंत्रालय की इस ताजा रिपोर्ट में यूपी की नौकरशाही को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले 10 गुणा तक ज्यादा भ्रष्ट बताया गया है। रिपोर्ट में यूपी के बाकायदा 30 अफसरों का ब्यौरा भी दिया गया है और बताया गया है कि कैसे ये योगी राज में चांदी कूट रहे हैं, वह भी खुल कर।

ट्रंप कार्ड के धनी मस्क

पिछले दिनों एक अंग्रेजी बिजनेस अखबार का अवार्ड समारोह आहूत था, एक बड़े स्टील बैरन की जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने बातों ही बातों में एलन मस्क पर कुछ जबर्दस्त चुटकी ले ली, उनकी चुटीली बातें सुन कर उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे भारत के सबसे बड़े टेलिकॉम टायकून भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वे ठहठाकर हंस पड़े। अभी कार्यक्रम खत्म भी नहीं हुआ था कि टेलिकॉम टायकून के पास एक फोन आ धमका, फोन करने वाले ने उन्हें डपटने वाले अंदाज में कहा-अगर आप वाकई शेर हैं तो सामने आकर वार करो। नीतिगत फैसलों में आप सरकार का समर्थन मांगते हो और कहते हो कि अगर 'स्टार लिंक' भारत आ गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अब जब कि भारत अमेरिका से अपने रिश्ते बेहतर बनाने में जुटा है तो ऐसे में आप लोग प्रेसिडेंट ट्रंप

के सबसे खास व्यक्ति को छेड़ने का जोखिम क्यों उठाना चाहते हैं।'

समय का फेर देखिए इस वाकये के कुछ रोज बाद ही इस भारतीय टेलिकॉम टायकून कंपनी का समझौता मस्क की स्टार लिंक के साथ हो गया, यानी अब स्टार लिंक को भारत में पैर जमाने का मौका इसी भारतीय कंपनी के मार्फत मिलेगा। इस डील के अगले ही रोज मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने भी देश में ब्रॉड बैंड इंटरनेट सर्विस देने के लिए मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से हाथ मिला लिया है यानी स्टार लिंक को भारत में पैर जमाने के लिए अब एक खुला मैदान मिल गया है और दो-दो मजबूत साथी भी।

क्या बीएमसी चुनाव फिर से टल गए?

लगता है मुंबई के स्थानीय निकायों यानी बीएमसी के चुनाव फिर से टल

गए हैं, पहले इस अप्रैल माह में इसे कराए जाने की बात हो रही थी, लेकिन लगता है अब साल के आखिर तक के लिए इसे टाल दिया गया है। सनद रहे कि स्थानीय निकायों में बीएमसी देश का सबसे अमीर कॉरपोरेशन है, इसका सलाना बजट ही 75 हजार करोड़ के आसपास का है, पर पिछले कोई तीन वर्षों से बीएमसी के चुनाव टल रहे हैं। ताजा मामला इसमें 27 फीसदी आरक्षण को लेकर है, राज्य सरकार ने जो आरक्षण व्यवस्था लागू की थी इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

वैसे भी बीएमसी में शिवसेना उद्धव गुट का अब भी अच्छा खासा असर है। भाजपा नेतृत्व उद्धव ठाकरे को अपने पाले में लाने की जद्दोजहद में जुटा है, इसकी पहल देश के एक शीर्षस्थ उद्योगपति के मार्फत हुई है। अगर भाजपा अपने मौजूदा साथियों यानी एकनाथ शिंदे व अजित पवार के साथ मिल कर बीएमसी का चुनाव लड़ती है तो उसे उद्धव, कांग्रेस व शरद पवार की महाअघाड़ी से कड़ी चुनौती मिल सकती है। अगर उद्धव और शरद दोनों ही भाजपा के पाले में आ जाते हैं तो फिर बीएमसी में कमल के नवप्रस्फुटन को भला कौन रोक पाएगा?

राहुल की 'फोटो फिनिश' पहल

राहुल गांधी अपनी राजनैतिक आक्रामकता से कहीं ज्यादा अपने लोक

सरोकारों वाले स्वांग के लिए जाने-पहचाने जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते जैसे ही संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आरंभ हुआ, राहुल अपने सुरक्षा घेरे में संसद भवन पहुंचे, जहां पहले से फोटो पत्रकारों का भारी जमावड़ा जुटा था। राहुल के वहां पहुंचते ही फोटो पत्रकारों में राहुल को कैप्चर करने की होड़ मच गई। राहुल ने देखा कि पत्रकारों के इसी भारी रेलमपेल में एक सबसे वरिष्ठ महिला फोटो पत्रकार शिप्रा दास भी स्ट्रगल कर रही हैं। यह देख कर वह अपने सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए बाहर निकले और सीधे शिप्रा के पास जा पहुंचे और उनका हाथ पकड़ कर अपनी गाड़ी तक ले गए।

राहुल ने उस महिला पत्रकार की लगन व मेहनत की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा, 'इस वक्त तो वे उसे बस यही दे सकते हैं,' राहुल ने गाड़ी में से लाजेंस (पल्स) का एक पैकेट निकाला और उसमें से कुछ लाजेंस शिप्रा के हाथों में रखते हुए कहा-याद रखो जिंदगी भी इसी लॉजेंस की तरह है कभी खट्टी, कभी मीठी, पर आनंद दोनों स्वाद का उठाओ।' राहुल का यह नया दार्शनिक अंदाज देख यह महिला फोटोग्राफर बस हक्का-बक्का रह गई।

कवि का गहरा है भगवा विश्वास

नई पीढ़ी को प्रेम का गीत सुनाने वाले इस कवि ने सफलता के कई नए मानक गढ़े हैं। प्रेम जब अपनी हदों को तोड़ कर स्वतंत्रता के नए उद्घोष में शामिल हो गया तो कवि महोदय रामलीला मैदान के मंच से भी दहाड़े, अन्ना आंदोलन के समर्थन में। ये आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी शुमार रहे। जब केजरीवाल व सिसोदिया संग दोस्ती में दरारें आने लगीं तो वे अपना नया कमल खिलाने में जुट गए, वह भी खालिस भगवा। राम पार्टी संग इतने राममय हो गए कि बाद के दिनों में वाकई 'राम कथा' ही बांचने लग गए, वह भी मोटी फीस के बदले।

पिछले दिनों कवि महोदय की पुत्री का विवाह समारोह संपन्न हुआ, क्या आयोजन था, गणमान्य लोगों की क्या उपस्थिति थी, प्रधानमंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति तक वहां हाजिरी लगाते दिखे। तमाम मुख्यमंत्रियों को भी इस समारोह का निमंत्रण भेजा गया था,

दिल्ली से लगे एक भगवा राज के मुख्यमंत्री को भी इस समारोह का निमंत्रण पत्र मिला तो उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ''ऊपर'' से ही पूछ लेने में भलाई समझी कि 'क्या उन्हें इस विवाह समारोह में जाना चाहिए?' इस पर सीएम साहब को वहां से एक दिलचस्प जवाब सुनने को मिला-'जाइए, बड़े शौक से जाइए, वैसे भी हम इनके गुनहगार हैं, जब कवि महोदय ने पहली बार हम से राज्यसभा मांगी तो हमने मना कर दिया, फिर एमएलसी मांगा, वह भी उन्हें नहीं मिल पाया, फिर जेड प्लस सिक्योरिटी मांगी, वह भी हम दे नहीं पाए, अभी कुछ महीने पहले तक वे अपने लिए पद्म पुरस्कार चाह रहे थे, हमसे वह भी नहीं हुआ।' अब अपने किसी व्यक्ति को इतनी बार 'ना' कहना भी तो ठीक नहीं।'

...और अंत में

2024 के पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों के नए अभ्युदय से भाजपा अपने मिशन 400 के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। अब भगवा पार्टी इसकी काट ढूंढने में लगी है। क्या यह परिस्थितियां उसे 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट' में बदलाव करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं?

भरोसेमंद सूत्रों का दावा है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद देश में त्रिदलीय व्यवस्था लागू हो सकती है। जिससे मुख्यधारा की राजनीति के लिए सिर्फ तीन राष्ट्रीय दल मैदान में रह जाएंगे, इसमें से एक पार्टी होगी भाजपा, दूसरी कांग्रेस व शायद तीसरे पर वामपंथियों का दावा है। सो, ऐसे में छोटे दलों खास कर क्षेत्रीय दलों की

मजबूरी हो जाएगी कि वे इन तीनों दलों में से एक का चुनाव कर उसके साथ मिल कर चुनाव लड़े। इस नई व्यवस्था की एक लाभार्थी कांग्रेस भी हो सकती है जिनका एक बड़ा वोट बैंक क्षेत्रीय पार्टियों ने गड़प लिया है।

असम कांग्रेस प्रवक्ता रीतम सिंह सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार

गुवाहाटी/उत्तर लखीमपुर, (पंजाब केसरी) : कांग्रेस की असम इकाई के प्रवक्ता रीतम सिंह को शनिवार को उस सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उन्होंने दो वर्तमान विधायकों समेत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। सिंह को गुवाहाटी पुलिस की सहायता से लखीमपुर जिला पुलिस की एक टीम ने गुवाहाटी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक मिहिरजीत गायन ने बताया कि भाजपा विधायक मनाब डेका की पत्नी द्वारा दो दिन पहले 'एक्स' पर एक पोस्ट को लेकर की गई शिकायत

के बाद सिंह को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने कहा, ''हमने उन्हें कानून की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अब लखीमपुर लाया जा रहा है।'' सिंह ने 13 मार्च को 'एक्स' पर उस खबर के साथ पोस्ट की थी जिसमें 2021 में धेमाजी जिले में बलात्कार के एक मामले में अदालत द्वारा तीन व्यक्तियों को दोषी ठहराए का जिक्र था।

कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट में पूछा था, ''इन दोषियों को वह सजा मिली जिसके वे हकदार थे। लेकिन असम भाजपा ने मनाब डेका, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भाबेश कालिता, पूर्व मंत्री राजेन गोहेन जैसे मंत्रियों और विधायकों पर क्या आरोप लगाया है। क्या कानून सबके लिए समान है।'' इस वर्ष जनवरी तक असम भाजपा के अध्यक्ष रहे कालिता विधायक हैं, जबकि गोहेन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे।

हिमाचल : कांग्रेस के पूर्व विधायक को गोली मारी

बिलासपुर, (भाषा): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को उनके घर पर अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

हमले में ठाकुर और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए। ठाकुर के पैर में गोली लगी है और उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) रेफर किया गया है, जबकि उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) को बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ले जाया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना पर संज्ञान लेते हुए कहा, ''मैंने बंबर ठाकुर से बात की है और उनसे एम्स जाने का आग्रह किया है, लेकिन वह आईजीएमसी शिमला में इलाज कराना चाहते हैं। उपायुक्त को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।'' मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा, ''गोलीबारी की घटना के पीछे जो लोग हैं, उन्हें पकड़ने के लिए सड़कों और फोरलेन पर अवरोधक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।''

बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया है। कांग्रेस नेता के बड़े भाई देश राज ठाकुर ने बताया कि बंबर ठाकुर पिछले एक साल से मादक पदार्थों के व्यापार, विशेषकर 'चिट्टा (मिलावटी हेरोइन)' के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्होंने असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

शगुन के मौके पर लूटपाट के 'अपशकुन'

श्रीमती किरण चोपड़ा
डायरेक्टर- पंजाब केसरी दैनिक समाचार लि.
चेयरपर्सन- वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब
मुख्य संरक्षिका- चौपाल
सदस्या- राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल, एकल
संरक्षिका- भारतीय लोक विकास परिषद
/kiranchopra01
kiranchopra@punjabkesari.com
kiranchopradesk@gmail.com

आजकल कम्प्यूटर युग में डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम, बैंक खातों से मनी ट्रांसफर और एप बनाकर लूटपाट के किस्से बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन शादियों जैसे शगुन के मौके पर लुटेरे खुशी को गम में बदलते हुए कुछ ही सैकेंडों में लाखों रुपए लूट कर दूल्हा-दुल्हन वालों के यहां ज्वैलरी और महंगे सामान से भरी अटैची और सामान लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने इसे नाम दिया है-बैंड-बाजा-बारात गैंग। पुलिस के रिकॉर्डों में इनकी लूटपाट के तरीके एफआईआर के रूप में दर्ज हैं और रिकॉर्ड बताते हैं कि पूरे भारत में इस बैंड-बाजा-बारात के सदस्य सक्रिय हैं। जब आप सोशल मीडिया पर इसके किस्से सुनेंगे तो पिछले दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में 8 अगस्त 2024 से लेकर 25 फरवरी 2025 तक अलग-अलग घटनाओं में एक करोड़ से ज्यादा का माल चाहे वह कैश, ज्वैलरी या महंगे कपड़े क्यों न हों इस बैंड-बाजा-बारात गैंग ने अपने हाथ साफ किए हैं। इनका लूट का तरीका बहुत ही अजीब है और बहुत ही अपनेपन और प्रेम की भावना से भरा हुआ है।

किसी भी शादी या रिसेप्शन के मौके पर गिरोह के सदस्यों ने दो या तीन सुन्दर लड़के और दो या तीन संभ्रांत महिलाएं वर या वधू पक्ष के यहां जुड़कर मुस्कुराते हुए बातें करने लगते हैं। पुलिस रिकार्ड बताते हैं कि जब स्टेज पर फोटो खिंचवाने का वक्त आता है या मिलनी के वक्त शगुन चल रहा होता या रिंग सैरेमनी के मौके पर दोनों पक्ष पूजा के मंच पर व्यस्त हो जाते हैं तो इस गैंग के सदस्य भी अपनी कारीगरी में जुट जाते हैं। सुन्दर-स्मार्ट संभ्रांत महिलाएं, पुरुष और बच्चे सबसे ज्यादा गम्भीरता से अपने टारगेट पर निगाह रखते हैं। शगुन के इस खास मौके पर ये लोग कैश, नगदी और कीमती सामान के बैग अपने पास रखने

वाले लोगों से मुस्कराकर बातें करते हुए उनकी मदद में हाथ बंटाते हैं। दोनों पक्ष यह सोच रहे होते हैं कि यह हमारे शुभचिंतक हैं। लड़की वाले सोचते हैं कि लड़के वालों के यह रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं जबकि लड़के वाले इन लोगों को लड़की वालों के रिश्तेदार समझकर इन पर भरोसा करते हुए अपना सामान व्यस्त रहने की वजह से सम्भालने को भी कह देते हैं। पंडित पूजा में व्यस्त होता है और दोनों पक्षों की पूजा या फिर मिलन कार्यक्रम चल रहा होता है। यह बैंड-बाजा-बारात गैंग के लिए सामान पर हाथ साफ कर देने का एक शानदार अवसर होता है।

पिछले दिनों पंजाब के एक शहर में ऐसे ही लुटेरों को लोगों ने कीमती सामान से भरा बैग अपने साथ ले जाते हुए देखा तो सतर्क लोगों ने शादी स्थल के गेट पर ही धरदबोचा। इन लोगों की खूब पिटाई हुई तो इनके लूटपाट का अंदाज सामने आ गया। मैं आप लोगों के सामने कोई कहानी नहीं कह रही बल्कि पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज एफआईआर और सोशल मीडिया पर लोगों की कहानियों के आधार पर असलियत बता रही हूं जिसमें पीड़ित पक्षों ने यह भावनाएं व्यक्त की हैं।

दरअसल महिला, पुरुष और नाबालिग लड़का या लड़की यह सब बैंड-बाजा-बारात गैंग के सदस्य हैं और इनको इस सारे कांड की ट्रेनिंग मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से 45 किलोमीटर दूर कड़िया सासी, गुलखेड़ी और हुलखेड़ी गांव से हैं, जहां पुलिस ने जांच-पड़ताल के आधार पर बताया कि यह गिरोह शादियों में लूटपाट के लिए कुख्यात है। मध्य प्रदेश में पुलिस को कई राज्यों से मिली शिकायत के बाद जागरूकता अभियान भी चलाए गए। पता चला है कि गिरोह के यह लोग छोटे बच्चों को व्यस्क बनने तक इस तरीके की लूटपाट के लिए ट्रेनिंग देते हैं। आज के समय में यह एक ट्रेंड बन चुका है कि शादियों के मौके पर बैंड-बाजा-बारात गैंग गिरोह के सदस्य देशभर में सक्रिय हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पूरे देश में 400 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश, राजस्थान यह लोग बड़े घरों या छोटे घर हर किसी के यहां शादी के मौके पर ही अपना दांव खेलते हैं। राजस्थान के एक फाइवस्टार होटल में महज 14 साल का एक बच्चा डेढ़ करोड़ रुपए के दो बैग वधू पक्ष के यहां से उड़ाकर ले गया। पुलिस टीम ने राजगढ़ के कड़िया गांव पहुंच कर सारा मामला हल किया। यह गैंग फाइस्टार में भी सेंध लगा सकता है।

सोशल मीडिया पर कई भुक्तभोगियों ने ऐसे लूटपाट के किस्से शेयर किए तो मेरी इस मामले में एक ही सलाह है कि अगर वधू या वर पक्ष के यहां कोई भी अनजान लोग घुसने की कोशिश करते हैं तो दोनों पक्षों के सदस्यों का फर्ज बनता है कि वह अलर्ट हो जाएं। आज के जमाने में सुरक्षा ही सबसे बड़ी सावधानी है। जब पता है कि किसी भी शादी, रिंग सैरेमनी और रिसेप्शन या शगुन के मौके पर ज्यादा मेहमान आ रहे हैं तो मेजबान लोगों को अपने मेहमानों पर प्रेमपूर्वक लेकिन सतर्कता से नजर रखनी होगी। बचाव में ही बचाव है, तभी आप शगुन के मौके पर लूटपाट जैसे अपशकुन से बच सकते हैं।

मणिपुर: काकचिंग जिले से उग्रवादी गिरफ्तार

इंफाल, (भाषा): मणिपुर पुलिस ने काकचिंग जिले से एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के सदस्य को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के इस कैडर को शुक्रवार को काकचिंग जिले के लांगमेइदोंग मामांग लाइकाई से पकड़ा गया।

अधिकारियों ने कहा कि चुराचांदपुर जिले के डांपी रिज इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए एक अन्य अभियान में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया जिनमें एक राइफल, एक 'सिंगल-बैरल'' बंदूक और दो आईईडी शामिल हैं। राज्य में लूटे गए, छीने गए या अवैध हथियारों को बरामद करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी बर्बाद हो गया था। युद्ध के बाद जर्मन लोगों ने हिटलर का रास्ता छोड़ा और आज जर्मनी यूरोप का सबसे धनी देश है। जर्मन अगर नफरत के रास्ते पर चले होते तो दूसरे विश्वयुद्ध के विनाश से कभी उबर न पाते।

—प्रशांत टंडन, पत्रकार @PrashantTandy

कृषि

भारत डोगरा

टिकाऊ और सस्ती तकनीक है कारगर

माली राम ऐसे भील आदिवासी किसान हैं, जो देखने-सुनने में बहुत साधारण लगते हैं पर प्राकृतिक खेती के प्रति उनकी निष्ठा और इस क्षेत्र में खिल रही उनकी रचनात्मकता के कारण दूर-दूर के लोग उनसे कुछ न कुछ सीखने आते रहते हैं। दुल्कीबाई और परिजनों के साथ उन्होंने अपने छोटे से 3 बीघे के खेत को प्राकृतिक खेती की कर्मभूमि बना दिया है। कटारों का खेड़ा नाम से इस परिवार का गांव राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा प्रखंड में है। इस प्रखंड में अनेक गांवों ने प्राकृतिक खेती और बागवानी विशेषकर फलों के बगीचों की ओर महत्त्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं, जिससे टिकाऊ खेती और पोषण सुधार की महत्त्वपूर्ण संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं।

माली राम जैसे छोटे और कम संसाधन वाले किसान अपने बेहद रचनात्मक प्रयासों से यह बना रहे हैं और सिखा रहे हैं कि कम भूमि और संसाधनों की स्थिति में भी मेहनत और समझदारी से संतोषजनक आजीविका प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने गाय और बैल पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बहुस्तरीय सब्जी उत्पादन, फलों के बगीचे और गेहूं, मक्के, दलहन, मूंगफली जैसी फसलों को मात्र 3 बीघे में ऐसे समेटा है कि उपलब्ध भूमि और संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग हो तथा नकदी खर्च कर्ज के बोझ से यथासंभव बचा जा सके। मुख्य रूप से गोबर और गोमूत्र के आधार पर खाद और हानिकारक कीड़ों से बचाव का प्रबंध किया जाता है। परंपरागत कुएं से सिंचाई की जाती है। लगभग 200 फलदार पेड़ लगाए हैं, जिनमें अमरूद, आम, नींबू, कटहल आदि के पेड़ हैं। बहुस्तरीय सब्जी उत्पादन में धरती पर, धरती के भीतर और ऊपर चढ़ने वाली बेलों में उगने वाली लगभग 15 सब्जियों को मिला कर उगाया जाता है। विभिन्न तरह के कार्य एक दूसरे के पूरक और सहायक है। माली राम कहते हैं कि छोटे-छोटे इन खेतों को एक-एक बीघा कर वे प्राकृतिक खेती की ओर ले आए हैं। उनके मुख्य खेत से दूर भी एक खेत है, बाद में उस पर ऐसे ही बदलाव करेंगे। उनकी देखा-देखी उनके भाई और पड़ौसी भी प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े हैं। उन्हें प्रशिक्षक के रूप में कार्यक्रमों में बुलाया जाता है।

माली राम ने बताया कि प्राकृतिक खेती अपना कर उन्होंने अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा की, दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा की और मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा की। वे अपने कृषि कार्य के प्रति इतने समर्पित हैं कि एक-एक पेड़ या क्यारी दिखा कर अपने रचनात्मक कार्य और प्रयोग के बारे में बताना चाहते हैं और साथ में यह भी बताते जाते हैं कि किस प्रयोग को दूसरे किसान भी अपनाएं तो उन्हें क्या लाभ मिलेगा। हालांकि देश में चर्चा तो किसान संकट की अधिक है, पर माली राम जैसे किसानों की ओर ध्यान देना इसलिए आवश्यक है कि वे इस संकट से बाहर निकलने के ऐसे रास्ते के बारे में बताते हैं जो खेती और बागवानी को टिकाऊ और सस्ता बनाने, मिट्टी की रक्षा करने और उपलब्ध सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करने से जुड़ा है। माली राम की तरह इस प्रखंड के अनेक अन्य किसान विशेषकर मीणा आदिवासी किसान भी इस तरह के प्रयोगों से आगे की बेहतर राह निकाल रहे हैं। इन प्रयासों में महिलाओं की विशेष उत्साहवर्धक भागेदारी है। सुहागपुरा प्रखंड में 'सृजन' संस्था की सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने प्राकृतिक और टिकाऊखेती, बागवानी और पर्यावरण रक्षा की प्रगति को अनेक गांवों में पहुंचाया है। तीन वर्षों में 140,000 फलों के पेड़ लगाए गए हैं और फलों, सब्जी, किचन गार्डन का कार्य प्राकृतिक खेती के तौर-तरीकों से ही प्रसारित है। सामान्य कृषि में भी प्राकृतिक पद्धतियों का प्रसार हो रहा है। सोलर पंप सेट और स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रसार से सिंचाई को बेहतर किया जा रहा है। कुछ किसान तीसरी फसल भी लेने लगे हैं जिसमें मूंग, दाल आदि का उत्पादन बढ़ा है।

प्राकृतिक खेती अपनाने से आरंभ में कुछ समस्या आती हैं, अतः वे एक बार में नहीं छोटे-छोटे बदलाव कर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय बाद प्राकृतिक खेती में स्थिरता आ जाती है और उत्पादन अच्छा होने लगता है और खर्च कम हो जाता है। इसी तरह सामान्य खेती की जगह अमरूद जैसे फल के बगीचे प्राकृतिक तौर-तरीकों से लगाने से शुरू में कुछ गांववासियों को कठिनाई आई, पर इसका समाधान प्राप्त किया गया कि आरंभिक वर्षों में फलों के पेड़ों के बीच में अन्य फसलों को भी उगा लिया गया ताकि जब तक पेड़ों से फल न प्राप्त हो गाएं, तब तक फसलों का उत्पादन प्राप्त होता रहे। इस तरह प्राकृतिक और विविधता भरी खेती में कोई समस्या आती है तो आपसी विमर्श और भागेदारी से समाधान भी प्राप्त किए जाते हैं। इन गांवों में आपसी विमर्श और भागेदारी बढ़ी है

कल्याणपुरा गांव में एजन नामक अधिक सक्रिय महिला किसान ने बताया कि हमें विभिन्न फलों और सब्जियों के उत्पादन, भोजन में तरह-तरह की सब्जियों के शामिल होने से और खर्च का भार कम करने से इतना उत्साह मिला कि हम बहुत मेहनत करके भी अधिक प्रसन्न थे। लक्ष्मीबाई ने बताया कि किचन गार्डन से इतनी सब्जियां प्राप्त हुईं कि पोषण सुधार के साथ बिक्री से अच्छी आय भी हो सकी। 'सृजन' के स्थानीय समन्वयक प्रेमनाथ योगी बताते हैं कि यहां महिला उत्पादक समूह बनाए गए हैं। वे आगे चल कर विभिन्न कृषि और बागवानी उत्पादकों के प्रसंस्करण के कार्य आगे बढ़ाएंगे। डोल्माश्री नाम के ऐसे एक समूह की तैयारी है कि महुआ का तेल स्थानीय स्तर पर निकाला जाए ताकि गांववासियों का खर्च कम हो, उन्हें शुद्ध तेल प्राप्त हो और साथ में खली भी उनके पास रहे। एक अन्य प्रमुख कार्यकर्ता मोहम्मद सकीब बताते हैं कि गांववासियों का उत्साह अनेक नये कार्यों में भी आगे बढ़ने के लिए है जैसे परंपरागत बीजों का संग्रहण। सेमलिया खुर्द में अंबालाल और चंबा बाई जैसे अनेक किसान हैं, जिनमें उत्पादन और प्राकृतिक खेती की बढ़ती उपलब्धियों से बहुत उत्साह है। इस गांव में सोलर पंप और स्प्रिंकलर कृषि अपनाने से भी सिंचाई बेहतर करने और उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है। सामूहिक चर्चा में यहां के अन्य गांववासियों ने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने से आरंभ में कुछ समस्या आती हैं, अतः वे एक बार में नहीं छोटे-छोटे बदलाव कर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय बाद प्राकृतिक खेती की स्थिरता आ जाती है और उत्पादन अच्छा होने लगता है और खर्च कम हो जाता है। इसी तरह सामान्य खेती की जगह अमरूद जैसे फल के बगीचे प्राकृतिक तौर-तरीकों से लगाने से शुरू में कुछ गांववासियों को कठिनाई आई, पर इसका समाधान प्राप्त किया गया कि आरंभिक वर्षों में फलों के पेड़ों के बीच में अन्य फसलों को भी उगा लिया गया ताकि जब तक पेड़ों से फल न प्राप्त हों, तब तक फसलों का उत्पादन प्राप्त होता रहे।

इस तरह प्राकृतिक और विविधता भरी खेती में कोई समस्या आती है तो आपसी विमर्श और भागेदारी से समाधान भी प्राप्त किए जाते हैं। इन गांवों में आपसी विमर्श और भागेदारी बढ़ी है। समूहों के माध्यम से और पारदर्शिता से कार्य करने से आपसी विश्वास भी बढ़ा है। प्राकृतिक खेती अपनाने के साथ खेत पर अपनी खाद बनाने और कीड़ों से बचाव करने के ऐसे प्रयास बढ़ रहे हैं, जिनमें पर्यावरण की कोई क्षति न हो अपितु पर्यावरण की रक्षा हो। इन विविध कार्यों के बीच किसानों की रचनात्मकता और प्रयोग कर सीखने की क्षमता भी बढ़ती है, इस तरह की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। इस तरह के विविधता भरे खेत और बगीचों के बीच रचनात्मकता के कार्य करते हुए किसान अधिक संतुष्ट और प्रसन्न हैं। इन दिनों अधिक चर्चा का विषय यह है कि फल, सब्जी उत्पादन की संभावना बढ़ने के बीच सिंचाई के पानी की कमी के कारण कई बार बहुत समस्याएं आ जाती हैं, हालांकि कुछ गांवों में सृजन और जल-संरक्षण के प्रयास भी तेज किए हैं, पर कुछ अन्य गांवों में सिंचाई की कमी बनी हुई है। अतः आगामी दिनों में इन गांवों में भी जल संरक्षण पर अधिक ध्यान देना होगा।

बुरा न मानो होली है

मीडिया

सुधीश पचौरी

इस होली के दिन साफ हुआ कि 'बुरा न मानो होली है' में 'बुरा न मानने वाले' कौन हो सकते हैं और 'बुरा मनवाने वाले'...और जब इस होली के दोपहर बाद जब खबर आई कि होली का जलूस संभल मस्जिद के सामने से शांतिपूर्वक गुजर गया है तो बहुतों को राहत महसूस हुई

कुछ पहले तक 'होली' के आसपास एक ही वाक्य सुनाई पड़ा करता था कि 'बुरा न मोनो होली है...'। लेकिन इस बार होली का यह 'चेतावनी वाक्य' कम ही सुनाई पड़ा। यों, इन दिनों 'होली' के 'दो संस्करण' नजर आते हैं : एक वो, जिसे लोग गली-मुहल्लों में खेलते हैं, दूसरा वो जो 'मीडिया' में प्रसारित होता दिखती है। और, इसी प्रक्रिया में यह अपने आप साफ होता गया कि 'बुरा न मानो होली है' का असली अर्थ क्या है और क्यों है? होली के आसपास चैनल और रिपोर्टर बताते दिखाते रहे कि इस बार होली उसी दिन है, जिस दिन जुमे की नमाज पढ़ी जानी है यानी उस दिन 'तनाव' हो सकता है...कुछ 'अनहोनी' भी हो सकती है। खबरें यह भी बताती रहीं कि संभल के कई संवेदनशील इलाकों में कुछ मस्जिदें तिरपाल से ढंकी गई हैं...यूपी के बारह जिलों में सुरक्षा का भारी बंदोबस्त किया गया ताकि सब शांति से निपट जाए।

मीडिया के जरिए प्रशासन पब्लिक से कहता रहा कि होली शांति से मनाएं...'डीजे वीजे' का शोर कम करें...होली ढाई बजे तक मनाई जाए और नमाज ढाई बजे के बाद पढ़ी जाए ताकि किसी को शिकायत न हो...कुछ दिन पहले एक पुलिस अफसर ने संभल में होली के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कह दिया कि जो होली न खेलते हों वे घर से बाहर न निकलें यानी घर में ही नमाज पढ़ें...ऐसी 'समझाइश' ने चैनलों में विवाद आमंत्रित किया और इस बार की होली एक 'तनाव भरे वातावरण' में होती दिखी।

ऐसे तनाव भरे वातावरण पहले भी रहे होंगे। ऐसे ही तनावग्रस्त वातावरणों को नियंत्रित करने के लिए कभी कहा गया होगा कि होली जब भी खेलें दूसरों को सावधान करते हुए खेलें, इसलिए हमेशा कहें कि बुरा न मानो होली है...। इसका अर्थ यह भी हुआ कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो होली खेलना पसंद न करते हों...इसी तरह इस होली के दिन साफ हुआ कि 'बुरा न मानो होली है' में 'बुरा न मानने वाले' कौन हो सकते हैं और 'बुरा मनवाने वाले'...और जब इस होली के दोपहर बाद जब खबर आई कि होली का जलूस संभल मस्जिद के सामने से शांतिपूर्वक गुजर गया है तो बहुतों को राहत महसूस हुई।. इसीलिए चैनलें कहते रहे कि होली सौहार्द्रपूर्ण तरीके से मनाई गई। एकाध जगह हुए तनाव की खबर आई तो भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो उसको सिर्फ 'अपवाद' की तरह माना।

'बुरा न मानो होली है' का 'एक और अर्थ' भी हो सकता है और वह है बरसाने की 'लठमार होली' जिसमें 'ब्रज क्षेत्र' के 'नांव' के 'गोप' (हुरिहारे) बरसाने की 'गोपियों' को पहले छेड़ते हैं, फिर गोपियां ग्वालों पर लट्ठ बरसाती हैं लेकिन ऐसी छेड़छाड़ और लट्ठपिटाई का कोई बुरा नहीं मानता...'लठामार होली' इस बार भी लाइव दिखी और उससे भी समझ में आया कि 'छेड़ना' और 'लट्ठ मारना', दोनों में ही कुछ 'जबर्दस्ती' के भाव छिपे हैं। हो सकता कि पहले कभी ऐसे छेड़ने, लट्ठ मारने को बुरा माना जाता हो और इसीलिए कहा जाता हो कि 'बुरा न मानो होली है' ताकि जो ऐसा नहीं मानते वे भी समझ लें कि होली में ऐसा कुछ भी हो सकता कि 'बुरा लगे'! शायद इसलिए पहले ही कह दिया जाता था कि 'बुरा न मानो होली है...' ताकि सामने वाला सावधान रहे। पहले के लोग शायद बड़े दिल वाले होते हों कि किसी के छेड़ने, रंग डालने पर बुरा न मानते हों, लेकिन जब से समाज में सहनशीलता कम हुई है और लोग जरा जरा सी बात को अपने 'ईगो' पर लेने लगे हैं तब से 'बुरा न मानो होली है' कहने का भी कोई मतलब भी नहीं रह गया है। मैं सोचता रहा कि अपनी होली में 'बुरा' मानने के लिए ऐसा क्या है कि खेलने से पहले बोलना पड़े कि 'बुरा न मानो होली है...'। यों होली मनाने या नमाज पढ़ने में कुछ बुरा नहीं है लेकिन जब से होली या नमाज 'अस्मितावादी ताकत की राजनीति' से जुड़ी है, वोट बैंक से जुड़ी है, तब से जब जो चाहे दूसरे में जरा जरा सी बात में बुराई खोज सकता है हर बात में 'दूसरे की बुराई' खोजने वालों को कभी कबीर ने समझाया था : 'बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय/जो दिल खोजों आपना, मुझसा बुरा न कोय!' यानी, जब तक हम अपने अंदर की बुराई न देखेंगे, तब तक दूसरों में ही बुराई देखते रहेंगे और डरी हुई होली खेलते-देखते रहेंगे जबकि होली मस्ती, बंधहीन और एक दिन के लिए पूरी तरह आजाद हो जाने का त्योहार है।

ट्रंप-पुतिन की जुगलबंदी

वैदेशिकी

डॉ. दिलीप चौबे

यूरोपीय नेताओं को इस बात का भान है कि वे राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सीधे रूप से मुहिम चलाने की स्थिति में नहीं हैं। उनकी कोशिश है कि राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी यूक्रेन नीति में ही फंसाया जाए। इसी रणनीति के तहत यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को स्वीकार किया है

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत उलटफेर हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन के बीच जुगलबंदी आकार ले रही है। दुनिया में यदि सकारात्मक माहौल होता तो यह नया समीकरण शांति और स्थिरता का नया दौर शुरू हो सकता है। लेकिन अमेरिका की घरेलू राजनीति और यूरोप के देशों के नकारात्मक रवैये के कारण इस आशा पर संदेह खड़ा होता है। प्रयास इस बात का है कि ट्रंप के रूस समर्थक रवैये को पलटा जाए तथा अमेरिका और रूस को आमने-सामने खड़ा किया जाए। अमेरिका का डीप स्टेट और यूरोपीय देश प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इसी कवायद में लगे हैं।

ट्रंप को मिले भारी जनादेश के बावजूद यह मानना सही होगा कि अमेरिका में डीप स्टेट पराजित हो गया है। डीप स्टेट वास्तव में अमेरिका का सैनिक और औद्योगिक तंत्र है जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करता रहा है। यह तंत्र किसी भी राष्ट्रपति को बाध्य करता है कि वह दुनिया पर दबदबा कायम करने की नीतियों पर चलता रहे। यूरोप के अधिकतर देश इस डीप स्टेट के स्वाभाविक मित्र या सहयोगी हैं। ट्रंप प्रशासन ने डीप स्टेट पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाना शुरू किया है, लेकिन यह अभी प्रारंभिक दौर में है। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड और संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के प्रमुख काश पटेल पर यह प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी है कि वे डीप स्टेट को काबू में करें। उन्होंने अपनी ओर से कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। तुलसी गबार्ड ने हाल में खुफिया संस्थाओं की सूचनाओं को लीक करने वाले लोगों को चेतावनी दी है। वास्तव में अमेरिका की नौकरशाही में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रंप विरोधी हैं तथा डीप स्टेट के लिए काम करते हैं। इनको पूरी तरह समाप्त करना असंभव है। अधिक से अधिक उन पर अंकुश ही लगाया जा सकता है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए प्रयास शुरू किये हैं, तभी से उनके खिलाफ मुख्यधारा की मीडिया ने अभियान शुरू कर दिया है। शायद ही किसी राष्ट्रपति को ऐसे दुष्प्रचार का सामना करना पड़ा हो। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों की मीडिया भी ट्रंप प्रशासन की साख कम करने में लगी है। पर्दे के पीछे से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी ट्रंप के खिलाफ शतरंज की चालें चल रहे हैं। यूरोपीय नेताओं को इस बात का भान है कि वे राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सीधे रूप से मुहिम चलाने की स्थिति में नहीं हैं। उनकी कोशिश है कि राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी यूक्रेन नीति में ही फंसाया जाए। इसी रणनीति के तहत यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अब यूरोपीय देश इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि गेंद रूस के पाले में है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के शांति प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। इन हालात में राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बनाया जाएगा कि वह रूस के खिलाफ नये प्रतिबंध लगायें। संभवतः राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन इस पूरे खेल को समझ रहे हैं। यही कारण है कि दोनों ने एक-दूसरे के प्रति सकारात्मक रुख अपना रखा है। यूरोपीय देशों का मानना है कि यदि यूक्रेन युद्ध एक साल तक और चले तो रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। नये प्रतिबंध लगने पर रूस आर्थिक रूप से इस स्थिति में नहीं होगा कि बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई जारी रख सके। दूसरी ओर, राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त कराना चाहते हैं। वास्तव में यह चुनाव बयान था लेकिन इसकी भावना निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। यह भी सचाई है कि यदि अमेरिका के तत्कालीन प्रशासन और यूरोपीय देशों ने कूटनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया होता तो यूक्रेन युद्ध शुरू ही नहीं होता।

इस बीच युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन के लिए बुरी खबर है। यूक्रेन ने रूस के जिस कुर्स्क क्षेत्र पर कब्जा किया था, वहां उसके हजारों सैनिक घिर गये हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से अनुरोध किया है कि इन सैनिकों पर रहम किया जाए। राष्ट्रपति पुतिन ने इस पर कहा है कि यदि ये सैनिक आत्मसमर्पण कर दें तो इन्हें बख्श दिया जाएगा। इस विषम परिस्थिति में भी यूरोप के नेता यूक्रेन से कह रहे हैं कि पीछे मत हटना, लड़ते रहो।

गुड़-गोबर होती देश की राजनीति

बहस

डॉ. सत्यवान सौरभ

बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास जैसी चिंताओं के बीच एक परेशान करने वाला नया चलन सामने आया है, राजनीतिक दलों की वादाखिलाफी तथा नेताओं की अमर्यादित भाषा का। राजनीतिक दल अपने वादे पूरे करने में विफल रहे हैं, और नेता अनुचित भाषा का सहारा ले रहे हैं। लगता है कि नेता सिर्फ दिखावटी बन कर रह गए हैं, जो असली मुद्दों को हल करने की उपेक्षा कर रहे हैं। अतीत में, राजनेता अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते थे, और राजनीति में जो संस्कृति, सभ्यता और शालीनता की भावना थी, वो अब गायब हो गई है। आजकल, नेता अक्सर व्यक्तिगत हमलों में शामिल होते हैं, विमर्श की सीमा को पार करते हैं। आज कुछ नेता अपने विरोधियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, जबकि अन्य आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी टिप्पणियां स्वस्थ और रचनात्मक राजनीति के आदर्शों को धूमिल करती हैं। क्या ये नकारात्मक प्रभाव हमारी राजनीतिक व्यवस्था में स्वीकार्य हैं? क्या राजनीति में ये दाग अच्छे हैं?

हरियाणा विधानसभा में नेताओं द्वारा 'गोबर पीने वाले' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। चुनाव के मंच पर आरोप-प्रत्यारोप के अलावा व्यक्तिगत हमले अब संसद और विधानसभाओं में भी होने लगे हैं। हरियाणा विधानसभा में राजकुमार गौतम ने गोहाना में मिलावटी जलेबी बनने की बात कही, तो गोहाना के विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि गौतम तो गोबर भी पीते हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें जलेबी की गुणवत्ता की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग सार्वजनिक धन की कीमत पर तुच्छ काम कर रहे हैं। जागरूक मतदाताओं से ही राजनीतिक विमर्श में सुधार हो सकता है। यह कोई अकेली घटना नहीं है; कई नेताओं ने पहले भी विवादित टिप्पणियों से राजनीतिक क्षेत्र को कलंकित किया है। राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन वे तेजी से स्पष्ट कलह में बदल रहे हैं। नेताओं को याद रखना चाहिए कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों में सबसे कटु बात का उत्तर शालीनता से देने का कौशल था। एक नेता की असली क्षमता अक्सर उसके शब्दों के चयन में झलकती है। अगर राजनीतिक नेता यह पढ़ रहे हैं, तो उन्हें यह पहचानना चाहिए कि भाषा का सम्मान उनका कद बढ़ाता है, जबकि अशिष्टता इसे कम करती है। समर्थक भले ही व्यक्तिगत चुटकुलों का स्वागत करें, लेकिन समझदार मतदाता-जो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं-एक ऐसे नेता की स्थायी छाप बनाते हैं, जो बाद में चाहे कितनी भी सकारात्मक बातें क्यों न कही जाएं, अपरिवर्तित रहता है। राजनीति में भाषा के बिगड़ने से सवाल करने की क्षमता खत्म हो गई है, क्योंकि नेता अपने बयानों को पूर्ण सत्य के रूप में देखते हैं। वाजपेयी और इंदिरा गांधी जैसी हस्तियों की वाक्पटुता आज भी लोगों को प्रभावित करती है। दुर्भाग्य से, विरोधी दलों पर तीखे हमले समाज में केवल कलह और अशांति पैदा करते हैं। चुनाव आयोग के लिए ऐसे मानक स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है, जो अनुचित टिप्पणी करने वाले नेताओं पर सख्त दंड लगाते हैं। जनता को यह भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसा नेता, जो कठोर और अपमानजनक भाषा का सहारा लेता है, लोकतंत्र के मंदिर में जगह पाने का हकदार है। लोकतंत्र में नेता अपनी शक्ति और अधिकार जनता से प्राप्त करते हैं, जिसका वे प्रयोग भी कर सकते हैं, और दुरुपयोग भी कर सकते हैं।

नदियों को विवाद नहीं, विकास का जरिया बनाएं

मसला

ललित गर्ग

नदियां मानव अस्तित्व का मूलभूत आधार हैं, और देश एवं दुनिया की धमनियां हैं, इन धमनियों में यदि प्रदूषित जल पहुंचेगा तो शरीर बीमार होगा। लिहाजा, हमें नदी रूपी इन धमनियों में शुद्ध जल के बहाव को सुनिश्चित करना होगा। नदियों के समक्ष आने वाले खतरों जैसे प्रदूषण, आवास की क्षति और जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 मार्च को 'नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस' मनाया जाता है, जो नदियों और उनके संरक्षण के लिए एक वैश्विक मंच है, ताकि नदियों और समुदायों की एकजुटता बढ़ाई जा सके और नदियों के महत्त्व के बारे में जागरूकता लाई जा सके। इस वर्ष इस दिवस की थीम 'हमारी नदियां, हमारा भविष्य' है। इस दिवस की शुरुआत 14 मार्च 1997 को कुर्टिबा, ब्राजील में बांधों से प्रभावित लोगों की पहली अंतरराष्ट्रीय बैठक में हुई थी।

यह दिन व्यक्तियों और संगठनों को नदी संरक्षण की दिशा में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। वर्तमान में भारत सहित दुनिया की तमाम नदियों के सामने जहां प्रदूषण व अतिक्रमण जैसी भयावह चुनौतियां खड़ी हैं, वहीं उनमें निरंतर घट रही पानी की मात्रा भी गंभीर चिंता में डालने वाली है। कस्बों व शहरों के घरेलू, औद्योगिक कचरे एवं बेहिसाब गंदगी के कारण नदियों ने गंदे नाले का रूप लेना शुरू कर दिया है। हमारी जिन नदियों ने नालों का रूप धारण कर लिया है, उन्हें पुनः नदी बनाने की जरूरत है। समूची दुनिया में पीने का शुद्ध पानी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पानी जहरीला हो चुका है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नदी प्रबंधन, नदी प्रदूषण और नदी संरक्षण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करके विश्व स्तर पर लोगों को नदियों को बचाने के बारे में बात करने के लिए अग्रसर करना एवं उनमें जागरूकता पैदा करना है। इस दिवस की उपयोगिता एवं सार्थकता तभी है जब हम नदियों की रक्षा में अग्रणी समुदायों और नागरिक समाज के आंदोलनों को मजबूत करें। मजबूत डेटा और साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए खोजी अनुसंधान को बल दें।

भारत नदियों का अनोखा देश है जहां नदियों को पूजनीय माना जाता है लेकिन दुर्भाग्य से नदियों में प्रदूषण बड़ी समस्या है। गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु (सिंधु), और कावेरी जैसी नदियों को देवी-देवताओं के रूप में पूजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन में बनाया गया जल शक्ति मंत्रालय, नदी घाटियों में आर्दभूमि के पुनरुद्धार-संरक्षण और नदी प्रदूषण के खतरनाक स्तर से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है। देश के समक्ष वाटर विजन-2047 प्रस्तुत किया गया है यानी आजादी के सौ वर्ष पूरे होने तक देश को प्रत्येक वह कार्य करना है, जो देश को पानी के मामलों में सबल बना सके। इसमें हमारी नदियां भी शामिल हैं। हमें अपनी नदियों को 2047 तक निर्मल-अविरल बनाने के संकल्पित लक्ष्य को लेकर बढ़ना होगा। भारत की नदियों की दिन-ब-दिन बिगड़ती हालत एवं बढ़ते प्रदूषण पर पिछले चार दशकों से लगभग हर सरकार कोरी राजनीति करती रही है, प्रदूषणमुक्त नदियों का कोई ईमानदार प्रयास होता दिखाई नहीं दिया

यह पृथ्वी पर सबसे विविध और लुप्तप्राय वन्यजीवों में से कुछ का घर भी है। भारत नदियों का अनोखा देश है जहां नदियों को पूजनीय माना जाता है लेकिन दुर्भाग्य से प्रदूषण बड़ी समस्या है। गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु (सिंधु), और कावेरी जैसी नदियों को देवी-देवताओं के रूप में पूजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन में बनाया गया जल शक्ति मंत्रालय, नदी घाटियों में आर्दभूमि के पुनरुद्धार-संरक्षण और नदी प्रदूषण के खतरनाक स्तर से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है। देश के समक्ष वाटर विजन 2047 प्रस्तुत किया गया है यानी आजादी के सौ वर्ष पूरे होने तक देश को प्रत्येक वह कार्य करना है, जो देश को पानी के मामलों में सबल बना सके। इसमें हमारी नदियां भी शामिल हैं। हमें अपनी नदियों को 2047 तक निर्मल-अविरल बनाने के संकल्पित लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। भारत की नदियों की दिन-ब-दिन बिगड़ती हालत एवं बढ़ते प्रदूषण पर पिछले चार दशकों से लगभग हर सरकार कोरी राजनीति कर रही है, प्रदूषणमुक्त नदियों का कोई ईमानदार प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। नदियां हमारी जीवन रेखा हैं, गति हैं, ताकत हैं। पानी, बिजली, परिवहन, मछली और मनोरंजन के लिए स्रोत हैं। नदियां पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। किनारे बसे शहरों की वजह से आर्थिक रूप से भी अहम हैं, इनसे पीने का पानी मिलता है, बिजली बनती है, खेती के लिए जरूरी उपजाऊ मिट्टी मिलती है। नदियों से जल परिवहन होता है। नदियां प्राकृतिक संपदा हैं। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रमुख सोत हैं, जिनके किनारे महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। नदियों के किनारे ही कई प्रमुख शहर, शैक्षिक और पर्यटन से जुड़े शहर बसे हैं।

आधुनिक शोधों से भी प्रमाणित हो चुका है कि गंगा की तलहटी में ही उसके जल के अद्भुत और चमत्कारी होने के कारण मौजूद हैं। यद्यपि औद्योगिक विकास ने गंगा की गुणवत्ता को प्रभावित किया है, किंतु उसका महत्त्व यथावत है। उसका महात्म्य आज भी सर्वोपरि है। गंगा स्वयं में संपूर्ण संस्कृति है, संपूर्ण तीर्थ है, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। गंगा ने अपनी विभिन्न धाराओं, विभिन्न स्रोतों से भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया, गंगा विश्व में भारत की पहचान है। वह मां है, देवी है, प्रेरणा है, शक्ति है, महाशक्ति है, परम शक्ति है, सर्वव्यापी है, उत्सवों की वाहक है। महान तीर्थ है। पुराण कहते हैं कि पृथ्वी, स्वर्ग, आकाश के सभी तीन करोड़ तीर्थ गंगा में उपस्थित रहते हैं। गंगा जल का स्पर्श इन तीन करोड़ तीर्थों का पुण्य उपलब्ध कराता है। गंगा का जल परम पवित्र एवं स्वास्थ्यवर्धक है, जिसमें रोगवाहक कीटाणुओं का भक्षण करने की क्षमता है। गंगा का दर्शन मात्र ही समस्त पापों का विनाश करना है। 140 सालों में आने वाला महाकुंभ हाल में प्रयासराज में संगम पर 66 करोड़ लोगों का साक्षी बना, जिस गंगा का इतना महत्त्व है, उपयोगिता है तो फिर क्यों उसके प्रति उपेक्षा एवं उदासीनता बरती जाती रही है?

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 208 आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) आजादी के लिए आंदोलन नहीं है-यह उग्रवादी गुट है, जो हिंसा, अस्थिरता और विदेशी एजेंडा से प्रेरित है। इसकी हरकतों से सर्वाधिक नुकसान बलूच अवाम को ही हुआ है। दहशतगर्दी से तौबा करें।
–उज्मा खान रूमी, टीवी पत्रकार @UzmaRumi

वस्त्र क्षेत्र में क्रांति

गिरिराज सिंह

भारत की विकास गाथा के केंद्र में उपभोग

एक दशक पूर्व भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ थी। उपभोक्ताओं का खर्च मुख्य रूप से इच्छा की बजाय आवश्यकता से प्रेरित होता था। खरीदारी का पूर्वानुमान लगाना बहुत आसान था। त्योहारों के लिए नये कपड़े, सावधानीपूर्वक योजना आधारित खर्च और फिजूलखर्ची की बजाय बचत पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। लक्जरी ब्रांडों की दूर से प्रशंसा की जाती थी। उच्च श्रेणी का फैशन अभिजात वर्ग तक सीमित था। आज देश की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ हो गई है। मध्यम वर्ग तेजी से बढ़त की ओर है। वही परिवार पूरे आत्मविश्वास से प्रीमियम स्टोर में कदम रखता है। आसानी से ऑनलाइन खरीदारी करता है। अपने जीवन में अनेक अवसरों को उत्सव के तौर पर भी देखता है।

बढ़ती क्रय शक्ति, विकसित होती उपभोक्ता मानसिकता और अंतिम-मील डिजिटल कनेक्टिविटी, ये तीनों इस बदलाव के मुख्य वाहक हैं। आर्थिक सुधार अभूतपूर्व रहा है। इसे बढ़ती आय, सरकार समर्थित विनिर्माण पहल और डिजिटल रूप से सशक्त भारत के माध्यम से पंख लगे हैं। 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत' योजना शुरू की गई। इस विजन ने आत्मनिर्भरता की नींव रखी। इसे प्रोडकशन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्कों द्वारा और सशक्त किया गया। जैसे-जैसे विनिर्माण में उछाल आया, रोजगार सृजन हुआ और इसके साथ ही डिस्पोजेबल आय में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप भारतीयों के खर्च करने के तरीके बदल गए। उपभोग अब भारत की विकास गाथा के केंद्र में है, जो कपड़ा क्षेत्र को स्वर्ण युग में ले जाने के लिए तैयार है। पिछले कई वर्षों में, आकांक्षाएं सचमुच वास्तविकता से आगे निकल गईं। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ, डिजिटल इंडिया ने आकार लिया और आर्थिक सुधार मूर्त विकास का इंजन बन गए। इसके प्रभाव से भारत गुणवत्ता, शैली और सुविधा को अपनाने के लिए तैयार आत्मविश्वासी उपभोक्ताओं वाले देश के रूप में उभरा।

आय में उछाल आया है। प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में 72,805 से बढ़कर 2023-24 में 1.88 लाख रुपये हो गई है और 2030 तक 3.5 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। आज छह करोड़ भारतीय सालाना 8.3 लाख रुपये से अधिक कमाते हैं-2015 की संख्या से दोगुने से भी अधिक है। यह बढ़ती समृद्धि फैशन, कपड़ा और जीवन शैली वाले उत्पादों की अभूतपूर्व मांग को बढ़ावा दे रही है। 2027 तक भारत चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता टिकाऊ बाजार होगा जो न केवल सामर्थ्य, बल्कि आकांक्षाओं से भी प्रेरित होगा।

कोविड के बाद उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव गेम-चेंजर रहा। डिजिटल पहुंच बढ़ी, ऑनलाइन रिटेल फला-फूला और यूपीआई लेनदेन आसमान छू गया। वित्त वर्ष 2013-14 में 220 करोड़ से इस डिजिटल परिवर्तन ने शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाट दिया है। इससे सुनिश्चित हुआ कि चाहे मेट्रो शहर में रहें या छोटे शहर में, भारतीयों के पास अब वैश्विक और स्थानीय फैशन तक निर्बाध पहुंच है।

कभी पश्चिमी अवधारणा, फास्ट फैशन अब युवा भारतीयों के लिए जीवन का एक तरीका है। जो कभी अनन्य था, वह अब पहुंच के भीतर है। इसका श्रेय ज्यूडियो, रिलायंस ट्रेंड्स और शीन जैसे ब्रांडों को जाता है। ये ब्रांड 10 बिलियन डॉलर के उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। यह कारोबार 2030 तक 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए तैयार है। लेकिन यह बदलाव केवल सामर्थ्य के बारे में नहीं है-लक्जरी और विरासत वाले वस्त्र फास्ट फैशन के साथ-साथ फल-फूल रहे हैं। जैसे-जैसे आकांक्षी परिवार 2027 तक 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर रहे हैं, हस्तनिर्मित कपड़े, रेशम की साड़ियां और उच्च श्रेणी के डिजाइनर परिधान फिर से उभर रहे हैं। यह क्रांति कोई संयोग भर नहीं है। यह सरकार द्वारा संचालित पहलों का प्रत्यक्ष परिणाम है। बिचौलियों को खत्म करके कारीगरों के प्लेटफार्मों को डिजिटल बनाकर और सीधे ग्राहक-से-कारीगर कनेक्शन

को सक्षम करके, डिजिटल इंडिया ने फैशन को खरीदने और बेचने के तरीके को बदल दिया है। महाराष्ट्र की पैठणी, कश्मीर की पश्मीना-अब एक बटन के क्लिक पर उपलब्ध है। इससे विरासत शिल्प को पुनर्जीवन मिल रहा है, और भारत की वस्त्र विरासत को वैश्विक मंच पर सबसे आगे आ रहा है।

भारतीय शादियां हमेशा भव्य रही हैं किंतु आज वे अरबों-खरबों डॉलर की आर्थिक शक्ति हैं। 45 बिलियन डॉलर का विवाह उद्योग पारंपरिक बुनाई क्लस्टरों में नई जान फूंक रहा है। इसमें परिवार बड़े पैमाने पर उत्पादन की बजाय कलात्मकता को चुन रहे हैं। विलासिता अब लेबल के बारे में नहीं है, यह विरासत के बारे में है। दुल्हन और दूल्हे विशिष्टता का विकल्प चुन रहे हैं। हाथ से बुने बनारसी रेशम, जटिल कांजीवरम और भारत की समृद्ध वस्त्र विरासत का जश्न मनाने वाले डिजाइन का चयन कर रहे हैं। लेकिन परिवर्तन परिधान तक ही सीमित नहीं है। जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसकी सुंदरता की चाहत भी बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2019-23 के बीच रियल एस्टेट की कीमतों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और बड़े, अधिक परिष्कृत घरों के साथ हस्तनिर्मित साज-सज्जा, डिजाइनर असबाब, विरासत सजावट की मांग बढ़ गई है। आधुनिक घर भारतीय शिल्प कौशल का प्रदर्शन बन गए हैं। परिणामस्वरूप हाथ से बने वस्त्रों की मांग फैशन से परे इंटीरियर और लक्जरी लिविंग में बढ़ रही है।

भारत का कपड़ा उद्योग अब केवल उत्पादन के बारे में नहीं है। नवाचार, डिजाइन और वैश्विक प्रभाव के बारे में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'मेक इन इंडिया' 'डिजाइन इन इंडिया' में विकसित हुआ है, जहां भारतीय रचनात्मकता अंतरराष्ट्रीय फैशन को आकार देती है। अनुसंधान एवं विकास पर सरकार का ध्यान और एक संपन्न स्टार्टअप इको-सिस्टम को बढ़ावा देने से बेजोड़ आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तीन टी टैक्सटाइल (वस्त्र), टूरिज्म (पर्यटन) और टैक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी)-पर काम करते हुए अपना देश अब विकसित भारत की नींव रख रहा है। हाल में बजट में वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दिए जाने के साथ, 136 बिलियन डॉलर का घरेलू उद्योग 2030 से पहले ही 250 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। इससे वैश्विक अग्रणी के रूप में भारत के स्थान की पुष्टि होती है। निजी खपत 2013 में 87 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में 183 लाख करोड़ रुपये हो गई है। 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद 635 लाख करोड़ रुपये को छूने का अनुमान है। निजी खपत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा होगी। यह बदलाव भारत को वैश्विक खपत शक्ति बना देगा, जो अमेरिका, चीन और जर्मनी जैसे विकसित देशों से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन भारत का उदय केवल इस बारे में नहीं है कि कितना उपभोग किया जा रहा है। यह इस बारे में है कि इसे क्या महत्त्व दिया जा रहा है। भारतीय कपड़ा उद्योग को कभी उत्पादन केंद्र के रूप में देखा जाता था। अब इसे वैश्विक फैशन ट्रेंड तय कर रहा है। दुनिया भारत को न केवल इसके शिल्प कौशल के लिए, बल्कि इसकी दूरदर्शिता, लालित्य और विरासत के आधुनिकता के साथ मिलन की क्षमता के लिए भी देखती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। नया भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, बल्कि उन्हें बनाता है। भारत के युवाओं से कहना है, वे नौकरी चाहने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें। आपकी शैली, महत्त्वाकांक्षा, विचार-यही भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य है। ■

कभी पश्चिमी अवधारणा, फास्ट फैशन अब युवा भारतीयों के लिए जीवन का एक तरीका है। जो कभी अनन्य था, वह अब पहुंच के भीतर है। लेकिन यह बदलाव केवल सामर्थ्य के बारे में नहीं है-लक्जरी और विरासत वाले वस्त्र फास्ट फैशन के साथ-साथ फल-फूल रहे हैं। जैसे-जैसे आकांक्षी परिवार 2027 तक 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर रहे हैं, हस्तनिर्मित कपड़े, रेशम की साड़ियां और उच्च श्रेणी के डिजाइनर परिधान फिर से उभर रहे हैं। यह क्रांति कोई संयोग भर नहीं है। यह सरकार द्वारा संचालित पहलों का प्रत्यक्ष परिणाम है

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

संकट में सांस्कृतिक विरासत

बलूचिस्तान में बवाल

भारतीय सांस्कृतिक एकता की जादुई हकीकत को नजरअंदाज कर इस्लामिक राष्ट्रवाद की कपोल कल्पित अवधारणा के बूते भाषा, क्षेत्र, जातीय और सांस्कृतिक विविधता के खत्म होने तथा एकरूपता में बंधने की मोहम्मद अली जिन्ना की सोच को पश्तूनों ने शुरुआती दौर में ही गलत ठहरा दिया था। 1971 में पृथक बांग्लादेश ने उसे आईना दिखाया और अब बलूचिस्तान उसी विचार को धराशायी कर रहा है।

इस समय समूचा बलूचिस्तान उबल रहा है। बलूचिस्तान की अवाम का गुस्सा पाकिस्तानी सेना, सत्ता और व्यवस्थाओं को लेकर है। न्यायिक हिरासत, सरकारी हिंसा, उत्पीड़न, अपहरण और शोषण से जूझते यहां के लोगों को पाकिस्तान की पुलिस से गहरी नफरत है, सेना को वे अपना दुश्मन समझते हैं, और न्यायपालिका पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है। महरंग बलोच, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो मुखरता से पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती देते हुए तकरीरें करती हैं। इन तकरीरों में हजारों लोग जुटते हैं, जो पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र देश बलूचिस्तान के पक्ष में हुंकार भरते हैं। उनके नेतृत्व में कई विरोध मार्च और आंदोलन हुए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों का मुद्दा बुलंद हुआ है। पाकिस्तान की सेना इन्हें देशद्रोही, अलगाववादी और आतंकवादी कह कर मारती और प्रताड़ित करती है, इससे लोगों में गुस्सा और बढ़ा है। पाकिस्तान की व्यवस्थाओं पर पंजाबीवाद बुरी तरह से हावी है, जहां बड़े पदों से लेकर राजनीतिक सत्ता तक पंजाबियों का कब्जा समझा जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान में पंजाबी बनाम बलूचिस्तानी की लड़ाई हिंसक हो गई है। बलूचिस्तान में पंजाबियों से इतनी नफरत है कि

पहचान सामने आते ही उन्हें मार दिया जाने लगा है। आधे पाकिस्तान से बस थोड़े ही कम क्षेत्रफल वाले पाकिस्तान के इस सबसे बड़े प्रांत के बाशिंदे खुद को पाकिस्तानी बताने से परहेज करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। बलूच जातीय और ऐतिहासिक रूप से अलग लोग हैं, जो करीब पौने चार लाख वर्ग मील के क्षेत्र में रहते हैं। बलूचिस्तान के अंतर्गत पाकिस्तान का बलूचिस्तान नामक दक्षिण-पश्चिमी प्रांत, दक्षिणी-पूर्वी ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत और दक्षिणी अफगानिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र आते हैं। इनके लिए बलूचिस्तान एक पहचान नहीं बल्कि एक राष्ट्र है जिसमें साझा भावना सामूहिक पहचान का एक रूप प्रदान करती है, और राजनीतिक एकजुटता में व्यक्तियों को एक साथ बांधती है।

बलूचिस्तान को पाकिस्तान में एक पिछड़ा प्रांत समझा जाता है, लेकिन बलूच बलूचिस्तान को एक राष्ट्र और सांस्कृतिक राजनीतिक समुदाय के रूप में भी परिभाषित करते हैं, जो अपनी स्वायत्तता, एकता और विशेष हितों के प्रति बहुत सचेत है। भारत विभाजन के बाद से ही बलूचिस्तान में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत- पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। बलूच निवासी खुद को पाक के अधीन नहीं रखना चाहते। बलोच राष्ट्रवाद उनके अलग देश बनाने की चाह का नतीजा है। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद से ही बलूच राष्ट्रवादियों और केंद्र सरकार के बीच संबंध टकरावपूर्ण रहे हैं, जो समय-समय पर हिंसक होते रहे हैं। बलोच नेता अकबर खान बुगती की पाकिस्तानी सेना द्वारा 2006 में हत्या कर दी गई थी। इस अभियान का आदेश जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिया था जो तब देश के सैन्य प्रमुख और राष्ट्रपति, दोनों थे।

बुगती, जो बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई के बड़े सम्मानित चेहरे माने जाते थे, की हत्या से विवाद गहरा गया और यह हिंसक संघर्ष के रूप में अब भी जारी है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर कई यात्रियों को बंधक बनाने वाले प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) नामक चरमपंथी संगठन को आम बलूच लोगों का भारी समर्थन हासिल है। बीएलए एक दशक से ज्यादा समय से बलूचिस्तान में सक्रिय है। यह समूह बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव से आजाद कराने की इच्छा रखता है। बीएलए का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक उनका है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में चीन की महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं का भविष्य अधर में पड़ गया है। बलूचिस्तान प्राकृतिक गैस और तेल से समृद्ध है, और पाकिस्तान के सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।

इस समय यहां चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का विरोध चरम पर है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है। इसका उद्देश्य चीन के पश्चिमी भाग में स्थित शिनिजयांग प्रांत को पाकिस्तान के उत्तरी भागों में खुंजेराब दर्रे के माध्यम से बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। यह ग्वादर पोर्ट से चीन के लिए मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे चीन हिन्द महासागर तक पहुंच सकेगा। 2013 में शुरू किए गए बीआरआई का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि तथा समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है।

बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की सत्ता और सेना मिल कर उनके खनिज संसाधनों को लूट रही हैं तथा इसमें चीन की प्रमुख भागीदारी है। यही कारण है कि बीएलए के लड़ाके चीन के इंजीनियरों को भी निशाना बना रहे हैं। बलूचियों के गुस्से के कई कारण हैं, और पाकिस्तान की व्यवस्था ने इसे बढ़ाया ही है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र में बहुत गरीबी और पिछड़ापन है। पंजाबियों के प्रभुत्व वाली व्यवस्थाएं पाकिस्तान के लिए अभिशाप से कम नहीं हैं। 1971 में अलग बांग्लादेश का बनना भी पंजाबियों के प्रभाव से अलग होने की छटपटाहट थी, जिससे पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया। बलूच लोग सेना, पुलिस और न्यायपालिका में बलूच प्रतिनिधित्व की कमी देखते हैं, इस पर पंजाबियों के हितों का व्यापक प्रभुत्व है। पाकिस्तान की सरकार हिंसक तरीके से बलूच राष्ट्रवाद को खत्म करना चाहती है, जो नामुमकिन है। सेना के प्रभाव वाली पाकिस्तानी व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से समस्याओं के समाधान को नजरअंदाज किया जाता है, इसने स्थिति को ज्यादा जटिल बना दिया है। अंततः भारतीय उपमहाद्वीप का चरित्र लोकतांत्रिक और समावेशी रहा है, पाकिस्तान आठ दशकों से उसी पहचान को मिटा देने की कोशिश करते-करते खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। ■

राग रंग | आलोक पराड़कर

भावुक कोठरियों का 'चंदन किवाड़'

जो संगीत के सागर में गोते लगाते हैं, कैनवास पर रंगों-रेखाओं का संसार रचते हैं, कम ही होता है कि लेखन का किवाड़ भी उनसे खुल सके। चर्चित लोक गायिका मालिनी अवस्थी अच्छी वक्ता रही हैं, कार्यक्रमों में भी श्रोताओं से खूब बातें करती हैं, साहित्य उत्सवों के मंच पर वाकपटुता का परिचय देती हैं, नियमित तौर पर आलेख भी लिखती हैं लेकिन अपने संगीत संसार के तमाम आख्यानों को उन्होंने जिस प्रकार अपनी पुस्तक 'चंदन किवाड़' में शब्दों से पिरोया है, वह गहरा असर छोड़ता है। लेखिका ने इसे जीवन की 'देखी-अनदेखी भावुक कोठरियां' कहा है, जहां जीवन के सतरंगे जीवंत रंग बिखरे हुए हैं। पुस्तक पर विविध मंचों पर हो रही चर्चाओं में वह इन आख्यानों को सुना भी रही हैं।

'चंदन किवाड़' उन तमाम कथाओं-प्रसंगों की दास्तान है, जो गायिका के संगीत, उनके लोक गीतों से जुड़ते हैं। वह कहती हैं, 'यह हमारा मन ही है, जिसकी आधारशिला पर उपस्थित हो बारह सुर आरोह, अवरोध, आलाप, तान, गमक, मीड़ का निराकार स्वरूप गढ़ते हैं। मन का जैसा आलोड़न, मन की जितनी गहरी व्याप्ति, मन का जितना उदार आकाश, वैसा संगीत का प्राकट्य। क्या यही कारण है, जो मेरे सुर में प्राण बन अशेष सुमंगलाएं अपनी आपबीती के साथ जब-तब प्रकट हो जाती हैं? मानो मेरी इस धारणा को दृढ़तर करती जाती हैं कि हर गीत में प्राणतत्त्व है, वही प्राणतत्त्व उस गीत की प्रेरणा हैं, वही शक्ति ! मैंने हर बार महसूस किया कि इन गीतों को गाते हुए मैं परकाया प्रवेश कर जाती हूं, फिर मैं नहीं गाती, वही नायिका उस गीत को आगे ले जाती है,

जानती हूं, यह सामान्य बात नहीं है। एक ही गीत को सैकड़ों बार गाने के बाद भी, हर बार उस गीत में वही ऊर्जा, वही जीवंतता कैसे प्रकट हो जाती है, ये कोई बहुश्रुत फिल्मी गीत नहीं, ये शास्त्रीय-संगीत की अवतारणा भी नहीं, जहां हम नित्य नया स्वतन्त्र वितान रचते हैं, ये हमारे अन्तःकरण के रक्षक लोक गीत हैं, जो कहने-सुनने में बहुत सामान्य लगते हैं, किंतु जब-जब मुखरित होते हैं, हमें हमारी चेतना से जोड़ते जाते हैं, जहां कहा कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रह जाता, सामूहिकता को समर्पित हो जाता है। मेरे भीतर का कलाकार बहुधा मुझे इस बात के लिए उद्वेलित करता है कि क्या अभिव्यक्ति कंठ स्वर से भी ऊपर उठकर अपना नया रचना संसार गढ़ सकती है?'

मालिनी अवस्थी लोक गीतों से उन तमाम कथाओं, प्रसंगों को पिरोती हैं, जो परिवार की, परिचितों की, प्रशंसकों की और आसपास के हैं। ये आख्यान बताते हैं कि पीढ़ियों से गाए जा रहे ये लोकगीत आज भी किस प्रकार हमारे समय से जुड़ जाते हैं, यही उनकी लोकप्रियता के कारण भी हैं और उन्हें कालजयी भी बनाते हैं। इन आख्यानों में ऐसी नायिकाएं हैं अपने अभावों से जूझती हुई लेकिन संघर्षों में डटी हुई, जिनकी कहानियां मार्मिक हैं, हमें उदास कर देती हैं, चाहे वह दन्नो बुआ दमयंती हों या फिर गुमनामी में खो गईं विख्यात गायिका विदुषी गिरिजा देवी की गुरु बहन छुन्नी, जिसके बारे में खुद गिरिजा देवी ने कहा था कि वह राग-'चारु केशी' बहुत सुंदर गाती थी-'तड़प तड़प जिया जाए'। पारिवारिक जिम्मेदारियों में खो गईं, ऐसी तमाम महिलाएं इन आख्यानों की नायिकाएं हैं। लेखिका का अध्ययन इन आख्यानों को और विस्तार देता है, तमाम प्रसंगों में संस्कृत साहित्य से लेकर हिन्दी के साहित्यकारों की रचनाओं का उद्धरण इन्हें रोचक और गंभीर बनाता है। बातों-बातों में वह बताना नहीं भूलतीं कि किस प्रकार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की 'शेषेर कोबिता' का उन पर इतना गहरा असर था कि बेटी का नाम लावण्या रखने की सोची थी, हालांकि बाद में उन्हें यह निर्णय बदलना पड़ा। कभी प्रवास तो कभी कार्यक्रमों के कारण विभिन्न नगरों का खूब वर्णन इन आख्यानों में है।

'छापक पेड़ छियुलिया' लोक गीतों की ताकत, उसकी गंभीरता को बताती है। लेखिका ने लिखा है कि प्रसिद्ध साहित्यकार विद्यानिवास मिश्र ने उन्हें मारीशस के विश्व भोजपुरी सम्मेलन के समय यह सोहर गाने को कहा था जिसमें राजा दशरथ के घर हो रहे छठी के उत्सव का वर्णन है, लेकिन यह उत्सव हिरनी की पीड़ा का कारण है। गीत में वर्णन है कि हिरन को मार कर उसकी खाल से खंजड़ी बनाएंगे जिससे राम खेलेंगे। लेखिका ने लोक में प्रचलित इस लोक गीत के विविध पाठों का भी उल्लेख किया है। कुछ गीतों में यह भी वर्णन है कि हिरनी के श्राप से ही रानी कौशल्या को पति के वियोग और पुत्र के वनवास का दुख भोगना पड़ता है। हम अपने हर्ष में किसी के दुख को न भूल जाएं, अपने इसी संदेश को लेकर यह सोहर लोक में प्रचलित है। 'चंदन किवाड़' में बहुत से अध्याय ऐसे हैं, जिन पर अलग से पूरी किताब हो सकती है। गुरु गिरिजा देवी का उल्लेख बार-बार आया है, गजल गायक उस्ताद राहत अली पर भी अध्याय काफी बड़ा है। मालिनी अवस्थी ने लगातार कार्यक्रमों के बीच 'चंदन किवाड़' के लेखन का एकांत तलाशा है, भविष्य में अपने गुरुओं पर भी उन्हें विस्तार से लिखना चाहिए। लोक कलाकारों पर अलग से किताब लिखने की बात तो उन्होंने खुद ही इसमें कही है। ■

कैनवस | जय त्रिपाठी

आकारों के अनगिनत रूप

जैसे-जैसे कला की दुनिया विकसित होती है, कलाकार, कला चिंतक एवं कला से जुड़े व्यक्ति कला आलोचना-समालोचना अनुकूलन जारी रखते हैं, यह समकालीन कला को गतिशील और हमेशा बदलते स्वरूप में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कला में आज पारंपरिक कला इतिहास के मानदंडों से मुक्त होने का प्रयास करते कार्य न केवल प्रत्येक तत्व के रूप का पता लगाते हैं, बल्कि मानव जाति के साथ उसके संबंध और प्रभाव को भी दर्शाते हैं। नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर की विजुवल आर्ट गैलरी में पिछले सप्ताह मंजूषा शीर्षक से पंद्रह कलाकारों के कामों की समूह कला प्रदर्शनी प्रदर्शित रही। समय के बदलते स्वरूप को अपनी विशेष दृष्टि से रेखांकित करती इस समूह प्रदर्शनी को चैता बसु जेना ने क्यूरेट किया है।

चैता जेना द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में प्रवेश करते ही एकाएक नजर उस ओर जाती है, जहां इस महिला कलाकार ने हैंडमेड कागज पर इंटैग्लियो, पिग्मेंट आदि के तकनीकी प्रयोग से प्रकृति और उसके जीवों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की है, जो इसे सुंदर बनाती है। चैता के रचनात्मक कामों को गौर से देखने पर उनकी तकनीकी दक्षता का आभास होता है। उनके काम जीव और प्रकृति पर केंद्रित हैं। उन्होंने मानवीय चिंताएं दर्शाते पैनलों की श्रृंखला को प्रदर्शित किया है।

कलाकार अनिरुद्ध मुखोपाध्याय ने समाज और लोगों के जीवन को आकार देते हुए संवेदनात्मक चित्रण किया है। चित्रों को देख कर महसूस होता है कि वह मनुष्यता के प्रति सामाजिक चिंता व्यक्त करते हैं। चित्रों में गढ़े हाव-भाव सत्ता और जटिल सामाजिक संबंधों के सामने उनकी स्थिति को सूक्ष्मता से दर्शाते हैं। कोलकाता की कलाकार गौरी भौमिक की कला शहरीकरण के विभिन्न पक्षों के माध्यम से एक नये जीवन की ओर ले जाने को उत्सुक दिखती है। हरीत बसु का बाउल शीर्षक से गढ़ा शिल्प एक अनुभवी बाउल गायक का कांस्य माध्यम में सजीव मूर्तिशिल्प है। बसु के शिल्पों को देख कर लगता है कि वह मूर्तिकला बनाने की बारीकियों में अधिक गहराई से उतरते हैं।

मिट्टी के बर्तनों, चीनी मिट्टी और कांच को अपने मूर्तिकला माध्यमों के रूप में उपयोग करते कृपा सिंधु दक्ष कलाकार हैं, जो सबसे नाजुक माध्यमों में से एक कांच आदि का मूर्ति निर्माण में प्रयोग करते हैं। कृपा के प्रतीकात्मकता शिल्पों में एक छोर पर मस्तिष्क जैसा समूह है, और दूसरे छोर पर लहरदार पूंछ है। प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां सृजन मिथकों और वैज्ञानिक विचारों दर्शाती हैं। वरिष्ठ कलाकार ललित मैती ने अपनी व्यक्तिगत शैली विकसित की है जो गीतात्मक और वर्णनात्मक है। ग्राफिक कला की दक्षता उनकी पेंटिंग में देखी जा सकती है। शर्मा मुनि लंबरदार दैनिक जीवन की घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक घटनाओं को भी व्यक्त करने में सक्षम हैं। खैरागढ़ विश्वविद्यालय से प्रिंटमेकिंग में स्नातकोत्तर प्रियम तालुकदार लकड़ी की नक्काशी में दक्ष प्रतीत होते हैं। कल्पना, अति यथार्थवादी कल्पना और वर्तमान समाज को प्रतीकात्मक और कथात्मक रूपों में दिखाते प्रियम का वुडकट प्रिंट आकर्षक है। ओडिशा के सरोज कुमार राउत के स्टोनवेयर की कृति जैविक रूप की जटिल प्रतिकृति प्रतीत होती है।

सामाजिक रूप से चैतन्य कलाकार शास्वती चौधुरी अपनी पेंटिंग और अन्य कामों में माध्यमों, शैलियों के साथ-साथ विषयों की उपयोगिता को समझती हैं। उनकी यथार्थवादी कलाकृतियों में उनकी रचनात्मक सोच और एक मानवतावादी के रूप में स्त्री की स्वतंत्र वैचारिकी की स्पष्टता देखी जा सकती है। शुभंकर तरफदार उस दुनिया के बारे में स्पष्ट विचार है जिसमें वह रहते हैं, और उन दृष्टिकोणों के बारे में जो मनुष्यों को अधिकारी और अधीनस्थ, दोनों बनाते हैं। कोलकाता के कलाकार सुबीर कयाल ने गैर-प्रतिनिधित्वात्मक प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। सुधी रंजन महाराथा का स्टोनवेयर शिल्प सौंदर्यवादी रूप है जो दर्शकों के मन में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को जगाता है। महाराथा सिरेमिक के माध्यम से कई दृष्टिकोण बनाते दिखते हैं। कलाकार सुकन्या का कांस्य शिल्प महिला का चंचल स्वरूप प्रस्तुत करता है, जो सुकन्या की व्यक्तिगत शैली स्थापित को करती है। स्वप्न कुमार साहा के ब्रश स्ट्रोक और रंगों के प्रयोग चित्र को आकृष्ट बनाते हैं। ■

https://t.me/AllNewsPaperPaid

पायनियर
नई दिल्ली, रविवार, 16 मार्च, 2025

कब्जामुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं सबक: मुख्यमंत्री

● जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि गरीबों की जमीन पर यदि किसी ने कब्जा किया है तो तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ दबंगों को सबक सिखाया जाए। किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कानून सम्मत कड़ा एक्शन लिया जाए। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। गोरखपुर में होलिकोत्सव मनाने के बाद सीएम योगी शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

यूपी में कानून-व्यवस्था पर भाजपा सरकार का कोई नियंत्रण नहीं: अखिलेश यादव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भाजपा सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। जब राज्य में प्रशासन ही सुरक्षित नही तो जनता की सुरक्षा की बात क्या की जा सकती है। लूट, हत्या, बलात्कार तो रोजमर्रा की बातें हो गई है। आश्चर्य यह है कि मुख्यमंत्री इस पर भी प्रदेश में कानून के राज का खयाली पुलाव पकाने में जरा भी संकोच नही करते है और जनता को गुमराह करना ही अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहे है। लेकिन वे भूलते हैं कि जनता की नजरों से कुछ छुपा नहीं रहता है।

उन्होंने कहा कि बरेली में दबंगो ने होली के दिन कानून को ठेंगा दिखाते हुए एक डिप्टी एसपी का बंगला ही पेट्रोल डालकर फूंक दिया। पुलिस प्रशासन देखता रह गया। लखनऊ में तैनात महिला कांस्टेबल छुट्टी लेकर अपने गांव भाई के साथ जा रही थी। मुंडेरा बस स्टेशन के पास शराबियों ने अभद्रता की, सोने की चेन लूट ली। पुलिस जब आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए गई तो वहां महिलाओं के विरोध के आगे पुलिस बेबस दिखी। ये तो दो ताजा घटनाए हैं जिनसे पता चलता है कि प्रदेश में अराजक तत्वों के हौसले कितने बुलंद है। मुख्यमंत्र की घोषणाएं बेदम है। अपराधी जेल से भी कारनामे कर रहे हैं। दूसरे प्रदेशों के अपराधी भी अब उत्तर प्रदेश को अपने लिए सुरक्षित प्रदेश मानने लगे है। उन्हे यहां कोई डर नहीं। आतंकी गतिविधियों का भी यह केन्द्र बनता जा रहा है। सच तो यह है कि मुख्यमंत्री जी को प्रदेश में कामकाज देखने की फुर्सत ही नही है। वे प्रशासक कम स्टार प्रचारक ज्यादा हो गए है। प्रदेश प्रगति के तमाम पायदानों में पिछड़ता जा रहा है। विकास ठप्प है। पूंजी निवेश के नाम पर बस एमओयू की फाइले हैं जो जमीन पर उतरने वाली नहीं है। कोई निवेशक यहां आना ही नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के संरक्षण में ही अराजकतत्व पनप रहे हैं। सरकार को बस लोकतंत्र से परेशानी है।

सपा मुख्यालय में मनाई गई कांशीराम की जयंती

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय सहित प्रदेश के सभी जनपदों में शनिवार को कांशीराम की जयन्ती सादगी से मनाई गई। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ में कांशीराम के चित्र पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने माल्यार्पण कर नमन किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मान्यवर कांशीराम की स्मृति को नमन करते हुए एक वक्तव्य में कहा है कि वे एक सुलझे हुए राजनेता तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने बहुजनों के राजनीतिक सशक्तिकरण तथा उनके उत्थान के लिए निरन्तर संघर्ष किया। दलितोंए वंचितों की आवाज उठाने में वे कभी पीछे नहीं रहे। यादव ने कहा कि कांशीराम ने सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध थे। वे दलितों, शोषितों के मसीहा थे।

महाकुंभ के बाद होली ने दिया सनातन विरोधियों को जवाब: मुख्यमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/गोरखपुर

होली के शुभ अवसर पर शुक्रवार सुबह होलिकादहन के भस्म के तिलक से शुरुआत करने और फिर घंटाघर से निकलने वाली भगवान नृसिंह की पारंपरिक रंगभरी शोभायात्रा में शामिल होकर होली खेलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराह्न काल से शाम तक गोरखनाथ मंदिर में होली मिलन कार्यक्रम में उमड़े लोगों पर फूलों की बौछार की। इस अवसर पर उन्होंने सभी को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं और कहा कि महाकुंभ के बाद अब होली ने सनातन धर्म के विरोधियों को जवाब दे दिया है। पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली का आयोजन संपन्न हुआ है।

गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म की परंपराओं पर और सनातन धर्म पर प्रश्न उठाते थे, उन लोगों को जवाब है होली। जो लोग सनातन को बदनाम करते हैं और हमेशा दुष्प्रचार करते हैं कि सनातन धर्म जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर, अगड़ी-पिछड़ी के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर बंटा है, इन दुष्प्रचारों का जवाब महाकुंभ के बाद आज होली ने भी दे दिया है। होली पर एक साथ हर भारतवासी, हर सनातन धर्मावलंबी गले मिल रहा था, रंग और गुलाल लगा रहा था, उत्साह-उमंग के साथ भारत की सनातन परंपरा को मजबूती प्रदान कर रहा था। यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। महाकुंभ के बाद होली के पर्व ने अपनी परंपरा और संस्कृति के प्रति श्रद्धा श्रद्धा व आस्था का भाव प्रदर्शित कर यही संदेश दिया है सनातन लोगों के बीच कोई बटवारा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंटवारा तो सनातन धर्म को बदनाम करने वालों की बुद्धि में है, ऐसे लोगों की बुद्धि दूषित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश ने लंबे समय तक गुलामी झेली है। आक्रांताओं ने होली, दीपावली जैसे पर्व-त्योहार और महाकुंभ जैसे आयोजनों को बाधित करने का प्रयास किया लेकिन सनातनियों की अधिक आस्था के चलते वे कभी सफल नहीं हो पाए। योगी ने कहा कि सनातन धर्म को जीवन पद्धति कहा जाता है। इसमें अगर कभी कोई विकृति किन्हीं कारणों से आ गई हो तो उसके परिमार्जन का मार्ग हमारे पर्व-त्योहार स्वयं ही आगे बढ़ा देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया देख रही थी जब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, 45 दिनों के प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का पावन त्रिवेणी में डुबकी लगाना दुनिया के लिए कौतुक और आश्चर्य का विषय था। दुनिया के लिए यह चमत्कार सारिका था लेकिन सनातन धर्मावलंबियों के लिए वह सामान्य जीवन पद्धति का हिस्सा था। क्योंकि कुंभ की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। यह भारत की ज्ञान की परंपरा और ऋषि परंपरा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान करने आए ही इसके साथ ही दुनिया में ऐसा कोई सनातन धर्मावलंबी लंबी नहीं होगा जिसके घर महाकुंभ का गंगाजल न पहुंचा हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरीशस की यात्रा पर गए थे और मॉरीशस के राष्ट्राध्यक्ष को उन्होंने गंगाजल भेंट किया।

घंटाघर से निकलने वाली भगवान नृसिंह की रंगभरी शोभायात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गोरखपुर

● सनातन धर्म जितनी पर्व-त्योहार की समृद्ध परंपरा दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं: योगी

गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म जितनी समृद्ध पर्व-त्योहारों की परंपरा दुनिया के किसी भी अन्य देश में या मत, मजहब के पास नहीं है। हमारी आस्था ही सनातन धर्म की ताकत है और आस्था की आत्मा पर्व, त्योहार में है। सनातन पर्व परंपरा में दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक वर्षभर उत्साह और उमंग से जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है।

सीएम योगी शुक्रवार को होली के पावन महापर्व पर घंटाघर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व श्री होलिकोत्सव समिति की ओर से निकलने वाली भगवान नृसिंह की रंगभरी शोभायात्रा के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। सभी प्रदेशवासियों को होली की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पौराणिक गाथा गाथा के अनुसार भारत में जन्म लेना दुर्लभ है। और, उसमें भी मनुष्य रूप में, सनातन धर्म में जन्म लेना और भी दुर्लभ। जो लोग सनातन को कोसते थे उन्होंने भी सनातन का सामर्थ्य प्रयागराज महाकुंभ में देखा है। प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पावन त्रिवेणी में स्नान कर पुण्य के भागीदार बने। दुनिया में कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जाति का, किसी भी भाषा को बोलने वाला सनातनी रहा हो, उसने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर जीवन को धन्य बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ को दुनिया विस्मयकारी भाव से, कौतूहल भरी निगाहों के साथ देख रही थी। जबकि सनातन धर्म के लोग इस महाकुंभ के माध्यम से पूरे विश्व को एकता का संदेश देने के लिए जुड़े हुए थे। प्रयागराज में अद्भुत मर्यादा और अद्भुत अनुशासन देखने को मिला। वहां ऐसी एक भी घटना नहीं हुई जिसके कारण सनातनी लोगों को सिर नीचे करना पड़ता।

होलिका भस्म की पूजा कर सीएम योगी ने मनाई होली

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गोरखपुर

● गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने लिया फाग का आनंद

होली के पावन महापर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह होलिका भस्म की पूजा कर होली मनाने का शुभारंभ किया। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में फाग गीतों का आनंद लिया और गोवंश को भस्म, गुलाल लगाकर गोसेवा की। मुख्यमंत्री ने भीम सरोवर के पास बतखों को तथा मंदिर की गोशाला के पास मोर को भी दाना खिलाया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होलिकोत्सव की शुरुआत शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर होलिका भस्म की पूजा से हुई। मंदिर के मेला ग्राउंड में जलाई गई होलिका के पास जाकर योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच होलिका भस्म (सम्मत की राख) की पूजा की और आरती उतारी। इस अनुष्ठान के बाद साधु-संतों व श्रद्धालुओं ने इसी भस्म से गोरक्षपीठाधीश्वर का तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। गोरक्षपीठाधीश्वर ने भी उन्हें तिलक लगाकर होली की मंगलकामना की। होलिकादहन स्थल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर पहुंचे और श्रीनाथ जी को होलिका भस्म अर्पित किया। इसके बाद श्रीनाथ जी के मंदिर के चबूतरे पर फाग गीतों का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने भी कुछ देर वहां रुककर फाग का आनंद उठाया और सबको होली की बधाई व शुभकामनाएं दीं। होली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गोशाला पहुंचे और गोवंश को भस्म व अबीर-गुलाल लगाकर उनके लिए भी मंगलकामना की। उन्होंने गोवंश को गुड़ खिलाकर उनकी सेवा की। गोशाला में मुख्यमंत्री ने माथा व गर्दन सहलाकर गोवंश को खूब दुलार भी किया। शुक्रवार सुबह अपनी दिनचर्या के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए भीम सरोवर के पास पहुंचे। यहां उन्होंने सरोवर किनारे टहल रहे बतखों को दाना खिलाया। उधर गोशाला भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने वहीं पास में विचरण कर रहे एक मोर को भी दाना खिलाया।

प्रदेश के हर ग्राम पंचायतों में बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र

● गांव-गांव आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण कर बच्चों का भविष्य संवार रही योगी सरकार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मनरेगा योजना के तहत बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग और पंचायती राज विभाग के अभिषरण से प्रदेश के गांवों में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह पहल राज्य में कुपोषण को दूर करने, महिला एवं बाल विकास को सशक्त बनाने और ग्रामीण स्तर पर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रदेश सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है ।ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण से न केवल बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित हो रही है, बल्कि यह महिला सशक्तीकरण को भी बढ़ावा दे रहा है। गांवों में गुणवत्तापूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कर बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 से अब तक मनरेगा योजना के तहत 19,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है।

सरकार की प्रतिबद्धता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 3,020 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 9,448 केंद्र निर्माणाधीन हैं। योगी सरकार के इस पहल से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पोषण और शिक्षा को बढ़ावा मिला है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। निर्माण कार्यों में श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में सरकार ने गुणवत्ता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र नेशनल हाईवे के किनारे न बने, जिससे बच्चों की सुरक्षा बनी रहे।

अब ऑनलाइन होगी बिजली लोड वृद्धि की प्रक्रिया

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

योगी सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब बिजली लोड बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए नई प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे उपभोक्ता बिना बिजली दफ्तर गए ही अपना लोड बढ़ा सकेंगे। प्रदेश के उपभोक्ता यूपीपीसीएल की वेबवसाइट पर जाकर 'लोड परिवर्तन अनुरोध' के लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि योगी सरकार पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस डिजिटल प्रक्रिया से उपभोक्ताओं को तेजी, सुचिता और समयबद्ध सेवा मिलेगी। योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। अब उन्हें बिजली विभाग के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वे आसानी से अपना लोड बढ़ा सकेंगे।

मायावती ने केंद्र सरकार से की अविलंब जातिगत जनगणना कराने की मांग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बसपा अध्यक्ष मायावती ने पार्टी संस्थापक कांशीराम की जयंती के मौके पर केंद्र सरकार से मांग की है कि जातिगत जगणना के काम को अविलंब कराना चाहिए।

मायावती ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि बहुजन समाज की आबादी इस समय 80 फीसद से ज्यादा है। जातिगत जनगणना का लगातार लम्बित पड़ा रहना सरकार का गुड गवरनेन्स तो क्या गवरनेन्स भी नहीं है। देश के विकास को नई सही दिशा और गति देने के जातीय जनगणना के भी महत्व से कोई इंकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसके प्रति अपेक्षित गंभीरता निभाने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। जनगणना नहीं कराने पर संसदीय समिति ने भी अपनी चिन्ता व्यक्त की है। मायावती ने बहुजन समाज से आह्वान किया कि वह सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेने का संकल्प ले। उन्होंने अपनी चार बार की सरकार के काम को याद दिलाते हुए कहा कि यूपी के लोगों ने सभी विरोधी पार्टियों को बार-बार परख कर देख लिया है और वे लोग मेरी सरकार द्वारा विशेषकर जनहित व जनकल्याण के मामले में किए गए ऐतिहासिक कार्यों तथा अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामलों में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का बेहतरीन राज से तुलना कर सकते हैं। बसपा कहने में कम और करने में ज्यादा विश्वास करती है जबकि दूसरी पार्टियाँ केवल हवा हवाई बातों, लुभावनी घोषणाओं व दावों के साथ-साथ 'अच्छे दिन' आदि के हसीन सपनों के माध्यम से वरगलाने में ही जनता को उलझाए रखना चाहती हैं। मायावती ने कहा कि देश में चल रहे घातक विवादों की असली जड़ देश में हर जगह हर स्तर पर हावी हो रही संकीर्ण जातिवादी व साम्प्रदायिक द्वेषपूर्ण राजनीति की तीव्रता है, जबकि जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि की राष्ट्रीय समस्याओं को पूरे तौर पर भुला दिया गया है।

वर्तमान खरीफ क्रय वर्ष में 57.70 लाख मीट्रिक टन हुई धान खरीद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अन्नदाता किसानों को योगी का साथ पसंद है। किसानों के साथ की बदौलत योगी सरकार ने धान खरीद में अपना पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले वर्ष की अपेक्षा खरीफ क्रय वर्ष 2024-25 में 3.90 लाख मीट्रिक टन अधिक धान की खरीद हुई। पिछले वर्ष 53.80 लाख मीट्रिक टन धान खरीद हुई थी, जबकि इस वर्ष यह बढ़कर 57.70 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गई। वहीं योगी सरकार ने 99 फीसदी से अधिक किसानों को भुगतान भी कर दिया। यह आंकड़ा 13326 करोड़ से अधिक का है। धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये व ग्रेड ए का 2320 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया था। गत वर्ष से इस वर्ष किसानों को 117 रुपये प्रति कुंतल अधिक एमएसपी दिया गया। वर्ष 2024-25 के लिए धान की बेतहाशा खरीद की गई। आठ लाख किसानों से 5770671.09 मीट्रिक धान की खरीद हो चुकी है। पिछले वर्ष (2023-24) तक इस अवधि तक 5380032.83 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी।

उपमुख्यमंत्री समेत भाजपा नेताओं ने खेली फूलों की होली, लगाया गुलाल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता नीरज सिंह द्वारा होली के अवसर पर विभूति खंड गोमती नगर आवास के सामने स्थित ग्राउंड में रंगारंग होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर योगी सरकार में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता गण, जनप्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में प्रबुद्ध जन और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए।

मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि होली समागम कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, प्रदेश महामंत्री संजय राय, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, एमएलसी मुकेश शमा एमहापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक डॉ नीरज बोरा, एम एल सी रामचंद्र प्रधान, पवन सिंह चौहान, अवनीश पटेल, मुख्यमंत्री गृह सचिव संजय प्रसाद, सलाहकार अवनीश अवस्थी, सचिव आरके सिंह, सीएमओ एन बी सिंह सहित व्यापारी नेता, पार्टी पदाधिकारी, पार्षद गण, मंडल अध्यक्ष व हजारो की संख्या में कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस मौके पर नीरज सिंह ने मुख्य अतिथियों का गुलाल लगाकर और रंगारंग अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और गले मिलकर होली की बधाई शुभकामनाएं दी। एक ओर मंच पर कलाकारों द्वारा होली के गीत और भजनों की प्रस्तुति चल रही थी जिस पर उपस्थित लोग भी थिरके और जमकर गुलाल उड़ाया गया। कार्यक्रम के दौरान फूलों की होली भी खेली गई।

नीरज सिंह ने उपस्थित सभी लोगों पर फूलों की वर्षा की। कार्यक्रम के साथ ही सभी ने गुजिया, ठंडाई और चाट का लुफ्त उठाया।

विकसित भारत के संकल्प की पूर्णता में सभी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें: भूपेन्द्र सिंह

लखनऊ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी एवं प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने प्रदेशवासियों को होलिकोत्सव की अनंत शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सभी अपने राष्ट्रीय व सामाजिक दायित्वों के साथ विकसित भारत के संकल्प की पूर्णता में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने होलिकोत्सव पर्व पर शुभकामना संदेश में कहा कि होली का उत्सव हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए विश्वबन्धुत्व का संदेश देता है। होलिकोत्सव असत्य, अधर्म, अन्याय, अत्याचार व आसुरी शक्तियों के दहन और शास्वत सत्य के अमरत्व के संदेश साथ सप्तरंगी उल्लास का महापर्व है।

अयोध्या और कोरिया के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संबंध सदियों पुराने: जयवीर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

दक्षिण कोरिया के गारक राजवंश के प्रतिनिधि सहित 80 सदस्यीय शिष्टमंडल 13 मार्च को अयोध्या पहुंचा। कोरिया राजवंश के लोग अयोध्या स्थित क्वीन हो मेमोरियल पार्क पहुंचकर पूर्वजों को श्रद्धासुमन अर्पित किया। यह यात्रा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगा।

दक्षिण कोरिया की प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार, करीब 2,000 वर्ष पूर्व अयोध्या की राजकुमारी सुरीरत्ना ने कोरिया के राजा किम सुरो से विवाह किया था। गया राजवंश की संस्थापक राजा से शादी के बाद राजकुमारी सुरीरत्ना रानी हियो ह्वांग-ओक के नाम से जानी गईं। हियो ह्वांग-ओक को गारक राजवंश की संस्थापक माना जाता है। दक्षिण कोरिया के लोग अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं और साल में एक बार अयोध्या जरूर आते हैं। इस ऐतिहासिक संबंध के प्रतीक के रूप में अयोध्या में रानी हो का एक स्मारक पार्क भी स्थापित किया गया है, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करता है। दक्षिण कोरिया के गारक राजवंश के प्रतिनिधि सहित 80 सदस्यीय शिष्टमंडल 11 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचा। 12 मार्च को दल वाराणसी के लिए रवाना हुआ। कोरिया से आए आगंतुक 13 मार्च को अयोध्या पहुंचे। यहां राम मंदिर, क्वीन हो स्मारक सहित अन्य पावन स्थलों का दर्शन-भ्रमण भ्रमण किया। शाम को सरयू आरती में शामिल होने के बाद लेजर शो का आनंद लिया। रात में दक्षिण कोरिया के सदस्यों ने तय कार्यक्रम के अनुसार कुछ लोगों से मुलाकात की। मेहमानों के लिए आठ कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। गौरतलब है कि, दक्षिण कोरिया राजवंश की यह 72वीं पीढ़ी है। राजवंश के सदस्य हर दौर में अपने जड़ से लगाव को प्रदर्शित करते रहे हैं।

सनातन से उनका जुड़ाव सदियों पुराना है। यही वजह है कि अयोध्या उन्हें आकर्षित करता है। अपनी पांच दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधिमंडल आगरा में भ्रमण के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दक्षिण कोरिया के गारक राजवंश के सदस्यों की आत्मीयता और पूर्वजों के प्रति समर्पण जगजाहिर है। उनकी सनातन के प्रति आस्था का हम सम्मान करते हैं।